हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

16/03/2016/1100/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः2925

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल आनी के अंतर्गत मु0 44 करोड़ 88 लाख 32 हजार रुपये की कुल आठ डी0पी0आर्ज0 तैयार हो गई हैं जिनमें से पांच डी0पी0आर्ज0 नाबार्ड व भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी गई है जिनका ब्योरा प्रपत्र "क" पर दिया गया है। इसी तरह से उठाऊ पेयजल योजना शिल्ही च्वाई जिला कुल्लू के आनी ब्लॉक का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 को 2 करोड़ 43 लाख 9 हजार रुपये की दी गई है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 में स्वीकृत हुई थी तथा इसका शिलान्यास श्री रविन्द्र सिंह जोकि तत्कालीन सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री थे, द्वारा 11 फरवरी, 2012 को किया गया था। विभिन्न वर्षों में स्वीकृत बजट के अनुसार सामान्यतः अन्य कार्य भी किए गए। अभी तक कुल योग हमारा 143.68 करोड़ रुपये खर्च हुआ है । इसके अलावा उठाऊ पेयजल योजना निशानी आदि बहुत सारे लम्बे नाम हैं। यदि मैं सभी का नाम पढ़ने लगूंगी तो बहुत लम्बा समय लग जाएगा। इसी तरह से ग्राम पंचायत फनाली डिगीधार आनी ब्लॉक जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति 3 फरवरी, 2012 को 1 करोड़ 17 लाख 39 हजार रुपये दी गई है। इस तरह से आपको काफी लम्बा जवाब मैंने दे दिया है और जो आपकी योजनाएं लम्बित हैं उनके बारे में भी मैंने आपको पूरा जवाब दे दिया है।

श्री खूब रामः अध्यक्ष जी, मंत्री महोदया ने वैसे तो विस्तृत जानकारी दे दी है लेकिन मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आठ डी0पी0आर्ज0 तैयार हो गई हैं उनके से केवल मात्र 5 डी0पी0आर्ज0 को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। बाकी डी0पी0आर्ज0 की स्वीकृतियां नाबार्ड से कब तक आ जाएंगी? दूसरे, 1 जनवरी, 2012 को जो शिलान्यास हुआ है वह स्कीम भी अभी तक अधूरी है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि क्या इसके लिए पर्याप्त धन देंगे ताकि लोगों को पर्याप्त पानी मिल जाए? इसके अलावा, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे

16/03/2016/1100/MS/AG/2

आनी चुनाव क्षेत्र में पानी की बहुत कमी आ रही है। हमारे पास वहां पर कोई जे0ई0 भी नहीं है। तो कब तक वहां पर जे0ई0 को भेज दिया जाएगा ताकि ये सारी डी0पी0आर्ज0 तैयार हो जाए?

अध्यक्षः वैसे इसके साथ यह प्रश्न ताल्लुक नहीं रखता। अगर मंत्री जी जवाब देना चाहती हैं तो दे सकती हैं।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसको मैं समझ गई हूं कि आपके क्षेत्र में जे0ई0 नहीं है और अन्य भी समस्याएं हैं। आपको समय पर समस्या को हमें बताना चाहिए। अगर आप उसी वक्त हमें बताते तो हम उसी वक्त कुछ-न-कुछ इंतजाम कर सकते थे परन्तु फिर भी जो आपके क्षेत्र में कमियां हैं उनको हम जरूर दूर करेंगे। कहीं भी कमियां नहीं रहनी चाहिए।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, मंत्री महोदया ने उत्तर में कहा कि भारत सरकार को ये योजनाएं भेजी गई हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सत्य क्या है? जो सूचना आपने सभा पटल पर रखी, उसके अनुसार एक योजना अभी तक नाबार्ड द्वारा एप्रूव्ड है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

16.03.2016/1105/जेएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 2925ः-----जारी-----

श्री महेश्वर सिंहः-------जारी-----

तीन नाबार्ड को भेजी गई है, अभी वे विचाराधीन है और एक भेजी जा रही है। इसके अन्तर्गत दो योजनाएं अभी डिविज़न में पड़ी हुई है और चीफ इंजीनियर ने उसमें ऑब्जर्वेशन्ज लगाई हैं। माननीय मंत्री जी ने कैसे कहा कि आठ भेजी है?

दूसरे, ख-भाग के उत्तर में उठाऊ पेयजल योजना शिलान्यास बगैरह पर आपने बड़े विस्तार से कहा कि वर्ष 2012 में हो गया। दूसरी योजना टोगी वाली 1.9.2012 में शुरू हो गई। प्रश्नकर्त्ता ने यह पूछा है कि काम शुरू हुआ तो बन्द होने के क्या कारण है ? आप तो कह रहीं है कि यह काम शुरू हो गए हैं। अगर ये काम शुरू हो गए हैं, बन्द नहीं हुए तो इन दोनों कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? जब वर्ष 2012 में काम शुरू हुए तो चार वर्षों में पूर्ण न होने के पीछे क्या-क्या कारण है?

Speaker: Hon'ble Minister, if you have got some information please reply.

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यहां पर जो बात कही, मैंने पहले ही कह दिया है कि गत वर्षों के दौरान सिंचाई एवं जन- स्वास्थ्य मंडल के अन्तर्गत 44 करोड़ 88 लाख 32 हजार रूपए की कुल 8 डी0पी0आर0 तैयार हो गई है। मैं यहां पर सारे का सारा हिसाब-किताब दे रही हूं और माननीय सदस्य को यहां पर गलत सूचना नहीं दे रही हूं। उसी के साथ 5 डी0पी0आर0 भारत सरकार व नाबार्ड की स्वीकृति हेतु भेजी गई है। जिनका ब्योरा प्रपत्र-क में दिया है। उसके साथ ही उठाऊ पेयजल योजना शिल्ही च्वाई, आनी ब्लॉक, जिला कुल्लू का पूरा प्रशासनिक अनुमोदन आय-व्यय की स्वीकृति देना 5.12.2011 को मुख्य दो करोड़,-----व्यवधान--- नहीं-नहीं जो आपने कहा कि पैसा है ही नहीं, हमारे पास तो जो आपका सवाल है, उसके बारे में हम बता रहे हैं।

16.03.2016/1105/जेएस/एएस/2

श्री महेश्वर सिंहः माननीय मंत्री जी, मैं पूछ रहा हूं कि जब 2012 में उन स्कीमों का काम चल पड़ा तो बन्द क्यों हुआ? आपका कथन है कि वह काम शुरू है। तो इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ? वर्ष 2012 से शुरू है, बजट प्रावधान हुआ है तो इस विलम्ब के क्या कारण है?

सिंचाई एवं जन-स्वरस्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है कि मैं माननीय सदस्य के

खिलाफ हूं। हम सच्ची बात कह रहे हैं। लगभग अभी तक 143.68 लाख रूपये खर्च हो चुका है। ऐसा नहीं है कि एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। हमने 143.68 लाख रूपया अभी खर्च भी कर लिया है। हमने सब चीजों के लिए खर्च किया भी है और अभी और कुछ धनराशि आएगी तो उसके बाद भी खर्च होगा। धन्यवाद।

16.03.2016/1105/जेएस/एएस/3

प्रश्न संख्याः 2926

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यहां पर विस्तृत रूप से उत्तर दिया है, लेकिन अनैक्चर-बी में जो पशुओं की बीमारियां दर्शाई गई हैं, उनमें से जो Anthrax है और जब कभी यह बीमारी बढ़ती है और उससे पशुधन का नुकसान होता है, लगातार मौतें होती है तो जब विभाग को रिलीफ के लिए हम केसिज भेजते हैं तो वे कहते हैं कि इस बीमारी को रिलीफ मैनुअल में कवर नहीं किया गया है। मैं, माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि इस बारे में विभाग को स्पष्ट आदेश दिए जाएं और एस0डी0एम0 तथा तहसीलदार ऑफिसिज़ में आदेश दिए जाएं कि इस अनैक्चर-बी में जितनी भी बीमारियां कवर की गई है इनको रिलीफ दिया जाए। इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां जैसे कि हाऊस फायर होती है, कैटल शैड में फायर लग जाती है और पशु जल जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरे, स्नेक बाईट, जहरीली घास खाने से भी बरसात के दिनों में पशुओं की मौतें हो जाती है। मैं, माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि ये जो भी बीमारियां हैं क्या इनको भी रिलीफ मैनुअल में कवर किया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वैसे जानकारी विस्तृत तौर पर दी गई है और किन-किन बीमारियों को हम डिजास्टर मैनेजमैंट और रेवन्यू मैनुअल के अन्तर्गत लेते हैं। सभी किस्म के जो पालतू ज़ानवर है उनके बारे में यहां पर कहा गया है। जहां तक इन्होंने कहा कि आग जलने से अगर कोई पशु मरते हैं That is an

accidental case और उसको भी तहसीलदार पैसे देता है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

16.03.2016/1110/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 2926 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

इसके बाद जो स्नेक वाइट की बात है या ये जो भी बीमारी होती है उसमें फेक सर्टिफिकेट न मिलें इसके लिए हमने कहा है कि अगर कोई पशु मरता है और विशेष रूप से इन बीमारियों से मरता है तो उसमें या तो वैटरिनरी डॉक्टर पोस्टमार्टम करें या वहां पर जो स्थानीय फार्मासिस्ट है, every veterinary dispensary has a veterinary pharmacist, वह फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट देगा। उसके आधार पर जो हमने पैसा निर्धारित किया है उसके मुताबिक उनको पैसा दिया जाता है। इसी तरह से जानवरों को जो बीमारी होती है वह उसी सूरत में होती है जैसे कोई एपेडैमिक हो जाए। जैसे कई बार गद्दियों की इकट्ठी भेड़ें मर जाती हैं। कई बार पॉल्ट्रीफार्म के पॉल्ट्रीफार्म खाली हो जाते हैं उसके अन्तर्गत पशुपालन विभाग आता है। इसलिए उन्हीं बीमारियों को जिनका हम इलाज करते हैं उनके अलावा जिसमें ज्यादा पशु मरते हैं उन बीमारियों को भी हमने इसमें कवर किया है।

डॉ0 राजीव बिंदलः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बीमारियों का ज़िक्र किया। जो अननैचुरल डैथ के अंदर बाकी चीज़ें हैं उसमें आगज़नी के बारे में भी आपने उत्तर दिया। मैं स्पैसिफिक इंस्टांस कोट करूंगा। पिछले सप्ताह आसमानी बिजली गिरने से गांव खरकिओं में फरीदखान के ऊंट की डैथ हुई। आसमानी बिजली गिरने से जो इस प्रकार की मृत्यु है उसको आप किस कैटेगिरी में कैसे कवर करेंगे, इसके बारे में बताएं। यह स्पैसिफिक गांव खरकिओं, ब्लॉक नाहन जो मैंने बताया है इसको आप किस प्रकार से कवर करेंगे? इसके लिए हम आश्वासन चाहते हैं।

Health And Family Welfare Minister: Mr. Speaker Sir, I have given detailed reply but he has put a specific question regarding thunder. आसमानी बिजली

गिरने से जो पशु मरते हैं वह भी एक एक्सीडैंट है। That is also unnatural death, जितनी भी अननैचुरल डैथ हैं those are covered under the Relief Manual. हम उनको भी रिलीफ देते हैं।

16.03.2016/1110/SS-DC/2

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने जवाब दिया, उसमें बीमारी के कारण डैथ का ज़िक्र किया। यह बात ठीक है। नुकसान तो नुकसान है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जैसे मेरे चुनाव क्षेत्र में एक जगह तेंदुए ने 25 बकरियां मार दीं। मेरे ताया के परिवार में 10 बकरियां मार कर तेंदुए ने ढेर लगा दिया। वे सारी फॉर्मैलिटीज़ जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं वे पूरी की गईं। वैटरिनरी डॉक्टर बुलाया गया। पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी जिस राहत मैनुअल की मंत्री जी बात कर रहे हैं कि इसके तहत पैसा देते हैं उसके हिसाब से 300 रुपये प्रति बकरी के हिसाब से देने लगे। उन्होंने उस पैसे को लेने से मना कर दिया।

अध्यक्षः ऐसा है मैनुअल में जो प्रावधान होगा, उसी के मुताबिक दिया जायेगा।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि नुकसान तो नुकसान है चाहे वह तेंदुए की वजह से हुआ है या चाहे बिजली के गिरने से हुआ है या चाहे बीमारी के कारण से हुआ है। जिन पशुओं की मौत हुई क्या उसके लिए आप एक जैसे मुआवजे का प्रावधान करेंगे? क्या इस प्रकार से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, जितना पैसा उनको मिलना है उससे कई गुणा ज्यादा उनका नुकसान हुआ है तो उसके लिए कोई ठोस नीति बनाकर आप उनको राहत देने की कोशिश करेंगे?

Speaker: It is a different question but you can reply, if you like.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः सर, इनफैक्ट जो ठाकुर जय राम जी ने कहा है कि तेंदुए ने भेड़ें या बकरियां खाई हैं। उसमें जो हमारे वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर्ज़ होते हैं, वे उसे देखते हैं। फॉरैस्ट डिपार्टमैंट उसकी भरपाई करता है। वह भी सिर्फ एक लिमिटिड हद तक करता है। इस प्रकार फॉरैस्ट डिपार्टमैंट के तहत वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमैंट है उसकी भरपाई देता है और यह हमारे लैंड मैनुअल में कवर नहीं होता।

Speaker: He means to enhance the compensation.

16.03.2016/1110/SS-DC/3

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, एक जगह ये 3 हजार रुपया दे रहे हैं। जो रिप्लाई दिया है उसके मुताबिक भेड़ या बकरी की बीमारी के कारण मौत होने पर 3 हजार रुपया देते हैं और दूसरी जगह अगर किसी बकरी को तेंदुए ने मार दिया या बिजली गिरने से मौत हो गई तो उसके लिए सिर्फ 300 रुपया दे रहे हैं, यह बहुत मिस-मैच कर रहा है। क्या सरकार इस पर विचार करने की कोशिश करेगी? कम-से-कम आप इसे एक बराबर तो करें।

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2016/1115/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 2926 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः Sir, of course, causality is causality. If leopard has killed so many sheep and goats, then it is covered under Forest department, but हमारा तो unnatural death due to diseases है, उसमें यह हमारे मैनुअल में कवर होता है लेकिन फिर भी जो इन्होंने सुझाव दिया है, he has given good suggestion for action.

16.03.2016/1115/केएस/डीसी/2

प्रश्न संख्याः 2927

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है, यह सूचना पांचवी बार इस विधान सभा के पटल पर रखी गई है। जब पहली बार यह सूचना सभा पटल पर रखी गई थी, उस समय भी मंत्री महोदय ने पूरा आश्वासन दिया था कि आपकी जो योजनाएं हैं, मेरे चुनाव क्षेत्र में 18 सिंचाई की योजना है, एक पूर्ण हो चुकी है वर्ष 1980 से पहले और वर्ष 2003 से आज तक यानि वर्ष वर्ष 2003 से जो सिंचाई की

और पीने के पानी की योजनाएं शुरू हुई थी, आज तक कम्पलीट नहीं हुई है। वर्ष 2013 में भी माननीय मंत्री महोदया ने आश्वासन दिया था, उसके बाद इनके चैम्बर में एक मीटिंग भी हुई और उसमें भी सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया था लेकिन आज तक मेरे चुनाव क्षेत्र की 17 उठाऊ पेयजल योजनाएं, 4 सिंचाई योजनाएं नेरवा डिविज़न की है और 4 सैंज सब डिविजन की उठाऊ पेयजल योजनाएं हैं और तीन सिंचाई योजनाएं हैं। ये आज तक पूर्ण नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदया जी से आश्वासन चाहता हूं कि ये योजनाएं कब तक पूर्ण होगी? जो 2003 में शुरू हुई थी न स्पॉट पर उसका टैंक है न पाइपें हैं और बहुत सारी दिक्कतों से हमारे चुनाव क्षेत्र की जनता जूझ रही है?

Speaker:- Please be brief.

I&PH Minister: Sir, 21 lift water supply schemes, 7 lift water irrigation schemes and 106 gravity water schemes are under execution in Chopal constituency . The details of ongoing schemes under IPH Division Nerwa and IPH Sub- Division Sainj are as under; in Nerwa division, 17 water supply schemes , 4 lift irrigation schemes and 106 gravity water schemes. Similarly in Sainj Sub-division , there are 4 lift water supply schemes and 3 irrigation scheme. The total is 21 lift water supply scheme , 7 lift irrigation schemes and 106 are gravity water supply schemes. None of the above schemes are completed yet.

16.03.2016/1115/केएस/डीसी/3

The details of all these schemes along with scheme wise requirements of funds for its completion is mentioned in 'Annexure-क', आप समझ सकते हैं कि आपके चुनाव क्षेत्र में इतनी तेजी से इतनी स्कीमें आई। हम मानते हैं कि हम उनको सम्भाल नहीं सके लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपके खिलाफ कुछ कर रहे हैं । काम तो हमें सभी का करना है। प्रत्येक को अपनी-अपनी स्कीमें बनानी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है I So anyway none of the above scheme is completed, I agree to that. The name of all the contractors to whom the works has been

awarded, the sanction amount and the action taken against the defaulting contractors is given in 'Annexure 4'. बीच में डिफॉल्टर्ज़ भी आ गए, आपको सब कुछ मालूम है । मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि 17 लाख का बजट है । हम अपने धन से ही कर रहे हैं। जितना फंड आएगा, उसके हिसाब से ये कार्य होंगें। आपने बहुत बड़ी स्कीमें भेजी थी, ज्यादा भेजी थी और उन सबको एकदम से तैयार करना सम्भव नहीं होता ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा---

16.3.2016/1120/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 2927------------- क्रमागत

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ------ जारी

आप एम0एल0ए0 फंड से भी कुछ कंट्रिब्यूट कर दीजिए, आपको उसका भी फायदा हो जायेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे-जैसे भारत सरकार से फंड मिलेगा उसके हिसाब से आगे पैसा दिया जायेगा और हम तेज गति से काम करेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधान सभा में यह जवाब पांच बार सुन चुका हूं और यह छठी बार है। हिमाचल प्रदेश के हर निर्वाचन क्षेत्र में जहां पर भी उठाऊ पेयजल योजना का काम होता है वह 4-5 वर्षों में पूरा हो जाता है। मेरे यहां वर्ष 2003 में योजना का काम शुरू हुआ था मगर वह आज तक पूरा नहीं हुआ। मेरे चुनाव क्षेत्र में पानी की बहुत दिक्कत है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है और मैं इस कारण से अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा सकता। यह आश्वासन मुझे पहले कई बार मिल चुका है कि 6 महीने के अंदर पूरी हो जायेगी, साल के अंदर हो जायेगी। मेरी ग्रेविटी की 106 स्कीमों में पैसे का प्रावधान नहीं है जबकि मंत्री जी ने पहले आश्वासन दिया था कि पैसे का प्रावधान हो जायेगा। वर्ष 2013, 2014 और 2015 चला गया, अब वर्ष 2016 चला है। अब वर्ष 2016 में यह कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे का प्रावधान नहीं है। अगर पैसे का प्रावधान नहीं था तो इन स्कीमों के टैंडर क्यों लगाये गये? अगर लगाये ही थे तो सबसे पहले पैसों का इंतजाम करना चाहिए था। इन स्कीमों में आधे काम हो चुके हैं। पानी की

आधी पाइपें बिछ चुकी है, पानी के बहुत सारे टैंक बन चुके हैं। मैंने वर्ष 2014 में प्रश्न लगाया था कि जो लिफ्ट और ग्रेविटी के 200 पानी के टैंक बने हैं उनमें से 198 तो फटे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह आश्वासन दे कि अभी गर्मी से पहले या 4-5 महीने में मेरी कुछ ग्रेविटी की स्कीमें तैयार हो जायेगी।

16.3.2016/1120/av/ag/2

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से मण्डल नेरवा की बात कर रही हूं। वहां पर 17 उठाऊ पेयजल योजनाओं, 4 सिंचाई योजनाओं, 106 ग्रेविटी पेयजल योजनाओं तथा उप मण्डल सैंज की 4 उठाऊ पेयजल योजनाओं तथा 3 सिंचाई योजनाओं का कार्य चल रहा है। सारे काम चल रहे हैं, इसमें कोई जादू से तो काम नहीं होते। आपकी केवल एक ही स्कीम नहीं है, आपकी इतनी सारी स्कीमें चली हुई है। आपको धन भी चाहिए, काम भी चाहिए। अब हम कोई जादू तो कर नहीं सकते। मैंने आपको नेरवा की इतनी स्कीमों के बारे में बता दिया है। उसके बाद प्रश्न के 'ख' भाग में मैंने बताया है कि इनमें से कोई भी योजना पूर्ण नहीं हुई है तथा इनके लिए आवश्यक धनराशि का विवरण प्रपत्र 'क' पर दिया गया है। (---व्यवधान---) मैं आपको सच्चाई बता रही हूं और यह कोई बूरी बात नहीं है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूं, जो विभाग की मज़बूरी है वह बता रही हूं। आपने पहले भी मेरे से इस बारे में कई बार बात की है और मैंने कहा है कि जैसे-जैसे हमारे पास फंड और स्टाफ का इंतजाम होगा उसके हिसाब से काम होगा। कोई जादू का काम तो है नहीं कि आपकी आठ स्कीमें इकट्ठी बन जाए, यह तो सम्भव नहीं है। विभाग इसके लिए कोशिश कर रहा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी, आप मंत्री जी से इस बारे में अलग से बात कर लेना।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि आपके समय में 200 टैंक्स बने थे जिसमें से 198 डेमेज्ड हैं। वे टैंक क्या विभाग ने बनाए या ठेकेदारों ने बनाए और जिन्होंने डेमेज्ड टैंक बनाए उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करेंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी नहीं है कि कितने टैंक ठीक बने हैं और कितने डेमेज्ड हैं। मगर एम0एल0ए0 साहब को अपने निर्वाचन क्षेत्र में यह पता होता है कि कौन सी स्कीम गलत बन रही है या कौन सी

16.3.2016/1120/av/ag/3

ठीक बन रही है। अगर कहीं कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है तो आप इस बारे में विभाग को सूचित कीजिए। हर जगह पर कितनी ही स्कीम्ज के तहत टैंक्स बन रहे होंगे या कोई दूसरे काम हो रहे होंगे तो विभाग के लिए यह देख पाना मुश्किल है। आप सही कह रहे हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं है।

टीसी द्वारा जारी

16.03.2016/1125/TCV/AG/1

अध्यक्षः आप माननीय मंत्री से अलग मिलें You can contact the Minister separately. No, no. No more question. Please sit down. Next Question.

प्रश्न संख्याः 2928

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है और माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं उससे संतुष्ट हूं लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जहां तक वैकेन्सिज़ की बात है, ये काफी अर्से से खाली पड़ी है। मैं इन वैकेन्सिज़ को जल्दी से जल्दी भरने का माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा। दूसरे, पार्किंग की बहुत दिक्कत आ रही है, इसका कार्य भी मैं शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने का माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि रोहडू नगर परिषद में एग्ज़ेक्यूटिव ऑफिसर का एक पद खाली है और टोटल पद 21 सैंक्शन्ड हैं, उसमें 15 इन-पोजिशन है और 6 पद खाली है। इन 6 पदों में एग्जेक्यूटिव ऑफिसर का पद बहुत जरूरी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 10 एग्जेक्यूटिव ऑफिसर को सभी नगर परिषदों में भरने की स्वीकृति प्रदान की है, जैसे ही ये पद भरे जाएंगे या ट्रांस्फर

के माध्यम से इस पद को भर दिया जाएगा। बाकी नॉन फंक्शनल पद हैं, इनको भी भरने की प्रक्रिया जारी है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोहडू में पार्किंग और कमर्शियल प्रोजैक्ट की बात है, उसके टैण्डर हुए हैं लेकिन टैण्डर में काफी देर हो गई है। उसके लिए 'राजीव गांधी अर्बन रिन्युअल मिशन' के अन्तर्गत कमर्शियल-कम-कार पार्किंग कम्पलैक्स बनना है। उसके लिए 29,86,950/- रूपया पड़ा हुआ है। इसमें जिसने हाईएस्ट बीड दी थी, उसको 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी है, मैं विभाग को कहूंगा कि उसके साथ नेगोशिएशन करके इस पार्किंग और कमर्शियल कम्पलैक्स को जल्दी आवार्ड करें ताकि जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू हो जाये।

16.03.2016/1125/TCV/AG/2

प्रश्न संख्याः 2929

श्री बलदेव सिंह तोमर(प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के 'क' भाग के जवाब में कहा है कि 01-01-2013 से 31-01-2016 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला सिरमौर में 619 मकान स्वीकृत हुए हैं। 31 जनवरी, 2016 तक 746 मामले लम्बित पड़े हैं और इन्होंने 'ख' भाग में पूरा ब्यौरा दिया है,उसमें बहुत सारे मकान 2013, 2014 और 2015 के लम्बित पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये 2013 और 2014 के मामले क्यों लम्बित पड़े हैं, क्या इसमें पिक-एंड-चुज़ का इस्तेमाल किया गया है? ये जो 746 मामले लम्बित पड़े हैं, इनको कब तक मकान मिलेंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पच्छाद क्षेत्र के बारे में पूछा है और यह जो 619 मामले कुल स्वीकृत हुए हैं, ये 396 cases were actually there before 2013 and after 2013, 223 cases were added. मैं जानता हूं कि 746 मामले आपके लम्बित हैं। इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, पहले तो बजट की उपलब्धता और दूसरे बहुत सारे इस प्रकार के पत्र आ जाना जिनको आपकी कमेटी, जिसमें मैंबर ऑफ पार्लियामैंट और हम सभी विधायक भी मौजूद होते हैं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी।

16.03.2016/1130/RKS/AS/1

प्रश्न संख्याः 2929... क्रमागत

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ... जारी

मेरा मानना यह है कि आप सभी लोग इन सारी चीजों को देखते हैं और इसके बारे में सूची तैयार करते हैं। कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें पात्र व्यक्तियों के पास मकान नहीं है, इन मामलों में नैचूरली, he takes priority. कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें आगनजिक या बाढ़ के कारण क्षति पहुंची हो। जहां तक जो 746 मामले लम्बित पड़े हुए हैं, उनकी प्रोसैस चली हुई है। जैस ही वेलफेयर कमेटी द्वारा इन मामलों की सूची बनाई जाती है, जैसे-जैसे बजट उपलब्ध होगा तो we will do it on priority basis.

अध्यक्षः डा0 राजीव बिन्दल।

डा0 राजीव बिन्दलः जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि विधायकों की कमेटी के अंदर इन मामलों का निर्णय होता है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इसके संबंध में वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 इन तीनों वर्षों में सिरमौर जिला के अंदर विधायकों की मीटिंग नहीं हुई है। हमारे बार-बार बोलने के बावजूद भी मीटिंग नहीं हुई है। एक दिन मीटिंग की डेट आई और जब हम लोग मीटिंग में जाने के तैयार हो गए तो टेलीफोन आया कि मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है। जब दूसरी मीटिंग होनी थी तब हम शिमला में थे और वहां से टेलीफोन आया कि आज मीटिंग है। हमने इस बारे में जिलाधीश और कमेटी चेयमैन के समक्ष मामला दर्ज करवाया। लेकिन मेरे, सुरेश कुमार और बलदेव सिंह तोमर जी के सुझाव इसके अंदर नहीं लिए गए। मेरा माननीय मंत्री जी से यह जानना है कि जो बैकलॉग किन्हीं दूसरे लोगों की सिफारिशों पर जारी किए है, क्या उनमें हमारे सुझावों को लेकर बैकलॉग में इनकॉर्पोरेट करके कम्पनसेट करेंगे? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं?

16.03.2016/1130/RKS/AS/2

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जी ने ऑब्जर्बेशन दी है, उसमें सरकार की ओर से जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी बनाई गई है उसमें सभी का होना अनिवार्य है। सभी का इन्टरवेंशन या सुझाव लेना भी अनिवार्य है। यदि इस प्रकार का कोई आपका सुझाव है तो उसमें आपको आश्वस्त किया जाएगा कि आप सब लोगों के सुझाव लिए जाएंगे और आगे के लम्बित मामलों का निपटारा भी किया जाएगा।

जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मकान देने की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया क्या है? क्या यह सत्य है कि वेलफेयर कमेटी में पहले सरकार ने यह निर्णय कर लिया था कि इसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होगा। बाद में जब विधायकों ने कहा कि पहली प्रक्रिया को जारी रखिए और कहा कि वरिष्ठ मंत्री इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। वरिष्ठ मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने के बाद जिला की जिस कमेटी का आपने जिक्र किया कि इस कमेटी को यह पावर है, यह स्वीकृत करती है, यह निर्णय करती है कि मकान किसको देना है? हम विधायक होने के नाते उस बैठक में वहां उपस्थित थे। विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र की जानकारी जितनी मुझे है उतनी किसी दूसरे आदमी को नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से जिला वेलफेयर कमेटी को आपने निर्णय करने की, स्वीकृत करने की पावर दे रखी है, उसके बावजूद जो नाम हमने दिए उससे हटकर निर्णय हुए। मकान देने के लिए कोई पात्रता नहीं देखी गई। क्या आप पूरे प्रदेश भर में इस बात के ऊपर आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिला वेलफेयर कमेटी में जो माननीय विधायक है,

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी

16.03.2016/1135/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 2929...जारी

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

जो अपने क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, उनका निर्णय अंतिम होगा। क्या आप इस प्रकार का आदेश देंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो कहना है, मैं समझता हूं कि it calls for a little bit of your conscious searching also **जब पूरी डिस्ट्रिक्ट वैलफेयर कमेटी एक साथ बैठी होती है, आप सब लोग उसमें मौजूद रहते हैं और वह स्वयं ही यह सब निर्धारित करती है। उसमें मैरिट बेसिज पर होना चाहिए और जिस व्यक्ति के लिए मकान बनाने की ज्यादा आवश्यकता है, उसी का नाम इसमें आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन को भी इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि जो विधायकों के सुझाव होंगे उन पर पूरी तरह से गौर की जाएगी, जो करनी भी चाहिए। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं।**

16.03.2016/1135/SLS-AS-2

प्रश्न संख्या : 2930

श्री इन्द्र सिंह : मानीय अध्यक्ष जी, सरकाघाट शहर में पार्किंग की समस्या बहुत गंभीर है और यह मामला बहुत सालों से लटका हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां अब दूसरी बार शिलान्यास रखा गया है, क्या वह भूमि जंगलात की है या शामलात है। अगर वह फोरैस्ट लैंड है तो, जैसा कि लिखित उत्तर में कहा गया है कि उसको NAC सरकाघाट तैयार कर रही है, मैं जानना चाहता हूं कि वहां उसे कौन तैयार कर रहा है? एक साल से वहां पर न तो जे.ई. है न सैक्रेटरी है। इसलिए यह झूठा उत्तर क्यों दिया जा रहा है? साथ ही, जो 2.39 करोड़ रुपये का ऐस्टिमेट दर्शाया गया है, वह पहले शिलान्यास की जगह का है या दूसरे शिलान्यास की जगह का है? इसमें कितना पैसा डिपोजिट में पड़ा है और कब से पड़ा है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (अधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, सरकाघाट में पार्किंग की समस्या निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है। वह काफी बड़ा शहर है और आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण काफी लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। उसको ध्यान में रखते हुए कार पार्किंग का जो 2.39 करोड़ रुपये का ऐस्टिमेट बना था उसके बदले में 80.00

लाख रुपये सरकार की ओर से हिमुडा को जारी हो गया है। जो पहले साईट सलैक्ट की थी उसमें लोक निर्माण विभाग से NOC लेना था। इस समय एक्जीक्युटिव इंजीनियर का चार्ज तहसीलदार के पास है। एक्जीक्युटिव इंजीनियर, नेशनल हाई-वे हमीरपुर को उन्होंने NOC के लिए पत्र भेजा है। लेकिन जिस स्थान पर पहली कार पार्किंग का शिलान्यास हुआ था वहां 5 मीटर ज़मीन नेशनल हाई-वे में आ रही है। इसलिए इस साईट को बदलना ज़रूरी समझा गया और इससे 150 मीटर आगे अब नए साईट को चुना गया है। इस साईट की कुल ज़मीन 01031 हैक्टेयर है। यह चरागाह दरख्तान है। इसका फोरैस्ट केस प्रोसैस हो रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि **सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इसको FCA के तहत जल्दी-से-जल्दी अनुमति मिले और इस कार पार्किंग का कार्य विधिवत तौर पर शुरू हो जाए।**

16.03.2016/**1135**/SLS-AS-**3**

श्री इन्द्र सिंह : सर, मैं पूछना चाहता हूं कि FCA का केस कौन बना रहा है जबकि वहां पर कोई भी अधिकारी बनाने वाला नहीं है? इस एक्शन को इनिशियेट कौन कर रहा है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : तहसीलदार सरकाघाट के पास एक्जीक्युटिव इंजीनियर का चार्ज है, वह इस केस को बना रहे हैं और जे.ई. तथा दूसरे स्टॉफ ने सारा केस तैयार कर दिया है। अब अप्रूवल के लिए यह केस शीघ्रातिशीघ्र भेज दिया जाएगा। मैंने आपको आश्वासन दिया है कि हमारी कोशिश होगी कि जल्दी-से-जल्दी इस कार पार्किंग का काम शुरू हो जाए।

अगला प्रश्न...श्री गर्ग जी

16/03/2016/1140/RG/DC/1

प्रश्न सं. 2931

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन सालों से लगातार यह जवाब यहां आ रहा है कि तीन मैडिकल कॉलेज यहां खोले जा रहे हैं और अब तो भारत

सरकार ने इसमें धन का प्रावधान भी कर दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि धरातल पर इनकी वस्तुस्थिति क्या है? कुछ हो भी रहा है या सिर्फ कागज़ों में ही ये कॉलेज चलते रहेंगे?
अध्यक्ष महोदय, जहां तक 'एम्स' की बात है, तो प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने यह 'एम्स' बिलासपुर के कोठीपुरा में खोलने का जो फैसला लिया है उसकी क्या स्थिति है? क्या जमीन आदि ट्रांसफर हो गई है या नहीं या भारत सरकार से इसको इन्होंने टेक अप किया है या नहीं? ये सारी जानकारी क्या माननीय मंत्री जी सदन में रखेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि जैसा इन्होंने कहा कि तीन साल से इनकी प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2012-13 में ये तीन मैडिकल कॉलेज उस समय की यू.पी.ए. सरकार ने दिए थे। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और मैंने श्री गुलाम नवीं आजाद से अनुरोध किया था। पूरे देश में 58 मैडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए थे और कहा गया कि 300 बिस्तरों के जिलों के जो रीज़नल अस्पताल हैं उनको अटैच करके दस किलोमीटर में मैडिकल कॉलेज और हॉस्टेल की स्थापना की जाए। उसमें जो फण्डिग पैटर्न था उसके अनुसार 90% भारत सरकार और 10% प्रदेश सरकार का हिस्सा इसमें होगा। हरेक मैडिकल कॉलेज के लिए 189 करोड़ रुपये भारत सरकार से मिलना है। इन तीन मैडिकल महाविद्यालय के लिए अभी केन्द्र सरकार ने जैसा उत्तर में बताया गया कि 21.53 करोड़ रुपये हमें दे दिया है। नाहन में हिमाचल के निर्माता डॉ. यशवन्त सिंह परमार के नाम पर मैडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। इस मैडिकल कॉलेज का काम Health Services Construction Company (HSCC) को दिया गया है। वहां सौभाग्य से हमें 21 एकड़ जमीन उपलब्ध हो चुकी है और उस पर काम चल रहा है। 300 बिस्तरों का अस्पताल भी हम करेंगे और मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि इन तीन मैडिकल कॉलेज के लिए हमने प्रोफैसर और टीचिंग स्टाफ की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। इसके अतिरिक्त हमने काफी लोगों को यह ऑफर दी है। कुछ लोगों ने हमारी ऑफर स्वीकार करके ज्वाईन भी कर लिया है, लैक्चरर्ज भी हैं, हमने

16/03/2016/1140/RG/DC/2

असिटैंट प्रोफैसर भी लगाए हैं और एक प्रोफैसर भी लगा दिया गया है, प्रिंसीपल भी उसमें हमने लगा दिया है। इसके अलावा Medical Council of India से हमने इस कॉलेज को अगस्त माह से चालू करने का अनुरोध भी किया है और Medical Council of India के प्रतिनिधियों ने डा. यशवन्त सिंह परमार मैडिकल कॉलेज, नाहन का निरीक्षण कर लिया है। इसके अतिरिक्त चम्बा के मैडिकल कॉलेज का नाम पं. जवाहर लाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। वह चम्बा में खोला जाएगा और चम्बा में भी सौभाग्यवश पशु-पालन विभाग की कुछ जमीन थी वह हमने मैडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग के नाम पर ट्रांसफर कर दी है। कुछ 5-6 एकड़ साथ की ऐडज्वाइनिंग जमीन का भी हमने केस बना दिया है। इस प्रकार चम्बा और नाहन में मैडिकल कॉलेज को चलाने के लिए प्राइवेट अकॉमोडेशन भी मिल चुकी है और वहां हमारे मैडिकल कॉलेज चल सकते हैं। चम्बा में भी राजा के महल में मैडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारी इनको शुरू करने की पूरी कोशिश है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास डॉक्टर्ज की कमी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन दोनों मैडिकल कॉलेज को तो जल्दी शुरू करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि हमीरपुर मैडिकल कॉलेज के पास हमारी अपनी जमीन नहीं थी,

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

16/03/2016/1145/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 2931 क्रमागत-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी-----

उससे 9 किलोमीटर दूर हमने जमीन छांटी है और वह फॉरैस्ट लैण्ड है। उसका केस एफ0सी0ए0 के तहत बनाया जा रहा है। जो एच0एस0सी0सी0 है उन्होंने भी इन्सपैक्शन करके उस जमीन को ठीक पाया है। हमारी कोशिश होगी, कर देंगे। बाकी जहां तक एम्ज का प्रश्न है। यह ठीक है कि पिछले साल के केन्द्र के बजट में एम्ज हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर हुआ था। नड्डा साहब सौभाग्य से हमारे केन्द्र में स्वास्थ्य मंत्री है। उन्होंने भी यह अनुरोध किया कि मैं इसको बिलासपुर में खोलना चाहता हूं। हमने केबिनैट में फैसला किया कि बिलासपुर में ही ये एम्ज खोला जाए। जो कोठीपुरा में

एनिमल हस्बैंड्री की काफी जमीन हमारे पास उपलब्ध थी, उसको केन्द्रीय हैल्थ मिनिस्ट्री के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ जमीन और जो फॉरैस्ट की थी, उसका एफ0सी0ए0 के तहत केस बनाया जा रहा है। उसके साथ ही अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने कहा था कि कंटूर प्लान लोक निर्माण विभाग से बनाकर भेजिए। वह कंटूर प्लान भी हमने भारत सरकार को भेज दिया है। उसमें टोटल 7 लाख 49 हजार रुपये केन्द्र सरकार ने देने थे। अभी केन्द्र सरकार ने वह पैसा भी उपलब्ध नहीं करवाया है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वहां प्रधानमंत्री को लाएं। हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जल्दी आएं और उसका शिलान्यास करें और यह कॉलेज जल्दी शुरू हो जाए।

श्री बी0के0 चौहानः अध्यक्ष जी, यह काफी हर्ष का विषय है कि चम्बा को भी पहली बार किसी ऐसे संस्थान के लिए भारत सरकार द्वारा चुना गया है और लगभग 21 करोड़ रुपये की राशि सभी संस्थानों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पहले जो जमीन इन्होंने चुनी है उसके साथ रिजर्व फॉरैस्ट की जमीन भी इन्क्लूड की है जिसकी अनुमति लेने के लिए काफी समय लगेगा। यह सही कहा कि चम्बा में जहां पहले पी0जी0 कॉलेज था वह अब नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है इसलिए वह स्थल अब उपलब्ध है। इन्होंने निर्णय लिया है कि वहां पर पर्याप्त एकॉमोडेशन है और वहां पर ये जल्दी

16/03/2016/1145/MS/DC/2

उसको खोलेंगे। क्या मैं मंत्री महोदय से इस आश्वासन की अपेक्षा कर सकता हूं कि आने वाले सत्र में यह मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाएगा और वहां कक्षाएं शुरू की जाएंगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कहा कि हम पूरी तरह से

गंभीर हैं कि ये दोनों मेडिकल कॉलेजिज कम-से-कम हम अगस्त में शुरू कर दें लेकिन ये मेडिकल काऊंसिल ऑफ इण्डिया की एप्रूवल पर निर्भर करता है और इसीलिए हमने दोनों मेडिकल कॉलेजिज में जो टीचिंग फैकल्टी के मैम्बर्ज हैं उनकी भी एप्रूवल की है क्योंकि एक दिन श्री भारद्वाज जी ने यह प्रश्न उठाया था कि आप उनको जबरदस्ती भेज रहे हैं। उस दिन चर्चा विस्तृत तौर पर हुई थी। हमने कहा कि उनको ऑप्शन दी है। जो यहां असिस्टैंट प्रोफेसर है उसको हम प्रमोट करके एसोशिएट प्रोफेसर बना रहे हैं और उनकी उम्र 62 साल से 65 साल हो जाएगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि इन दो मेडिकल कॉलेज को हम अगस्त में शुरू करना चाहते हैं but it is depends upon the approval of the Medical Council of India. जहां तक तीसरे मेडिकल कॉलेज की बात है उसकी एफ0सी0ए0 की हम कोशिश करेंगे ताकि जल्दी-से-जल्दी काम शुरू किया जा सके। एच0एस0सी0सी0 द्वारा वित्तीय निविदाएं भी की हैं और एक कोणार्क एसोशिएट को कन्स्ट्रक्शन वर्क भी प्रदान कर दिया गया है। तो हमारी कोशिश होगी कि जल्दी-से-जल्दी इसको शुरू करें ताकि डॉक्टर्ज की कमी को पूरा किया जा सके।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सौभाग्य से केन्द्र में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। मैं कहता हूं कि सौभाग्य से आप हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है और कुल्लू के बिल्कुल पड़ोसी है। आपने आज से दो साल पहले मनाली के लेडी बिलिग्टन हॉस्पिटल में लगभग 3000 लोगों के बीच में बड़े उत्साह से कहा था कि मैं प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बना हूं, दरंग का हूं, पड़ोसी हूं और बचपन से कुल्लू मनाली आता रहा हूं तो यहां पर भी हम किसी मेडिकल कॉलेज खोलने का विचार करेंगे, चाहे सरकारी न हो निजी क्षेत्र का ही हो। बाकी जगहों में आप मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या आप हमें भी ऐसा आश्वासन दे सकते हैं कि कोई बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज आने वाले दिनों में कुल्लू के लिए भी देंगे?

मंत्री जी का जवाब जे0के0 द्वारा----

16.03.2016/1150/जेएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2931ः----जारी-----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है मैं वहां पर गया था। वहां पर एक मिशन हॉस्पिटल है। वहां पर सिटी स्कैन का उद्घाटन किया था। श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, माननीय सदस्य ने कहा था कि कुल्लू में भी कोई मेडिकल कॉलेज खोला जाए। मैंने यह कहा था कि अगर प्राईवेट कोई भी पार्टी **कुल्लू में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए इन्ट्रस्टिड हो तो निश्चित तौर पर सरकार उसके लिए इज़ाजत देने पर विचार करेगी।**

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के ग-भाग में मंत्री जी ने कहा जी, नहीं। आपसे ऐसी बेरूखी की हम अपेक्षा नहीं करते और ऐसा रूखा ज़वाब आश्वासन के बावजूद दे दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि भले ही तुलनात्मक दृष्टि से कुल्लू जिला छोटा जिला है, लेकिन आपके द्रंग क्षेत्र के लिए, लाहौल और पांगी के लिए, और फिर सराज क्षेत्र के बाली चौकी व गाड़ागुसैनी के लिए यह एक केन्द्रीय स्थान है, सुविधाजनक स्थान है, इसलिए सारे के सारे मरीज़ वहां के कुल्लू हॉस्पिटल में आते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कोई स्थान विशेष में नहीं कह रहा हूं कि आपकी कृपा आने वाले समय में कुल्लू पर भी होगी या ऐसी ही बेरूखी रहेगी इसका हमें स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए और वहां भी विचार करके कोई न कोई संस्थान देना चाहिए।

Health & Family Welfare Minister: Mr, Speaker, Sir, you know, Himachal is a very small State and we have financial constraints also. It is not possible for the Government to run another medical college in Kullu. So, I request my Hon'ble Member that he should persuade some private party and if it is interested then we will be happy to give permission.

So far as Kullu hospital is concerned, keeping in view the geographical conditions as well as adjoining areas, we have recently upgraded that Regional Hospital from 200 beds to 300 beds. It would be happy to announce here that now we have decided to start Diplomate of National Board Three Years, which

16.03.2016/1150/जेएस/एजी/2

would be a Post Graduate Degree equivalent to Post Graduate Degree, in Kullu also. It would be in four disciplines. These are PG courses. So, it would not be possible for the Government to start another medical college because we have also decided to take over the ESI Corporation College at Mandi which was to be run by the Labour Ministry, Government of India. Since the Labour Ministry has withdrawn and they are not going to continue with the medical college, so they wrote a letter to us. We happily decided that we will take over that college. This college is at the final stage. So, there would be 4-6 medical colleges in the State. For such a small State, this is an honour to have six medical colleges. That is my request.

Concluded

16.03.2016/1150/जेएस/एजी/3

प्रश्न संख्याः 2932

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना यहां सभा पटल पर रखी है उसमें कुल 32 वाहनों के लिए इन्होंने जगह चिन्हित की है। क्या माननीय मंत्री महोदय बताएंगे कि देहरा शहर/बाजार में प्रतिदिन कुल कितने वाहन बाहर से रोज़ाना आते हैं? यहां पर 7-8 बैंक हैं। साथ में मुझे लगता है कि प्रदेश के कार्यालय के सभी विभाग वहां पर है और अधिकारियों/कर्मचारियों के पास कुल कितने वाहन वर्तमान में अपने हैं, वर्तमान में उनकी पार्किंग कहां-कहां होती है?

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

16.03.2016/1155/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 2932 क्रमागत

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

ये जो स्थान चयनित किये गये हैं क्या इनको चयनित करने से पहले वहां के बुद्धिजीवी लोगों से, नगर-परिषद् के चुने हुए प्रतिनिधियों से या व्यापार मंडल कोई बना है उनसे बातचीत की? जैसे मैं भी वहां का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं क्या वहां सब-डिवीजन के एस0डी0एम0 और जिलाधीश ने कभी चुने हुए प्रतिनिधियों से वार्तालाप करने की कोशिश की है? साथ में मेरा एक सुझाव है। आपने "ग" भाग में बताया है कि हमने जगह देखी है और उसकी प्रक्रिया जारी है। उस नाले पर यह सम्भव नहीं है, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो बस-अड्डा वर्तमान में है, मेन सड़क से नीचे है। उस पर पूरे-का-पूरा एक स्लैब डालकर बस-अड्डा नीचे बन जायेगा और उसके ऊपर देहरा शहर के लिए एक परमानैंट और बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था हो जायेगी। जितनी गाड़ियां आप खड़ी करवाना चाहते हैं वह वहां हो सकती हैं। क्या आप उसको प्रायोरिटी देंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐग्जैक्टिव ऑफिसर, देहरा से keeping in view the traffic congestion in Dehra city सुझाव मांगा था। उन्होंने कहा कि आप देखिये कि पांच जगह नगर-परिषद् ने ही यहां सिलैक्ट की थीं, जिसका आपने रैफरैंस दिया है। लेकिन अब यह मामला ओपन है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अभी ऑब्जैक्शन्ज़ लोगों से मांगे हैं, जैसे आपने बात की कि जन-प्रतिनिधियों से पूछा है या नहीं पूछा है। तो ऑब्जैक्शन के लिए उन्होंने एक महीने का समय दिया है। लेकिन यह मामला अभी ओपन है। अगर आप चाहेंगे तो जो आपने सुझाव दिया है उस पर भी अर्बन डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट विचार करेगा because we have not finally decided where to construct the parking place in Dehra city.

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, देहरा के साथ हमेशा ऐसा अन्याय होता आया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जितने वहां के कार्यालय बने हैं वे सारे-के-सारे देहरा शहर के बीच में हैं। मध्य में हैं। जैसे पी0डब्ल्यू0डी0 का एक्सियन का ऑफिस है तो वह बिल्कुल मध्य में है। उन्होंने देहरा शहर की बहुत प्राइम लैंड ऑक्यूपाई कर रखी है उस कार्यालय को कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। वहां पर मिनी सचिवालय

16.03.2016/1155/SS-AG/2

बना हुआ है लेकिन वह पार्किंग और जो आपने अन्य नगर-परिषदों के लिए कहा कि मॉल इत्यादि बनायेंगे उसकी व्यवस्था की जाए। उस कार्यालय को वहां से शिफ्ट किया जाए क्योंकि अन्यत्र जगह साथ में बहुत ज़्यादा है। उससे सारी समस्या का हल हो जायेगी तथा लोगों को वहां पर आने-जाने में सुविधा होगी। क्या आप इसको भी प्राथमिकता देंगे? जो मैंने अड्डे की बात कही है आपने उसका उत्तर नहीं दिया। क्या माननीय मंत्री जी उसके ऊपर भी गौर फरमायेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः सर, जहां तक बस अड्डे की बात है वह तो परिवहन मंत्री जी बतायेंगे क्योंकि बस अड्डे बनाना परिवहन डिपार्टमैंट का काम है। लेकिन यह ठीक है कि आपने सुझाव दिया है। मैं यह भी बोलना चाहता हूं कि देहरा के साथ भेदभाव की कोई बात नहीं है। अगर भेदभाव वाली बात होती तो यह कार्य अभी शुरू न होता। लेकिन फिर नगर-परिषद् ने जो सुझाव भेजे हैं कि उसके साथ ही कोई नाला है उसको चैनेलाइज करके मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन सकती है और वहां पर 100 से ज़्यादा गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। जो आपने सुझाव दिया है और नगर परिषद् ने सुझाव दिया है जो चार-पांच जगह चिन्हित कर दी गई हैं I will ask Deputy Commissioner, Kangra to consult you and hold the meeting with the representatives of the Beopar Mandal and you also so that suitable land can be identified where parking place can be constructed at the earliest.

16.03.2016/1155/SS-AG/3

प्रश्न संख्याः 2933

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में जगह-जगह टावर लगे हैं। इस मामले में मैं आपको बताना चाह रही थी। आपने आई0टी0 की बात कही। अर्बन लोकल बॉडीज़ व पंचायत और सूचना पूरे प्रदेश से एकत्रित की जा रही है। इसमें दुर्गम स्थान जैसे लाहौल-स्पिति व चम्बा भी मौजूद है, शीघ्र ही यह सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सरकार as per existing policy केवल एक बार इंस्टॉलेशन फी व एनुअल रिन्यूअल फी लेती है।

(ग) इस बारे में विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है। 6 डिस्ट्रिक्टस शिमला, बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर और सिरमौर से सूचना प्राप्त हुई है।

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2016/1200/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 2933 जारी---

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी----

और उसके मुताबिक सरकारी भूमि पर लगे टावर का किराया निजी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जा रहा है और अन्य जिलों से सूचना आनी शेष है। धन्यवाद।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि कितनी देर में, कब तक यह सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, हम जरूर सूचना आपको उपलब्ध करवा देंगें।

प्रश्नकाल समाप्त

16.03.2016/1200/केएस/एएस/2

अध्यक्षः No Question. अब कोई प्रश्न नहीं होगा। बिन्दल जी, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। अब आप किस बारे में कहना चाहते हैं? Whatever you want to say, it should not be pertained to any question.

व्यवस्था का प्रश्न

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। केन्द्र सरकार की एक नई

योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। उसके प्रारूप सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर बनाए जा रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि जिला परिषदों में इसके प्रारूप बनाकर इसी सप्ताह प्रदेश सरकार को आएंगें और प्रदेश उनको केन्द्र को भेज रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें अरबों रुपया अगले चार साल में व्यय हो रहा है। हिमाचल प्रदेश का किसान इससे समृद्ध हो सकता है। इस योजना के जो प्रारूप बनाए जा रहे हैं वे मिड हिमालय या अन्य योजनाओं की तरह पानी की तरह पैसा बर्बाद न हो जाए, एक तो यह कहना चाहता हूं दूसरे, विधायक की कन्सल्टेशन इसमें नहीं ली जा रही है । जिला परिषद कल और परसों में सारी शैल्फें एप्रूव करके प्रदेश को भेजने वाली है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि सभी विधायकों से कन्सल्ट करते हुए इसकी शैल्फों को भिजवाने का कष्ट करें अन्यथा इस योजना के पैसे बिल्कुल बेकार हो जाएंगें और इसी योजना के माध्यम से हिमाचल का कल्याण होना है। यह विषय मैंने अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उठाया है और माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी ओर जरूर ध्यान दें।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष : ठीक, है। आप बोलिए, सरकार की तरफ से जवाब कोई भी दे सकता है।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय जय राम ठाकुर जी और बाकी विधायकों की चिन्ता था और हाऊस की भी चिन्ता थी कि भेड़ और बकरी पर जब इनको कोई जंगली जानवर मारता है तो कितना कम्पन्सेशन मिलता है? अध्यक्ष जी, वर्ष 1996 में 188 रु0 मिलते थे

16.03.2016/1200/केएस/एएस/3

उसके बाद 27.08.2001 में 400 रु0 हुए और 04.03.2014 में अब 1500रु0 प्रति भेड़ है और अगर कोई ऐसा केस वाईल्ड लाईफ के पास या फोरैस्ट डिपाटैमैंट के पास होगा, पूरे प्रदेश का तो उसको तुरन्त पैसा स्वीकृत करके प्रभावित को रिलीफ दिया जाएगा।

अध्यक्षः जय राम जी, जो आप बात कर रहे थे उसकी वन मंत्री जी ने क्लैरिफिकेशन दी है। There should be no exchange for this. The Hon'ble Minister is informing

---

you about the rate of compensation.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, इसको बराबर करने में क्या दिक्कत है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो बीमारी की वजह से या महामारी की वजह से मर जाते हैं, उसमें कम्पनसेशन हमारा विभाग देता है और जो जंगली जानवर खाते हैं वह फोरैस्ट विभाग देता है और फोरैस्ट विभाग ने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी कि हम कितना देते हैं।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष जी, हम कह रहे हैं कि इसको बराबर करने में क्या कठिनाई है?

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इनकी जो शंका है, माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके इसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2016/1205/av/as/1

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 36(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण राज्य आयोग नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसजेई-ए-ए (3)-4/2014 दिनांक 05.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.02.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बालक

अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 36(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण राज्य आयोग नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसजेई-ए-ए (3)-4/2014 दिनांक 05.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.02.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

16.3.2016/1205/av/as/2

अध्यक्ष : माननीय धूमल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक डॉ0 राजीव बिन्दल ने बहुत महत्व का प्रश्न उठाया था। प्रधान मंत्री सिंचाई योजना का जो कार्यक्रम प्रारम्भ हो रहा है उसमें पंचायती राज संस्थाओं के भी सुझाव लिए जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। वह शैल्फ जिला परिषद से बनकर आयेगा। माननीय विधायक लोग भी चाहते हैं कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण योजना में प्रदेश का पक्ष सही ढंग से रखा जाए ताकि अधिक-से-अधिक धन उपलब्ध हो सके। इसलिए माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि भारत सरकार को भेजने से पहले उस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विधायकों को भी शामिल किया जायेगा? हम सभी ऐसा आश्वासन चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमें सुझाव अच्छे लगते हैं और मैं इसके ऊपर विचार करूंगा।

16.3.2016/1205/av/as/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति

(वर्ष 2015-16), समिति का 55वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्याः 2) के पैरा संख्याः3.8 व 3.9 की संवीक्षा पर आधारित है तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2015-16) का 55वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्याः 2) के पैरा संख्याः3.8 व 3.9 की संवीक्षा पर आधारित है तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर भी रखती हूं।

16.3.2016/1205/av/as/4

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2015-16), समिति का 18वां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति (वर्ष 2015-16) का 18वां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

16.3.2016/1205/av/as/5

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा जो कि पिछले कल यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने रुकवाया था।

अब माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। इस विषय पर श्री जय राम ठाकुर और श्री महेश्वर सिंह जी की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। अगर आप चाहें तो चर्चा में भाग ले सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जिला कुल्लू के मनाली व इसके साथ लगते अन्य पर्यटक स्थलों में समस्त पर्यटन गतिविधियों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां यह विषय कल प्रश्न काल से पहले उठाया था। उसके पश्चात विपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार धूमल जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चलो; देर आयद, दुरुस्त आयद। मैं अपनी बात प्रारम्भ कर रहा हूं। मेरी चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी से ही होनी है मगर माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी बातचीत में मस्त हैं। मैं जिस विषय पर यहां पर चर्चा कर रहा हूं उसके लिए मेरा निवेदन है कि आप इसको ध्यान से सूनें।

टीसी द्वारा जारी

16.03.2016/1210/TCV/DC/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ---- जारी।

माननीय मुख्य मंत्री जी मैं यहां पर यह विषय अगर लाया हूं तो मुझे कोई स्कोर/ प्वाईंट्स नहीं लेने हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

मैं गत 2 वर्षों से समय-समय पर प्रयास करता रहा हूं कि जो लोकहित की समस्या हो वह सरकार के ध्यान में लाएं और इस मान्य सदन में भी उस पर चर्चा हो। पिछले वर्ष भी

मैंने विधान सभा में प्रश्न भी किए थे और एक बात यह कही थी कि अब तक सरकार के द्वारा 'नेश्नल ग्रीन ट्रिब्युनल' में कब-कब क्या-क्या पक्ष रखा गया है, कौन-कौन से शपथ पत्र दिए गये हैं, वह जानकारी हमको मिले तो सरकार का उत्तर था कि सूचना एकत्रित की जा रही है। गत वर्ष 23, 24 जनवरी को सचिवालय में विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी ये विषय जब मैंने रखा तो आपने (मुख्य मंत्री) उसको सुन करके सरकारी अधिकारियों को ये कहा कि इसका जवाब दो। इसके बारे में एडिशनल चीफ़ स्क्रेटरी ने ये कहा कि इस बैठक के बाद जो एफेडेविट हमने दिए हैं,उनकी प्रति हम विधायक महोदय को भी देंगे ताकि इस पर कोई और विचार भी आ सकें। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी वह नहीं हुआ। इस बार जब मेरा प्रश्न लगा तो उस प्रश्न के अन्त में ये कहा गया कि वह प्रश्न विलोप किया गया। अततः मुझे इस सदन में अपना नोटिस देना पड़ा और उसके लिए मैं इस सदन का धन्यवाद करता हूं कि आपने इसको चर्चा के लिए स्वीकार किया। माननीय मुख्य मंत्री जी एक बात कहते हैं कि समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। मैं केवल मात्र समाधान और रास्ते तलाश करने के लिए यहां बात कर रहा हूं। कहते हैं कि जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हो। और जब आप किसी को हंसाते हो तो ईश्वर आप के लिए प्रार्थना करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज इस मनु की नगरी/देवभूमि के लोग वास्तव में मायूसी का जीवन जी रहे हैं। मैं सरकार के माध्यम से और आपके अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी मुझे चाहिए थी, वह मुझे प्राप्त नहीं हो सकी और पिछले कल बजट भाषण में मैंने कहा है कि जब हम सदस्य सदन में बोलते हैं तो क्या केवल मात्र सरकार और सरकार के अधिकारी सुनते हैं और सुनने के बाद क्या वह भूल जाते हैं?

16.03.2016/1210/TCV/DC/2

कभी-कभी लगता है कि हमारा कहना यह तो नहीं कि विधायक लोग है और विधायिका बोलती रहती है और कार्यपालिका को लगता है कि करना तो हमको वही है जो हमको करना है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं कुछ बातें आपके ध्यान में लाता हूं। केवल मात्र समाधान की दिशा में 3 जनवरी, 2013 व 3 मई, 2013 को माननीय उच्च न्यायालय ने मनाली-रोहतांग के संबंध में कुछ आदेश पारित किए और 3 मई, 2013 को जो आदेश पारित हुए, उसे माननीय उच्च न्यायालय ने 'नेश्नल एनवायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग

रिजनल इन्स्टीच्यूट' कानपुर, 'नीरी' की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किए। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें एक बात कही गई कि रोहतांग ग्लेशियर है और ईको सेंस्टिव एरिया है। लेकिन उसके बाद जी0बी0 पंत की रिपोर्ट के आधार पर ज्वाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ0 मिलाप चन्द और इन सब ने जो अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि रोहतांग ग्लेशियर नहीं है, रोहतांग केवल मात्र स्नो लाईन है और

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी ।

16.03.2016/1215/RKS/DC/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर द्वारा जारी....

यह ईको सैंस्टीव जोन नहीं है। गुलाबा के ऊपर कभी भी ईकोलॉजी नहीं रही है। रोहतांग के नजदीक अगर कोई ग्लेशियर है तो उस ग्लेशियर को हामटा कहा। हामटा के बारे में कहा गया कि यह स्टैगनेंट है। यह कहा गया कि जो 4 साल पुरानी गाड़ियां है, टैक्सियां हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा, टैक्सियों के स्थान पर बसों द्वारा पर्यटकों को रोहतांग तक ले जाना। तीसरा, सभी प्रकार के ढारों, ढाबों, होटल जो कि कोठी से लेकर रोहतांग पास तक है, उनको अनऑथोराइजड करके तोड़ने के आदेश दिए जाएं। चौथा, वैटरी ऑपरेटिड स्नो स्कूटर चलाए जाएं और स्नो स्कूटर्ज ऑल टेरेन व्हीकल्स इनको यहां पर चलने से बंद किया जाए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नेशनल ग्रीन टिब्यूनल में जाने के लिए एक साल का समय बीत गया। इस एक वर्ष के मध्य में सरकार कोई एस.एल.पी. इत्यादि करने में सर्वोच्च न्यायालय में नहीं गई। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही कि इसमें विधायकी की पार्टी और विधायक, लोगों को भड़काते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपका विधायक न होटल व्यवसायी है, न टैक्सी ऑपरेटर है, न मेरे पास स्नो स्कूटर है, न मेरे पास स्कींग है, न मैं पैराग्लाईडिंग करता हूं। लेकिन जब वह आंदोलन हुआ तो उसमें कांग्रेस पाटी के नेता मुझसे पहले वहां पहुंचे थे और जो आपके सबसे नजदीकी माने जाते हैं वे उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। जब आंदोलन हिंसात्मकता की ओर बढ़ गया, उस सारे वातावरण में आपके डिप्टी कमिश्नर और एस.पी. ने मुझे फोन करके कहा कि विधायक जी आप बीच में नहीं आएंगे तो लोगों को शांत करना मुश्किल हो

जाएगा। लगभग 5,000 लोग जो मनाली के मॉल में इकट्ठा थे, सड़क खाली करने को तैयार नहीं थे। लेकिन लॉ एण्ड ऑर्डर बना रहना चाहिए, मैंने लोगों को कहा मेरी जिम्मेदारी में आप रोड़ खोल दो, खाली कर दो और प्रशासन के अधिकारियों ने इसके लिए हमारा धन्यवाद किया कि आपके कारण आज स्थिति संभल गई। लेकिन परिणाम यह हुआ कि आज भी हम कोर्ट में केस भुगत रहे हैं। मनाली के टैक्सी ऑपरेटर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरिम ऑर्डर है, वापिस हाई कोर्ट मे जाओ। जब वापिस हाई कोर्ट

16.03.2016/1215/RKS/DC/2

में आए तो हाई कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया। लकिन उसके पश्चात् मनाली टैक्सी ऑपरेटर फिर से सुप्रीम कोर्ट गए। ढाबा वाले गए, ढारे वाले गए। दिनांक 30.7.2013 व 8.08.2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि रोहतांग तक जाने के लिए गाड़ी की एज(मॉडल) मैटर नहीं करेगा। गाड़ी की कंडिशनज कैसी है, पॉल्यूशन चैक करो उसके बाद अगर लगता है कि गाड़ी सारे नॉम्स फुलफिल करती है तो वह चलेगी। इसमें गाड़ी की एज मैटर नहीं करेगी। साथ में यह भी कहा कि प्रदेश सरकार इन टैक्सी ऑपरेटर्ज के लिए हिमाचल प्रदेश में एक पॉलिसी बनाएं।

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी

16.03.2016/1220/SLS-AG-1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ...जारी

उपाध्यक्ष महोदय, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपनी गाईडलाइंज दीं, उस समय सुप्रीम कोर्ट की बात को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताने का काम जनता का था या सरकार का था? उस बीच मढ़ी के ढाबे वाले कुछ लोगों को स्टे मिला है जिनके ढाबों को तोड़ा नहीं गया है। जब वे गरीब लोग वहां तक जा सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं गई? फिर 08.08.2013 के बाद ये सभी केसिज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर हो गए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसके पश्चात जो अपने आदेश सुनाए उनमें पहला

आदेश में उन्होंने कहा कि रोहतांग तक हर प्रकार की पर्यटन गतिविधि को बंद किया जाए। दूसरा, सभी खोखों और ढाबों को तोड़ने के आदेश दिए गए। तीसरा, डीजल टैक्सी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। चौथा निर्णय सी.एन.जी. बसों को चलाना था। पांचवां, प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि इसकी कंपलाईंस रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सीमित साधनों से सीमित जानकारी दे रहा हूं; आपके पास पूर्ण जानकारी होगी। उसके पश्चात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि 50 रुपये कंजैशन चार्जिज लगाए जाएं। फिर 15 जुलाई, 2014 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी प्रकार के वाहनों, जो टूरिज्म परपज के लिए चलाए जा रहे थे, उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उन आदेशों को पुनः जांचने के लिए प्रभावित लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ऐप्लिकेशन लगाई। फिर 19 फरबरी, 2015 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश सरकार को रिहैबिलिटेशन पौलिसी बनाने के लिए कहा। मेरे पास उस ऑर्डर की कॉपी है जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 19 फरबरी, 2015 को कहा कि चाहे सोलंग नाला है या रोहतांग पास है, जहां-जहां से भी इन लोगों को उजाड़ा गया है, प्रदेश सरकार इन सबके लिए एक महीने के भीतर पुनर्वास नीति लेकर आए और ईको फ्रैंडली मार्किट बनाए। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं जानना चाहता हूं कि अगर 19 फरबरी, 2015 को यह आदेश एक महीने के लिए था तो जहां-जहां से उन लोगों को उजाड़ा गया था, अभी तक भी वहां ईको फ्रैंडली मार्किट क्यों नहीं बनी, इसके लिए कहां कमी रही? फिर गुलाबा और वशिष्ट में ऑन लाईन पाल्युशन चैक पोस्ट की बात है। यह एक और निराशाजनक आदेश है।

16.03.2016/1220/SLS-AG-2

रोहतांग में 1000 गाड़ियों का प्रतिदिन जाना और उनमें से 600 पैट्रोल तथा 400 डीजल की गाड़ियों का जाना और इन सब गाड़ियों का बी.एस.-4 का कम्पलाईंस होना भी निराशाजनक आदेश है। उपाध्यक्ष महोदय, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से यह गाईडलाईन्ज आईं कि बी.एस.-4 की कम्पलाईंस हो, तो क्या हमारे सरकारी अधिकारी, हमारे एडवोकेट जिनकी मौजूदगी में यह निर्णय हुआ, ये लोग यह क्यों नहीं बता पाए कि हिमाचल प्रदेश में तो बी.एस.-4 ऑयल उपलब्ध ही नहीं है। उस समय मीनिस्टरी ऑफ पैट्रोलियम के डायरैक्टर ने यह कहा कि प्रदेश से भी कोई अधिकारी

दो जिसके साथ सी.एन.जी. और अन्य सब बातों के बारे में चर्चा की जा सके। मैं आपके ध्यान में एक और जानकारी लाता हूं। 21 जुलाई और 23 जुलाई को आपने ट्रॉयल किया। आप कहते है कि वहां पर सरकार ने अपने तर्क रखे। अगर सरकार ने तर्क रखे तो क्या सरकारी मशीनरी ने सी.एन.जी. की कॉस्ट को वर्कआऊट नहीं किया था? अगर वहां पर आपने सी.एन.जी. का ट्रॉयल किया तो उससे पहले क्या आपने मीनिस्टरी ऑफ पैट्रोलियम के साथ सी.एन.जी. के लिए कोई योजना बनाई थी और मीनिस्टरी ऑफ पैट्रोलियम और प्रदेश सरकार ने मनाली तक सी.एन.जी. की पाईपलाईन बिछाने के बारे में कुछ सोचा था?

जारी ...श्री गर्ग जी

16/03/2016/1225/RG/AG/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर------क्रमागत

और दिल्ली से दो बसें लाकर आपने रोहतांग के लिए ट्रायल किया। अब यह जानकारी मुझे नहीं है, कल माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि इस पर 25,00,000/-रुपये खर्चा हुआ। अब यह एक बस का खर्चा हुआ या दो बसों का खर्चा हुआ, मुझे नहीं मालूम। बिना पाईप लाईन के गैस किट्स लाने पर आप तैयार हो गए, ट्रायल किया और फिर कहते हैं कि हमने अपना पक्ष रखा। तो यह जो 25 या 50 लाख रुपये खर्चा हुआ, क्या यह प्रदेश के गरीब लोगों की जेब पर डाका नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने BS-IV के आदेश किए थे, लेकिन हिमाचल में तो BS-IV ऑयल ही नहीं है, तो क्या इस संबंध में हम उस समय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल एक बात कही कि जब तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल का फाईनल फैसला नहीं आता तब तक हमारे हाथ बंधे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। अगर सरकार के हाथ बंधे हैं, तो इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में टैक्सी ऑपरेटर्ज गए और ढाबे वाले गए। उनकी ऐप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यहां यह निवेदन करता हूं कि इसी सप्ताह में, मैं स्वयं भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला हूं। क्योंकि ये तो पिछले तीन साल से कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ करेंगे। मैं आपको दोष नहीं देता, आप संवेदनशील हैं, आप हमारी बात सुनते हैं। इस सबसे आज जो परिदृश्य वहां बना है मैं उस बारे में यहां

बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में लगभग दस गतिविधियां चलती थीं और 10,000 लोग सीधे तौर पर इन गतिविधियों से जुड़े हुए थे। एक-एक परिवार के 3-3 या 4-4 सदस्य तो पलते होंगे। आज वे सबके सब लोग बर्बादी के कगार पर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त भी बहुत सी चीजें हैं। जिनका प्रदूषण से कुछ लेना-देना नहीं है उनका क्या दोष है? पैराग्लाइडिंग कोई प्रदूषण नहीं करता, स्कीइंग के कारण कुछ नहीं होता, 500 घोड़े वाले हैं, रीवर क्रॉसिंग की गतिविधि है, 200 फोटोग्राफर्ज हैं, जो गरीब बुजुर्ग लोग बर्फ में चलने के लिए 10/-रुपये का एक डंडा किराये पर देते हैं वे लोग हैं, बैलूनिंग करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार के लोग हैं। इनके अतिरिक्त एक टी.वी. स्नो स्कूटर वाले हैं और उनके पॉल्यूशन के सर्टिफिकेट बने हुए हैं कि उनके कारण कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता। इस प्रकार के

16/03/2016/1225/RG/AG/2

लोगों की वहां सारी-की-सारी गतिविधियां बंद हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि यहां चार दिन पहले जिला प्रशासन ने मीटिंग की है कि करीब 400 महिलाएं जो कुल्लू की ड्रैस लगाती है, ढाटू, पट्टू और जो वहां के परिधान लगाती हैं उनका पैसा लेती हैं, लेकिन उनकी गतिविधि भी बंद करके रखी है। यह सच्चाई है। मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहूंगा, यहां पर कहा कि सरकारी अधिकारी भी और दोनों पक्ष 2 नवम्बर, 2014 को सरकार को जो आदेश दिए गए हैं जहां आपके अधिकारी, वकील आदि हाथ बांधकर खड़े रहे और कोई तर्क नहीं दिए। जिस दिन यह निर्णय हुआ, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव(गृह), प्रधान सचिव(वन एवं पर्यावरण), प्रधान सचिव(पर्यटन) और वाईस-चेयरमैन एवं मेंबर सैक्रेट्री, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वहां पर थे। इन सारे आदेशों को हाथ बांधकर माना गया।

एम.एस. द्वारा जारी

16/03/2016/1230/MS/AS/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जारी-----

उसके बाद कम्पलायंस रिपोर्ट दी है और कहीं पर यह तर्क नहीं दिया है कि ये चीज ठीक नहीं है गलत है। मेरे पास जो यह कम्पलायंस रिपोर्ट है इसमें कहा है कि ये 10 चीजें हमने कर दी हैं। जिन आदेशों के बारे में यह कहा गया कि लोगों को तोड़ने का काम है तो तुरन्त तोड़ डाले। लेकिन जब कहा कि रिहैब्लिटेशन पॉलिसी लाओ तो उस पर कुछ नहीं किया। मुख्य मंत्री जी अब पर्यटन सीजन आने वाला है। यह केवल-मात्र कुल्लू-मनाली का विषय नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इन दिनों में लगभग 600 ड्राईवर्ज विद एड्रेसिज मुझे मालूम है, मण्डी, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर के आज की तारीख में मुंबई चले गए हैं। हिमाचल मित्र मण्डल से सम्पर्क करके वे कह रहे हैं कि मनाली का एम्पलॉयमैंट खत्म हो गया है। अब पता नहीं ऐसे कितने लोगों का पलायन होना प्रारंभ हो गया है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन सारी बातों में ठीक प्रकार से कानूनी सलाह-मुश्विरा लेना चाहिए कि हम कैसे लोगों के हित में काम कर सकते हैं। जो नॉन पॉल्यूटिंग से संबंधित छोटा-मोटा काम करने वाले हैं, जिनका पर्यावरण से कुछ भी संबंध नहीं है, इनका काम प्रारंभ करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके लिए कानूनी सलाह ली जा सकती है। फिर उसमें एक चीज और है। -(घण्टी)- उपाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट का समय लूंगा। मुख्य मंत्री जी, जब 15 मई, 2015 को आप कुल्लू-मनाली आए थे तो जगतसुख में आपने स्कूल का शिलान्यास किया। उस जनसभा में जब मैंने यह विषय रखा तो आपने कहा कि अच्छा है आपने जनता का विषय रखा है। आपने उस दिन भी कहा था कि हम केवल-मात्र रोहतांग-मनाली के लिए बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता रखेंगे। अगर हमें प्राईवेट भी करना पड़े तो करेंगे। यही बात 23 और 24 जनवरी को हुई और उस जनसभा के बाद आप सोलंगनाला गए और वहां आपने पलचान में हाई स्कूल का शिलान्यास किया। फिर मनाली के सर्किट हाऊस में आपको होटल व्यवसायी और व्यापार मण्डल के लोग मिले और सब लोगों को भी आपने यही कहा कि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता लगाऊंगा जो स्पैशली इस मामले को ही देखेगा। मेरा निवेदन है कि यह अत्यन्त आवश्यक मुद्दा है और स्वारघाट से

16/03/2016/1230/MS/AS/2

मनाली तक पूरे देश के लोगों के लिए और लोकल लोगों के लिए है। मुख्य मंत्री जी एक और चीज कहूंगा। कभी-कभी लगता है कि कन्ट्राडिक्टरी कितनी चीजें हैं। इन सब बातों के साथ-साथ एक बात और कि रोहतांग में ह्यूमन कन्जैशन भी बढ़ रहा है। अब ह्यूमन कन्जैशन अगर रोहतांग में बढ़ रहा है तो इसको हम भी मानते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, मैं रोप-वे का विरोधी नहीं। अब ह्यूमन कन्जैशन के कारण से यह भी कहा है कि आप साथ में पीने-के-पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते। अगर ह्यूमन कन्जैशन बढ़ रही है, वैसे मेरी जानकारी अधूरी है लेकिन जो रोप-वे रोहतांग के लिए लगेगा, उसकी एक दिन लगभग 10 हजार लोगों को ले जाने की कैरिंग कपैस्टी होगी। उस मेमोरैण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग में यह भी है कि तब तो रोहतांग और गुलाबा में रेस्टोरैंट भी बनेगा। तो फिर इन छोटे-छोटे लोगों का क्या दोष है? मुख्य मंत्री जी, इसके साथ एक और बात है। मैं यह कहता हूं कि अगर रोहतांग में ह्यूमन कन्जैशन है तो दो साल के बाद रोहतांग टनल बनकर तैयार हो जाएगी। वहां से आर्मी के ट्रक और सारा लोकल ट्रैफिक भी वहां से जाएगा। रोहतांग केवल-मात्र क्या पर्यटकों के लिए रहेगा? दूसरा, हमारे पास रोहतांग जैसे सुन्दर और रोहतांग से भी अधिक सुन्दर और अनेक डैस्टिनेशन्ज हैं। अब जिस तेजी से हम रोहतांग के रोप-वे के काम के लिए लगे हैं उसी तेजी से आप भृगु के लिए भी लगें। आप बिजली महादेव के लिए लगे। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अंत में मैं एक बात कहूंगा कि आपके जिलाधीश और प्रदेश सरकार ने एक बात कही है कि मनाली, सोलंग और रोहतांग के क्षेत्रों में सारी कमर्शियल गतिविधियां बन्द हैं। अगर बन्द है तो लाठी, बूट, कोट, पट्टू का छोटा-मोटा कारोबार भी बन्द है लेकिन बड़े लोगों के लिए कुछ और और छोटे लोगों के लिए कुछ और है। सोलंगनाला का जो रोप-वे है वह दिन-रात चलता है जबकि बाकी सब गतिविधियां बन्द हैं। आज प्रातःकाल मुझे किसी का फोन आया कि बाकी तो सब प्रशासन ने बन्द कर दिया है लेकिन रोप-वे के मालिक ने 25-30 पैरा ग्लाइडिंग वालों

को बुलाकर कहा कि तुम सोलंगनाला में अगर पैरा ग्लाइडिंग कर सकते हैं तो कर लो।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

16.03.2016/1235/जेएस/एएस/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः------जारी------

यहां पर तुम्हें कोई रोकेगा तो मुझे कह देना, यह वास्तविकता है। वे लोग यहां आ करके कहने को तैयार है। अब दोहरा मापदण्ड क्यों? उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि मैंने यहां पर कुछ बातें लाने के लिए यह विषय रखा और इस सारे विषय में मैं आपको यह कहता हूं कि मेरी किसी भी बात को माननीय मुख्य मंत्री जी अन्यथा लेने का प्रयास न करें। यह मेरा दर्द, पीड़ा है और मैंने इस बार भी आपसे कहा था कि जब पंचायतों का चुनाव चल रहा था उस दौरान लोगों ने कहा कि सरकार ने हमारा पक्ष नहीं रखा। एक तरफा पूरी घाटी में वातावरण बन गया कि प्रदेश सरकार के विरूद्ध हम पंचायत चुनावों का बहिष्कार करेंगे। आप समाचार पत्र निकालो। मैंने कहा कि वोट चाहे आप मेरे प्रत्याशियों को न दो, लेकिन चुनाव का बहिष्कार मत करो। अराज़कता पैदा मत करो। मेरे अपने लोगों ने कहा कि तू चुनाव करवाने के लिए कह रहा है तेरा अपना नुकसान होगा। लेकिन खुल करके चुनाव बहिष्कार रुके और उसके बाद उसको रोका भी। चार पंचायतों के आम लोगों ने लिखा कि सरकार की नालायिकी का हम बहिष्कार करते हैं, लेकिन हमने उसे रोका जो कि हमरा कर्त्तव्य था। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक बात करके समाप्त करूंगा कि क्या आप इस सारे विषय में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए पुनर्वास नीति, उनके लिए मुआवज़े की बात की जाए, जिनका नुकसान हुआ है। आने वाले पर्यटन सीज़न में आप क्या करने वाले हैं, कैसे ये गतिविधियां प्रारम्भ होने वाली हैं, इन सब पर गम्भीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है? उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यहां पर मेरी बात को रखने का मौका दिया, जो कि तुरन्त, ज्वलंत और सामयिक मुद्दा है। मैं इस माननीय सदन का, इस मुद्दे के अलावा विशेषकर प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, प्रतिपक्ष के नेता जिनका कल हमें आर्शीवाद मिला और जो ताकत हमको मिली, उसके बाद मुख्य मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

16.03.2016/1235/जेएस/एएस/2

उपाध्यक्षः श्री जय राम ठाकुर जी, चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जय राम ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं। ____(व्यवधान)____

संसदीय कार्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, कल यह बात हुई थी कि श्री सुरेश भारद्वाज जी ने कहा था कि नियम-62 में चर्चा होगी। ____(व्यवधान)____

श्री जय राम ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है तो हम नहीं बोलेंगे। ____(व्यवधान)____

Deputy Speaker: Shri Jai Ram Ji, let him speak.

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय सदस्य, पहले आप हमारी बात सुनें। श्री सुरेश भारद्वाज जी ने कहा था कि नियम-62 में चर्चा होगी और गोविन्द सिंह ठाकुर जी मसला उठाएंगे और यहां से मंत्री जी रिप्लाई करेंगे और रूल भी यही कहता है। रूल-62 भी यही कहता है। उसके बाद इन्होंने दो लोगों से और नोटिस लगा दिया। इसमें महेश्वर सिंह जी का और श्री जय राम ठाकुर जी का भी नोटिस आ गया। इसमें रूल बिल्कुल क्लीयर है कि गोविन्द सिंह ठाकुर जी बोलेंगे और रिप्लाई होगा। इसमें rest of the members क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, लेकिन अदरवाईज यह तो नियम-130 में एक्सैप्ट हो जाता। अगर चर्चा करवानी है तो यह नियम-130 में एक्सैप्ट होती है, फिर नियम-62 का क्या औचित्य रहता है?

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठिए। इसमें पांच-पांच मिनट के लिए दोनों बोलेंगे।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस रूल के अन्दर चर्चा हो रही है ताकि हम भी जानें कि उस रूल की परिधि क्या है? उसकी सीमा क्या

है? हमें डिस्कशन से कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई गुरेज़ नहीं है। मगर रूल कोई

16.03.2016/1235/जेएस/एएस/3

कोट किया जाता है और उसकी अवहेलना करते हुए दूसरे रूल की बात की जा रही है। It is chaos (व्यवधान)____ नहीं, नहीं इसमें ऐसा नहीं होता है।

उपाध्यक्षः प्लीज, रूल-62 में श्री जय राम ठाकुर और महेश्वर सिंह जी का नाम भी आया हुआ है इसलिए ये पांच-पांच मिनट बोलेंगे। श्री जय राम ठाकुर जी आप लोग पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जय राम ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें मैं भाषण नहीं दूंगा, लेकिन अपनी बात तो मुझे यहां पर रखनी पड़ेगी। अगर नहीं कहा जाए तो मुझे लगता है कि आप बहुत कठिन परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अन्तर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी ने यहां पर रखा है, मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

16.03.2016/1240/SS-DC/1

श्री जय राम ठाकुर क्रमागतः

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ गोविन्द ठाकुर जी को इस बात के लिए बधाई देनी है कि विस्तार से इन्होंने एक-एक चीज़ को लेकर यहां पर अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। पीड़ा अपनी ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की है। मुझे लगता है कि यह पीड़ा हिमाचल प्रदेश की होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, बात आ रही है कि एक विधायक इस प्रकार से इस बात को यहां पर उठा रहे हैं, बजट सत्र चला है, हमारे विधान सभा क्षेत्र के छोटे-छोटे मुद्दों को ले करके लोगों को जन-प्रतिनिधियों से उम्मीद रहती है कि हमारे मुद्दों को विधान

सभा के अंदर उठाया जाए। मैं मानता हूं कि यह मुद्दा सिर्फ मनाली विधान सभा क्षेत्र का नहीं है। यह मुद्दा पूरे हिमाचल प्रदेश का है। मनाली हिमाचल प्रदेश में एक इंटरनेशनल डैस्टीनेशन है। इस बात का हमको गर्व है। जिस प्रकार से वहां पर परिस्थिति पैदा हुई है वे ठीक नहीं है। हमारा पर्यटन पूरी दुनिया से उठ करके मनाली पहुंचता है और मनाली में रहने के बाद जो सबसे बड़ा आकर्षण का केन्द्र है वह रोहतांग पास है। जहां पर लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर बर्फ मिलती है। वहां पर बहुत सारी गतिविधियां खेलों के माध्यम से चलती हैं। उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसका आनन्द लेते हैं। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इसका महत्व पूरे प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जो माननीय सदस्य, श्री गोविन्द ठाकुर जी ने यहां पर बात कही है, इस सारी परिस्थिति के लिए कहीं तो हम भी जिम्मेदार हैं। जो परिस्थिति वहां पर पैदा हुई उसके कारण एन0जी0टी0 की तरफ से आदेश आया। हाई कोर्ट की तरफ से पहले आदेश आया। उसके बाद एन0जी0टी0 की तरफ से आदेश आया। उनके प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। उनके बारे में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वह थोड़ा जरूरत से ज्यादा है। जिस बात को खुद माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है। पर्यटन की दृष्टि से मनाली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मनाली के साथ-साथ रोहतांग का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन उसके साथ-साथ हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि रोहतांग पर ही दुनिया समाप्त नहीं हो जाती। रोहतांग के पीछे

16.03.2016/1240/SS-DC/2

भी दुनिया रहती है। लोग वहां से जाकर स्पिति जाते हैं। रोहतांग से हो करके लाहौल जाते हैं। लाहौल के बाद लेह जाते हैं। आपके पांगी भरमौर के लिए जाते हैं। अगर हम उन सारी चीज़ों को देखें तो मुझे लगता है कि एक बहुत कड़ा निर्णय ले लिया। कठोर निर्णय ले लिया। मैं महसूस करता हूं कि इतने कठोर निर्णय की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह सचमुच चिन्ता का विषय है कि सरकार के ध्यान में यह विषय आने के बाद वहां पर हाई कोर्ट ने रैस्ट्रिक्शन इम्पोज़ की। उस निर्णय के बाद हम ठीक प्रकार से अपना पक्ष कहां रख सकते हैं वह नहीं रखा। आगे एन0जी0टी0 का

आदेश आ गया। उस निर्णय में ठीक प्रकार से अपना पक्ष रखने में एक साल का कार्यकाल बीत जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार इस सारे मसले को गम्भीरता से नहीं ले रही है। हज़ारों की तादाद में वहां पर, जिनको रोज़गार मिला था, वे बेरोजगार हो गये। आज वे वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी परिस्थिति निर्मित होने के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह सरकार के सिवाय दूसरा कोई नहीं है क्योंकि उनका पक्ष रखने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयत्न होने चाहिए थे वे प्रयत्न हुए ही नहीं। इस दृष्टि से, अध्यक्ष महोदय, एन0जी0टी0 के निर्णय के बाद जो भी मसले यहां पर उठाये गये, मेरा सरकार से निवेदन है कि इसको अन्यथा न लें। माननीय मुख्य मंत्री जी इसको अन्यथा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। यह मसला पूरे हिमाचल प्रदेश का है। सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि श्री गोविन्द ठाकुर जी विपक्ष के विधायक हैं, मनाली के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं इसलिए वे इस मसले को उठा रहे हैं और इनकी बात या मसले का समाधान करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि यह सोचना गलत होगा। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें पहल लेनी चाहिए। एक मसला एक बार नहीं बल्कि कई बार उठा। लोग वहां पर दर-दर भटक रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनको कुछ मदद मिलेगी। मदद की कहां से उम्मीद करते हैं? मदद की सरकार से उम्मीद करते हैं। अपने चुने हुए प्रतिनिधि से करते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जितने भी तमाम मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2016/1245/केएस/डीसी/1

श्री जय राम ठाकुर जारी----

सरकार इन तमाम मुद्दों पर गम्भीरता से विचार करने के साथ-साथ अगला कदम उठाएं ताकि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से मनाली जो एक बहुत ही सुन्दर क्षेत्र है और इसके साथ-साथ रोहतांग जो बहुत बड़ा आकर्षण का केन्द्र हैं वहां पर सारी चीजें ठीक रहें, यह बात आवश्यक है लेकिन उसके साथ में इस प्रतिबन्ध को तुरन्त प्रभाव से रोकने

के लिए जो कदम सरकार की ओर से उठाए जाने चाहिए, वे कदम सरकार उठाए ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। इतना ही मुझे कहना था अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

16.03.2016/1245/केएस/डीसी/2

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय नियम-62 के अंतर्गत संयुक्त रूप से हमें उठाने की अनुमति आपने प्रदान की है, उसके लिए मैं आसन का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्य, गोविन्द सिंह जी ने विस्तार से सभी बातें कही है और यह एक दिन में उठी समस्या नहीं है। अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए गत 15 वर्षों में जितनी भी सरकारें रही, सभी इसके लिए जिम्मेवार है और विशेष रूप से पर्यटन और वन विभाग इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। मुझे कहा गया कि केवल प्रश्नों को ही पूछा जाए तो मैं उन्हीं बिन्दुओं तक सीमित रहूंगा बाकी बात जो गोविन्द जी ने कही मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य नहीं है, 15 वर्ष पूर्व बुद्धिस्ट सर्कट योजना बनी और तत्कालीन केन्द्रीय पर्यटन मंत्री, उन दिनों मैं लोकसभा में था, वे कुल्लू पधारे और होटलियर्ज़ एसोसिएशन की एक मीटिंग में दो टूरिज्म इन्फोर्मेशन सैंटर मंजूर किए। एक मनाली के लिए और दूसरा भून्तर के लिए। क्या कारण है कि वहां पर कोई काम नहीं हुआ? एक जगह तो नींव का पत्थर लग गया लेकिन वहां पर भी काम नहीं हुआ और दूसरी जगह तो काम ही नहीं हुआ, वह पैसा कहां है, भगवान जाने। उसी दिन रोहतांग के लिए सुलभ शौचालय के लिए पैसा दिया गया और मनाली बाज़ार के बीच में एक टूरिस्ट इन्फोर्मेशन सैंटर के लिए भी पैसा दिया गया। उसके बाद रोहतांग पर आम आदमियों ने तो कई शौचालय बना दिए लेकिन कौन सा कारण है कि पर्यटन विभाग वहां पर सुलभ शौचालय नहीं बना सका, कहीं भी नहीं बना सका? कौन सा कारण है कि उस वक्त पर्यटन विभाग और वन विभाग दोनों ही कुंभकरण की नींद सोते रहे? क्यों नहीं जागे? इसके बाद रोहतांग के रास्ते में जहां-तहां लोगों ने खोखे खड़े कर दिए और जैसे यहां पर कहा गया कि यह कहा गया कि इनको हटाओ और ईको फ्रैंडली मार्किट बनाओ और इनकी रीहेबिलिटेशन करो। क्या मैं जान सकता हूं कि यह काम किसने करना था? क्यों नहीं किया, कहां सोए रहे? सारे

लोग उजड़ गए। रोहतांग दर्रे पर और मढ़ी में कोई वृक्ष नहीं है। खुला मैदान है, समतल जगह थी। जो गाड़ियों की पार्किंग नहीं बन सकी उसका दायित्व किसका है? वह एक दिन में

16.03.2016/1245/केएस/डीसी/3

नहीं बननी थी। यह 15 वर्षों में क्यों नहीं बनी? पयर्टन विभाग के लोग क्या करते रहे? मैं क्षमा चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति वहां एनक्रोचमैंट करता है तो वन विभाग सोया रहता है और जब विभाग काम करने लगता है तो गैंती बेल्चा छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। आज वहां पर अगर पार्किंग होती तो यह समस्या खड़ी नहीं होती। इसके अलावा वहां पर जितने भी वृक्ष है, कोई पत्थर है निर्देशों के बावजूद उनके ऊपर बड़े-बड़े होर्डिंग्ज़ लगाए गए। पत्थरों पर लिखा गया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2016/1250/av/ag/1

श्री महेश्वर सिंह---------जारी

जब यह सब कुछ हो रहा था तो पर्यटन विभाग और प्रशासन कहां सो रहा था? मैं एक दिन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सामने सारी बात रख रहा हूं।

मुख्य मंत्री : पत्थरों पर कब लिखा गया था?

श्री महेश्वर सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं पिछले 15 वर्षों के दौरान समय-समय पर रही सभी सरकारों की बात कर रहा हूं। मैं यह आज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह कहना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार को एक आदेश दिया था कि विभाग को 80 बीघा जमीन उपलब्ध करवाएं ताकि इस प्रकार की गतिविधियां हो सकें। कौन सा कारण है कि इतनी जगह होते हुए भी सरकार या प्रशासन आज तक वह 80 या 90 बीघा जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाया? पिछले कल यहां पर परिवहन मंत्री जी ने एक अजीब सा उत्तर दे दिया जिसके बारे में हमें आज समाचार पत्रों में भी पढ़ने को मिला है। इन्होंने कहा था कि

सी0एन0जी0 से चलने वाली गाड़ी का सफल परीक्षण हो गया है। आपने परीक्षण किया और कहा कि सफल है। क्या यह सत्य नहीं है कि सरकार की एक रिकोग्नाईज्ड ऐजैंसी ने रिसर्च के आधार पर एक किताब निकाली है और उसमें यह लिखा है कि इन सी0एन0जी0 गाड़ियों से जो नैनो पार्टिकल्ज निकलते हैं वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा उससे कैंसर हो सकता है। मुझे लगता है कि आपने यह पढ़ा होगा। जब पढ़ा है तो आपने वहां यह स्टैंड क्यों नहीं लिया? दूसरा, मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जहां इतनी ठंड पड़ती है और चढ़ाई है तो क्या वहां पर सी0एन0जी0 गाड़ियां चलेगी या धक्के लगाने पड़ेंगे? क्या वह जम नहीं जायेगी या क्या यह सम्भव है? जो सम्भव नहीं था उस पर 25 लाख रुपये खर्च कर दिए और जो सम्भव है उस पर कोई खर्चा नहीं करते, यह कौन सा कारण है? यह सारी समस्या खड़ी है इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक-दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके

16.3.2016/1250/av/ag/2

इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। मैं भी इस बात का स्वागत करता हूं जो माननीय सदस्य ने कहा कि मैं इसके लिए अदालत में जाऊंगा। हम भी इनका सहयोग करेंगे लेकिन क्या बिना सरकार के सहयोग के यह सम्भव हो पायेगा? कौन सा कारण है कि आज वहां लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं? मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात नहीं थी जो इन्होंने कही है। वहां पर महिलाएं जो शायद और काम नहीं कर सकती थी वे वहां जाकर पर्यटकों को कुल्लू के पहरावे की ओर लुभाती थी जिसके लिए उनको पैसे मिलते थे। वहां पर्यटकों की गोद में अपनी पाली हुई भेड़ और साथ में खरगोश देकर उनकी फोटो खिंचवाती थी। कुछ बुजुर्ग लोग डंडे तैयार करके पर्यटकों को चलने के लिए देते थे। कौन सा कारण है कि कुफरी में तो घोड़े जो सकते हैं, क्या वहां पर पर्यावरण संतुलन नहीं बिगड़ता? क्या पर्यावरण संतुलन केवल रोहतांग में बिगड़ता है? वहां पर आज 500 घोड़ा मालिक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय सदस्य ने स्की-स्कूटर और पैरा ग्लाईडिंग की बात कही कि वे आज सारे-के-सारे बेरोजगार बैठे है और दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बारे में कोई जल्दी-से-जल्दी फैसला करे। इसके अतिरिक्त, सरकार/मुख्य मंत्री जी ने लोगों को जो आश्वासन दिया है उसके

लिए समय आ गया है कि इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पैटिशन दायर की जाए ताकि अपनी बात कहने का सबको अवसर मिले और न्याय मिले। यह रोहतांग दर्रा केवल कुल्लू वालों के लिए नहीं है बल्कि वहां देश और प्रदेश के सभी जिलों के कोने-कोने से आए हुए लोग अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। वहां 10 हजार नहीं बल्कि कम-से-कम 30000 लोग आज अपनी रोजी-रोटी से महरूम होने जा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं,

टीसी द्वारा जारी

16.03.2016/1255/TCV/AG/1

श्री महेश्वर सिंह-- जारी।

दूसरा, अन्त में एक बात कहूंगा, सरकार व प्रशासन के लिए ये बात संभव नहीं है और आगे भी संभव नहीं होगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी वहां पर स्थानीय महिला मंडल हैं, जो आपके पास भी आये थे, अन्य कोई संस्था है, ऐसा कोई एन0जी0ओ0 खड़ा कर दिया जाये और उनको तैयार किया जाये कि वह सफाई का ध्यान भी रखे व अतिथि देवो भवः जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसका भी ध्यान रखें। किसी भी टूरिस्ट के साथ कोई मिस-वीहेव न हो और जितने पैसे खाने के लगने चाहिए उससे अधिक पैसा कमाने की कोशिश न करें। ये कार्य कोई भी विभाग नहीं कर पाएगा। सफाई की जहां तक बात है, इस प्रकार का कठोर निर्णय तब आया जब सरकार ने पौलीथीन बैग्ज़ पर प्रतिबंध लगाया था लेकिन पौलीथीन जहां तहां फैंके गये, न पर्यटन विभाग ने और न ही प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान दिया कि गंदगी न फैले। यह सब उन बातों का परिणाम है जो ऐसा कठोर निर्णय आज हमको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर कोई एन0जी0ओ0 खड़ा कर दिया जाये और उनसे एफेडेविट लिया जाये। फिर नेश्नल ग्रीन ट्रिब्युनल से समय मांगा जाये और फिर

सारा सुधार हो सकेगा। इस तरह से यह एक जन आंदोलन बनेगा और वहां के लोग ये सारी चीजें अपने हाथ में लेंगे, सफाई का दायित्व और अतिथि देवो भवः परम्परा को भी निभाएं ताकि टूरिस्ट खुशी से आए और रोजी रोटी भी चल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आपका सरकार व भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

16.03.2016/1255/TCV/AG/2

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहेंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह ठाकुर और श्री महेश्वर सिंह जी ने सी0एन0जी0 और बी0एस0-IV की बार-बार चर्चा की और यह भी कहा कि 25 लाख रूपये खर्च दिए। मैं सिर्फ 2-3 बातें क्लीयर करना चाहूंगा बाकी माननीय मुख्य मंत्री जी इसका पूर्णतः जवाब दे रहे हैं। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है और न ही वेस्टेज़ थी। एन0जी0टी0 ने एक आदेश दिए थे कि आप सी0एन0जी0 को वहां जाकर ट्रायल करें। हमारे सीमित साधन होते हुए भी हम सी0एन0जी0 के ट्रायल के लिए सिलेंडर्ज़ में सी0एन0जी0 लेकर गये और वहां पर हमने बसें पहुंचाई क्योंकि बीच में कहीं भी सी0एन0जी0 स्टेशन नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहूंगा कि आप पिछली हिस्ट्री देख लें कि मथुरा से दिल्ली आने में सी0एन0जी0 को कितने वर्ष लगे थे और दिल्ली से पंजाब तक आने में कितने वर्ष लगे, वह भी आप देख लें। हमारी कनेक्टिविटी के लिए जो मदर स्टेशन हरोली/ऊना में बनेगा उससे आगे मनाली तक पहुंचाने में अगले कितने साल लगेंगे? सी0एन0जी0 की एक बात तो यह है कि उपलब्धता नहीं है। दूसरी, बात यह जो आपने

कहा कि उससे कैंसर हो सकता है। लेकिन यह कंट्राडिक्ट्री स्टेडी है, एक वैज्ञानिक बोलता है हो सकता है और दूसरा कहता है नहीं हो सकता है। तीसरी, बात जो आपने बी0एस0-IV की कही, यह भी पक्ष हमने बड़ी मजबूती के साथ एन0जी0टी0 में रखा हुआ है। अगर इलैक्टिक बस चलानी है तो यह एक बस डेढ़ -दो करोड़ रूपये की आती है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार माननीय सदन में स्टेट्मैंट दे चुके हैं कि जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनके लिए हर आदमी चिंतित है, हर आदमी चाहता है कि इसका समाधान हो। मगर इसका समाधान कानूनी ढंग से होगा उसके लिए सरकार अपना पक्ष बड़ी मजबूती के साथ कोर्ट में रखा है, बाकी माननीय मुख्य मंत्री बयान देकर बताएंगे।

16.03.2016/1255/TCV/AG/3

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, श्री जयराम ठाकुर और श्री महेश्वर सिंह ने नियम-62 के अंतर्गत उठाए गये ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव के बारे में जो अपने विचार रखे हैं, वह मैंने बड़े गौर से सुने हैं। निःसंदेह यह एक महत्वपूर्ण विषय है और जो प्रभावित लोग हैं वह उससे दुखी है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी।

16.03.2016/1300/RKS/AS/1

मुख्य मंत्री द्वारा जारी....

हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश की आम जनता भी इसके बारे में चिंतित है। अभी यह बताया गया कि यह मसला पिछले साल-डेढ़ साल से उठा है और प्रदेश सरकार ने इसमें कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया है। It is a political statement, not

based on facts. सच्चाई यह है कि जब यह मसला उठा, जब इसके बारे में चर्चा होने लगी तो सरकार ने उसी वक्त इसका संज्ञान लिया। हमने अपने स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए भरसक प्रयत्न किया। जब यह मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में गया, उस वक्त भी जोरदार तरीके से जो जनता का पक्ष है और जो सरकार का पक्ष है उसे वहां पर रखा। मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। चाहे वह ग्रीन ट्रिब्यूनल है या कोई अन्य न्यायालय है। हम उनका आदर करते हैं। मगर कई बार over enthusiasm भी अच्छा नहीं होता । रोहतांग तक ट्रैफिक जाने के बारे में जो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए हैं वे मेरी समझ के मुताबिक जरूरत से ज्यादा है। अगर रोहतांग अपने आप में एक एंड होता, माऊंट एवरेस्ट होता कि उससे आगे कुछ नहीं है तो कुछ और बात होती। रोहतांग एक दर्रा है और रोहतांग से आगे भी लोग रहते हैं। रोहतांग से आगे भी हिमाचल और दूसरे राज्य हैं। रोहतांग से आगे लाहौल है। रोहतांग से आगे लद्दाख को रास्ता जाता है। रोहतांग से पांगी होते हुए जम्मू-कश्मीर को भी रास्ता जाता है और रोहतांग होते हुए,कुन्जुम होते हुए स्पिति को रास्ता जाता है। ऐसा नहीं है कि Rohtang is end of a mountain terrain रोहतांग में कोई ग्लेशियर नहीं है। वहां सर्दियों में बर्फ पड़ती है जो गर्मियों में पिघल जाती है। जो ग्लेशियर है, वह बहुत दूर है। इसलिए मैं यह नहीं समझता कि रोहतांग के लिए कोई खतरा था। अगर फिर भी कोई खतरा महसूस करते हैं तो उसको बचाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे बहुत से अनावश्यक थे, उनकी आवश्यकता नहीं थी। रोहतांग में सदियों से लोगों के काफिले आते रहें हैं, जाते रहे हैं । it is part of old silk route from China. तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर संज्ञान हुआ है तो हो सकता है कि उसके पीछे कोई कारण रहे हो। रोहतांग के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कि इतनी गाड़ियां जा सकेंगी उसमें जो पुरानी गाड़ी होगी वह नहीं जा सकेगी इत्यादि कई किस्म के प्रतिबंध लगाए गए हैं। उसके बाद इलैक्ट्रिकल व्हीकल्ज की भी बात हुई।

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी

16.03.2016/1305/SLS-AS-1

माननीय मुख्य मंत्री ...जारी

मैं समझता हूं कि it is an overreaction in this case. जहां तक प्रश्न है कि सरकार ने इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की या ग्रीन ट्रिब्यूनल में हमने कोई कदम नहीं उठाए, इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने समय-समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और चीफ सैक्रेटरी की ओर से एक माकूल ऐफेडैविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाईल किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि - The affidavit was filed by the Chief Secretary in 2011 before the Hon'ble High Court in which the Committee recommended to restrict the number of vehicles and tourists to the Rohtang Pass. It also recommended establishment of check posts and barriers and tourists vehicles to be regulated.

Sir, Shri Govind Singh Thakur has raised many issues and said that Government has not pleaded the case properly. I place on the Table of the House a copy of the detailed affidavit filed by us in the Green Tribunal in June 2014. This is the affidavit, which I want to place on the Table of the House, which will form part of record and we will show that what action the Government has taken. State Government has already submitted relief and rehabilitation reports before National Green Tribunal. Now case is listed for 30th March, 2016 for orders. We will examine the orders and then take the best appropriate action not only in the interest of the State but also of the people.

..Continue in English by Smt. DC….

16/03/2016/1310/RG/DC/1

Chief Minister continues…..

We are concerned about the rights of the people; we are concerned about the livelihood of the people; and we are concerned with the difficulties which are being faced by the affected people. So I don't want to make a political game out of it. Government is concerned about it. We have taken

appropriate action. To say the Government has not properly pleaded the case before the Green Tribunal is wrong. Very eminent people were involved in it and Government had taken every possible steps in-line with the thinking of the people to safeguard their interests and if necessary then we will take this matter to the Supreme Court also. I want to say this. I don't evoke the emotions of the people. I don't want to politicize the entire issue. This is a serious matter affecting the livelihood of the people. I sincerely feel many of the steps ordered by the Hon'ble Green Tribunal with regard to the journey from Manali to Rohtang are totally unnecessary. In the past, I myself walked on this road when there was no vehicular traffic. This is an old road is coming from centuries and it has been the route which people took to go to Ladakh, Lahaul & Spiti and beyond to China. It is part of China route silk route. Therefore, Sir, it has stood the traffic of that time. Maybe, today there is more traffic. The tourists who go to Rohtang as an excursion once you go to Manali, it is not much to do there. So, for day or two they will stay in Manali; one or two days for Rohtang. Some who are more adventurous may go to Lahaul like that. So, tourism is spreading and everybody who come to Manali makes a point to go to Rohtang. It is an important destination and great tourist attraction

16/03/2016/1310/RG/DC/2

for people who come from outside. That is there. At the same time we have to preserve our environment also and have to keep the place clean. We must ensure that regulated traffic is there. So all things are there. But at the same time, I think the State Government by itself and the people at large are capable enough to look after our affairs. To see there is sanitation; to see there is no exploitation of the tourists by anybody, to see that there is no harm to the nature and environment, and to see there is no traffic jams, that

is administrative matters. So I assure you Sir, that will be done . I know Maddi. It is a small stopping place on way to Rohtang. It started with one or two shops Now we have more hotels and restaurants there.

Continued by Mrs. M.S….

16/03/2016/1315/MS/dc/1

अंग्रेजी के बाद मुख्य मंत्री महोदय-----

वहां रास्ते में कोई हाल्ट होना चाहिए जहां पर आदमी आराम कर सके, चाय पी सके, कोल्ड ड्रिंक पी सके और अगर जरूरी है तो खाना खा सके। यह जरूरी है कि जो मढ़ी है वह भी सुन्दर बने। वहां ऐसे भवन बनें which does not clash with the environment. It should be clean and very beautiful destination to everybody and that is so necessary, वहां लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उनको वहां से बाहर करना भी ठीक नहीं है। वहां पर ठीक तरह से उनके हट्स और रेस्टोरेंट्स बनें which merge with the environment और साफ-सुथरे हों और रिजनेबल प्राइसिज के ऊपर वे लोगों को खाना, चाय व दूसरी वस्तुएं दें। यह भी बीच में जरूरी है, It is part of tourism. इस बारे में सरकार पूरा ख्याल रखेगी और मैं सबसे यह कहना चाहता हूं कि this is not something which Himachal Government has done. It is something which Green Tribunal has put certain conditions before us creating such a situation. We have to respectfully go to them and put our case properly. And if we are not satisfied with their decision then we have option to go to the Hon'ble Supreme Court and where Government will be with the people. Government will take initiative in this matter. Thank you.

अध्यक्षः माननीय सदस्य गोविन्द जी यदि आप शॉर्ट में क्लेरिफिकेशन मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए। लम्बा भाषण न दें।

16/03/2016/1315/MS/dc/2

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी कहा कि

हमारी पॉलिटिकल स्टेटमैंट है, मैंने पहले ही कहा कि हमारी किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल स्टेटमैंट नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि अभी तक जो भी पक्ष आपने रखा है, वह ठीक है। जो अभी यहां पर कॉपी रखी, वह भी ठीक है। लेकिन लगता है कि अभी तक जो भी पक्ष रखा है वह सब माननीय न्यायालय में शायद पर्याप्त नहीं था। इसीलिए जो दो साल से यह मसला चला है उसके कारण लोग लगभग बेरोजगार हो गए हैं और उजड़ चुके हैं तथा अभी भी वे सब-के-सब बेकार बैठे हैं। एक बात तो यह है कि अभी उनके लिए हम जल्दी में क्या कर सकते हैं? दूसरे, मुझे लगता है कि प्रयास हुए हैं लेकिन यदि वे पर्याप्त नहीं थे, मुख्य मंत्री जी आप ही

ने एक बार यह बात कही थी कि देश के पहले जो 15-20 बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनमें से किसी को हम एन0जी0टी0 में हायर करके लगा सकते हैं, अगर लगता है कि हमसे कोई कमी रह गई है। हम लोगों को न्याय दिलाने के और अधिक प्रयास कर सकें, यह मेरी आपसे मांग भी है। इसके अलावा जिन विषयों में हमने कहा है कि हम उच्चतम न्यायालय में जा नहीं सकते हैं लेकिन टैक्सी युनियन और ढाबा युनियन वाले गए हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि न्यायालय में इस पक्ष को रखने के लिए अपनी सरकारी मशीनरी को प्रयत्न करना चाहिए। एक बात की वास्तविकता है कि जब चीफ सैक्रेटरी या सरकारी अधिकारी वहां जाते हैं तो ये लोग वहां पर बहस नहीं कर सकते हैं। जो बहुत बड़े वकील को लगाने की बात आपने भी कही थी तो ऐसा एडवोकेट यदि आप खड़ा करते हैं तो मुझे लगता है कि और अधिक मदद मिल सकती है। अभी जो निकट भविष्य में पेशी होने वाली है क्या आप उसके लिए ऐसा करेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मैंने सभा पटल पर एफेडेविट रखे हैं जो सरकार ने दिए हैं, उससे यह मालूम होगा कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। हमने वहां पर क्या केस रखा है। क्योंकि यह भी कहा जाता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया और सरकार ने केस ठीक से नहीं रखा। उस डाउट को रिमूव करने के लिए I put copy on the Table of the House. जहां तक मुकदमा चलेगा तो जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं वे बड़े अनुभवी वकील हैं। मगर जब भी आवश्यकता होगी तब हम दूसरे जो हमारे देश के टॉप लायर्ज हैं उनको भी इंगेज

करेंगे।

अध्यक्ष जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

16.03.2016/1320/जेएस/एजी/1

अध्यक्षः माननीय सदस्य, क्लैरिफिकेशन की कोई बात नहीं है। बहस सबने कर दी है। It is clarification only. You sought for clarification. The Hon'ble Chief Minister has already replied. अगर डिस्कशन ही शुरू करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। This will not meant for this.

अब बजट अनुमान 2016-17 के होंगे। अभी दोपहर के भाजन का समय हो गया है तो इसके बाद ही टेक-अप करेंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, क्या अब यह मामला खत्म हो गया है?

अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी अब यह मामला खत्म हो गया, क्योंकि आपने इसमें अपना ज़वाब दे दिया है।

अब इस माननीय सदन की बैठक अपराह्न 2.20 बजे तक दोपहर के भोजन के लिए स्थगित की जाती है।

16.03.2016/1425/SS-AS/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2:25 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर चर्चा

अध्यक्षः अब बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2016-17 पर चर्चा जारी रहेगी। सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि बहुत सारे सदस्य बोलने वाले हैं। करीब 15 सदस्य बोलने वाले हैं। इसमें समय का बड़ा ध्यान रखें और 10-10 या 15-15

मिनट बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जब आप लम्बा बोलते हैं तो फिर बाकी सदस्य नाराज़ हो जाते हैं। --(व्यवधान)-- जब मैं रिकॉर्डिंग बंद करवा दूंगा, तब तो आप मान जायेंगे, अगर आप दस मिनट से ज़्यादा बोले।

अब मैं ठाकुर गुलाब सिंह जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2016/1430/केएस/डीसी/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 8 मार्च को 2016-2017 का अनुमानित बजट इस माननीय सदन में पेश किया और अपने बारे में यहां पर यह बताने की कोशिश की कि मैं इस माननीय सदन में 19वां बजट पेश कर रहा हूं। जो 19वां बजट इन्होंने यहां पर पेश किया उसे अंग्रेजी में पढ़ा। 60 पन्नों का अंग्रेजी में इन्होंने भाषण पढ़ा और लगभग साढ़े तीन घण्टे भाषण पढ़ते हुए वे खड़े रहे। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने साढ़े तीन घण्टे लगाए। शेरो-शायरी की फुहारों के बीच में, मुहावरों के बीच में, हालांकि उन्हें शेरो-शायरी करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी क्योंकि शायद बजट में जो शेरो-शायरी थी, उसका होमवर्क वे नहीं कर पाए थे इसलिए उनको काफी समय लगा। हम बड़ी रुचि के साथ और बड़े ध्यानपूर्वक उनको सुन रहे थे। उस सारे बजट में ऐसा लगा और हम उसके पन्ने भी बदलते रहे, अंग्रेजी के भी और हिन्दी के भी, हिन्दी के पन्ने हमने ज्यादा बदले और अंग्रेजी के कम बदले । ऐसा लगा कि इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसमें जो पिछली सरकार की उपलब्धियां या योजनाएं थी, उनका केवल मात्र प्रारूप बदला, पैरे बदले, नाम बदले, उन्हें इस बजट में समायोजित करने की कोशिश की और पिछले दो वर्षों में भारत सरकार से प्रदेश सरकार को जो योजनाएं आ रही हैं, उसके तहत जो पैसा आ रहा है, उन सभी योजनाओं को नाम बदल कर मुख्य मंत्री योजना के नाम से या अन्य नाम से उनको इसमें समायोजित किया है। कोई बड़ी योजना या कोई बड़ा कार्यक्रम जो बजट भाषण यहां पर पेश किया गया है, उसमें कहीं नज़र नहीं आता। यह मेरा इस सरकार पर आरोप है। अगर आप 8 मार्च, 2016 का भाषण पढ़ें और जो माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जब हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और वहां बैठते थे,

जो भाषण उन्होंने 19 मार्च, 2012 को इस माननीय सदन में पेश किया था उसको अगर आप स्टडी करें और इस बजट को स्टडी करें तो इसमें कोई फर्क नज़र नहीं आता और यह भी विडम्बना है, इत्तेफाक है कि जो इन दोनों बजटों के रचयिता है, वे एक ही है। वही प्रिंसिपल सैक्रेटरी ,फाईनैंस है जो उस वक्त भी बजट तैयार करते थे और आज भी तैयार करते हैं। यह भी बड़ी विचित्र बात है कि जो 60 पन्नों का श्री वीरभद्र सिंह,

16.03.2016/1430/केएस/डीसी/2

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत के साथ, मैंने तो कहा भी कि हम दाद देते हैं, जो इन्होंने 60 पन्नों का भाषण अंग्रेजी में पढ़ा वही 60 पन्नों का भाषण प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने भी इस माननीय सदन में यहां पढ़ा है । यह एक समानता है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

16.3.2016/1435/av/dc/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर क्रमागत

इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें भी 60 पेज ही हैं। इस बार के बजट भाषण में शरो-शायरी तथा फरेजिज इत्यादि 15-16 हैं। मगर उस समय धूमल साहब ने इस मान्य सदन में जो शेरो-शायरी की है उसका जवाब शायद इस बजट बुक में नहीं है। इस मान्य सदन में 5200 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का आकार 22800 करोड़ रुपये का था और पिछले 4 सालों में उस 22800 करोड़ रुपये में से 17000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। अब 9800 करोड़ रुपये बचते थे। मेरा आरोप है कि इस सरकार ने जो 5200 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है यह बहुत कम पेश किया है। अब क्योंकि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं तो यह बजट 9800 करोड़ रुपये का होना चाहिए था। आपने भारत सरकार को 6000 करोड़ रुपये सरेंडर किए हैं। मेरा इस सरकार पर यह आरोप है और जब माननीय मुख्य मंत्री इस बजट का जवाब दें तो इस बात को बतायें कि यह 6000 करोड़ रुपये आप क्यों खर्च नहीं कर पाये। यहां पर मुख्य मंत्री जी तथा अन्य बैठे मंत्री गण भारत सरकार पर गाहे-बगाहे आरोप लगाते रहते हैं तथा इस बात का राग अलापते रहते हैं कि भारत सरकार से

फंडिंग नहीं हो रही है। मगर मुझे एक बात की खुशी भी हो रही है क्योंकि अब की बार जो आपने बजट पेश किया है उसमें आपने भारत सरकार और नीति आयोग का धन्यवाद किया है। आपने यह भी कहा है कि भारत सरकार से जो अब 90:10 के अनुपात में ग्रांट मिलनी है उसके लिए हम भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं। 14वें वित्तायोग से हिमाचल प्रदेश को 40625 करोड़ रुपये की रैवन्यू ग्रांट प्राप्त हुई है। 13वें वित्तायोग के समय जब केंद्र में यू0पी0ए0 सरकार थी तब हिमाचल प्रदेश को केवलमात्र 8888 करोड़ रुपये की रैवन्यू ग्रांट मिली थी। यह हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है और हम इसके लिए केंद्र में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आभारी हैं कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को 415 करोड़ रुपये हायर बजट की ऐलोकेशन की है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इससे पहले हमें कभी भी इतनी ग्रांट नहीं मिली। जो यहां पर हमें बजट बुक दी गई है या जो मुख्य मंत्री

16.3.2016/1435/av/dc/2

जी ने बजट पेश किया है अगर आप उसको माइन्युटली देखें तो आपने हर योजना में बहुत कम पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप अनप्रोडक्टिव खर्चों पर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। आपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इत्यादि की बड़ी लम्बी फौज खड़ी कर रखी है। सरकार ने मंत्रियों और चेयरमैन्ज को लग्ज़री गाड़ियां खरीद कर दे रखी है। आप इस प्रकार का व्यर्थ का खर्चा क्यों कर रहे हैं? इस खर्चे को कर्टेल करो। अनप्रोडक्टिव खर्चे बंद होने चाहिए। भारत सरकार से आपको इतना ज्यादा पैसा इसलिए नहीं मिला कि आप इसको विकास के सिवाय दूसरे कार्यों में खर्च करें।

टीसी द्वारा जारी--

16.03.2016/1440/TCV/AG/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर-- जारी।

मेरा इस सरकार पर आरोप है और साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उन्होंने यहां अपना जो बज़ट भाषण पढ़ा उसके पेज नंबर 3 के पैरा नंबर-5

में आपकी जो 3 साल की उपलब्धियां हैं उनको दर्शाया गया है। सुनिए इस पैरे में क्या लिखा है, "अध्यक्ष महोदय, आईए हम कुछ वर्ष पूर्व का स्मरण करें जब प्रदेश में अलग विचारधारा वाली सरकारें आस्तित्व में आई। परन्तु तब न तो परस्पर वैमनस्य था और न ही दुर्भावना। तब एक दूसरे के साथ स्वस्थ्य विपक्ष व पारपरिक सम्मान था। तदोपरान्त मेरे विरूद्ध आधारहीन और झूठे आपराधिक मामले बनाये गये। बेशक कोई भी आधारहीन मामला न्यायालय समीक्षा में टिक नहीं पाया तथा मैं हर बार निर्दोश साबित हुआ। अभी भी कुछ लोग केन्द्रीय एजेन्सियों का दुरूपयोग कर मुझे उत्पीडि़त कर रहे हैं"। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्या यह उपलब्धियों का ब्यौरा है? यह बज़ट बुक में हैं। मैं इस मान्य सदन में अब से नहीं 30 वर्षों से हूं। 9 बज़ट भाषण तो माननीय मुख्य मंत्री जी के सुन लिए हैं और 10 प्रो0 प्रेम कुमार धूमल की तरफ से सुने हैं। आदरणीय शांता कुमार जी के 6-7 बजट भाषण सुने और ठाकुर राम लाल जी के बज़ट भाषण भी सुने हैं। इस तरह से लगभग 30 बज़ट भाषण यहां पेश हुए हैं लेकिन इस प्रकार की बातें बज़ट भाषण में लाएंगे, जो व्यक्तिगत है और बज़ट से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। बज़ट तो किसी स्टेट की सालाना उसकी क्या आमदनी है, क्या उसका एक्पेंडिचर है,क्या खर्चे करने जा रही है? उसका ब्योरा होता है और उस पर डिसक्शन होती है। लेकिन इस प्रकार की बातें अगर बज़ट भाषण में लाएंगे तो ये आईंदा आने वाले समय के लिए अच्छी नींव नहीं रख रहे हैं। मेरा यह अनुरोध रहेगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि इस प्रकार का जिन लोगों ने यह बज़ट भाषण बनाया/समायोजित किया और इन्होंने यह पैरा इसमें डाल दिया। पता नहीं

16.03.2016/1440/TCV/AG/2

यह किस नजरिये से किया होगा या किसी को खुश करने के लिए किया होगा। लेकिन यह अच्छी परम्परा नहीं डाली गई है। मैं इसके खिलाफ़ हूं और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बहुत सारी बातों की ओर न जाता हुआ केवल 2-3 बातों के बारे कहना चाहूंगा। एक तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय का हम आभार प्रकट करना चाहूंगा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी किया है, जो विधायक निधि है उसको बढ़ाया गया है, एक करोड़ रूपया इस विधायक निधि में किया गया है लेकिन मैं समझता हूं और सभी माननीय विधायक भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जो

पैसा विकास के लिए हम किसी भी योजना के मद् में देते हैं मसलन हम किसी स्कूल के भवन के निर्माण के लिए एक लाख रूपये देते हैं और जब दूसरी बार जाते हैं तो वह बोलते हैं कि इसमें तो लगभग डेढ़ लाख का खर्चा हो गया है, आप इसके लिए और 50 हजार रूपया दें। जब हम अपनी चिट्ठी 50 हजार की जिलाधीश को लिखते हैं तो उसमें वह 30 हजार रूपया ही देते हैं और 20 हजार रूपया काट देते हैं, ये कहते हैं कि मैंटेनेंस के लिए 30 परसेंट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा---- जारी

16.03.2016/1445/RKS/AG/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर द्वारा जारी....

30 हजार देने के बाद जब दूसरी या तीसरी बार फिर हम वहां जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी तक तो दरवाजे-खिड़कियां भी नहीं लगी है। जो आपने पैसा दिया था उससे कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ प्लानिंग मिनिस्टर भी रहा हूं, आप प्लानिंग डिपार्टमेंट को कहें कि इन सारे रूल्ज को अमेंड करें। रिपयेर के,कम्पलीशन के ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो कम्पलीट ही नहीं होते हैं। सरकार की तरफ से, कई मदों की तरफ से पैसा आता है परन्तु वह कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। जब विधायक अपने क्षेत्र में जाता है तो लोग पैसे की मांग के लिए वहां खड़े हो जाते हैं। इसलिए जो नियमों में 30% राइडर बजट को खर्च करने के लिए लगाया गया है उसको हटाया जाए। एम.एल.ए. की जो विधायक निधि है उसे चाहे किसी रिपेयर के लिए दें, किसी कम्पलीशन के लिए दें या जो कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं उनके लिए दें उसके लिए समुचित छूट नियमों में होनी चाहिए। बजट भाषण में कोई बड़ी योजनाएं तो देखने को नहीं मिली परन्तु जो कृषकों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए 'मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना' के नाम से जो नई योजना शुरू की है इस योजना के अंतर्गत किसान अपने खेतों में बार्बड वायर या फेंसिंग वगैरा लगा सकता है। इस योजना में 60 % सहायता सरकार करेगी। लेकिन जो 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है वह बहुत कम है। फेंसिंग के लिए जो तारें प्रयोग की जाएगी उनमें बिजली का करंट या सौर ऊर्जा करंट जोड़ने की जो बात कही है मेरे अनुसार यह बहुत घातक होगा। इससे

इन्सानी जाल माल का भी नुकसान हो सकता है। इस स्कीम के एवज़ में कहीं ऐसा न हो कि हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों का अवैध शिकार ज्यादा हो जाए। जो पोचर है जहां से जंगली जानवर घुसते हैं वहां बिजली की तारें लगा देते हैं और निहत्थे जानवर वहां मारे जाते हैं। जब आप इस चीज का बजट में प्रावधान कर देंगे तो कहीं ऐसा न हो कि जो पोचर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं उनके लिए यह पोचर संरक्षण योजना साबित हो जाए। एक किस्म से उनको यह लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा और कोई भी 'खैर' बच नहीं पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि

16.03.2016/1445/RKS/AG/2

जो करंट की बात है उसको इससे हटाया जाए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट यहां पेश किया है उस बजट में सड़कों के निर्माण के लिए पैसे का प्रावधान तो किया है लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं किया गया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय हमने सैद्धांतिक तौर पर एक फैसला लिया था कि सड़के हमारी जीवन रेखाएं हैं और जो बहुत दूर के इलाके हैं इनकी दूरियां कम की जाएं। सुरंगों का निर्माण किया जाए। सुरंगों का निर्माण करने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2012-13 में पैसा का प्रावधान भी किया था और सैद्धांतिक तौर पर उस चीज को माना भी था। उसके हिसाब से 3 महत्वपूर्ण सुरंगों को बनाने का फैसला लिया था। जिसमें कुल्लू और मण्डी को जोड़ने वाली भूभुजोत सड़क थी । धनेटा -बगाणा सड़क थी। होली- उतराला सड़क थी।

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी

16.03.2016/1450/SLS-AS-1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर ...जारी

इनके लिए पैसे का प्रावधान किया गया, कंसलटैंट सर्विस को हायर किया गया और इनकी इनवैस्टिगेशन का कार्य भी लगभग पूरा हो गया था। जब हमारी सरकार चली गई, उसके बाद 3 सालों तक आपकी सरकार का बजट यहां पर पेश होता रहा। उन बजटों में आपने इन 3 सुरंगों तथा 2 अन्य सुरंगों के बारे में ज़िक्र तक किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब मुख्य मंत्री महोदय ने जो चौथे साल का बजट पेश किया है, उसमें भी टनल और सुरंगों के निर्माण की बात गायब है, भले ही वह खड़ापत्थर सुरंग की बात हो या धनेटा-बंगाणा की बात हो। इन सुरंगों से फासले कम होने हैं और पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं होगा जबकि आने-जाने की दूरी अवश्य कम होगी। अगर भुभुजोत सुरंग बनती है तो कुल्लू-मण्डी का फासला 70 किलोमीटर कम होगा। अगर उतराला-हरोली की टनल बनती है तो बैजनाथ से हरोली का 200 किलोमीटर फासला कम होगा। धनेटा-बंगाणा सुरंग बनती है तो 10 किलोमीटर फासला कम होगा। अगर आनी के लिए जलोड़ी पास सुरंग बनती है तो 20-25 किलोमीटर का फासला कम होगा। आपने बजट में इनका ज़िक्र नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसे रिवियु करें और इसको बजट में रखें।

अध्यक्षः माननीय ठाकुर जी, आप और कितने समय के लिए बोलेंगे?

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सड़कों की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं है। अगर जोगिन्द्रनगर से चलें तो शिमला पहुंचने में 7 घंटे लग जाते हैं। एक दिन मेरे दोस्त आदरणीय श्री किशोरी लाल जी मेरे साथ-साथ जा रहे थे। इनकी गाड़ी घाघस पुल से गायब हो गई। मैंने फोन पर पूछा कि कहां चले गए; हमने सुंदरनगर या मण्डी में जाकर इकट्ठे चाय लेनी है? इन्होंने कहा कि मैं हमीरपुर होकर चला गया हूं। इस समय प्रदेश में सड़कें इतनी खराब हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है।

16.03.2016/1450/SLS-AS-2

ओप्टिकल फाइबर ने तो सारे प्रदेश में सड़कों पर तबाही मचाई है। इसके अलावा अभी हाल ही में अनटाइमली वारिस से भी सड़कों का हाल खराब हो चुका है। चाहिए यह था कि मुख्य मंत्री महोदय बजट भाषण में 200-250 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि इसके

लिए अलग से घोषित करते और विभाग को दिशा-निर्देश देते कि मैं महीने के अंदर प्रदेश की सारी सड़कों को सही रूप में देखना चाहता हूं। हालांकि इन्होंने मण्डी में कहा कि सड़कों का बुरा हाल है। अगर यह ठीक नहीं होती हैं तो एस.ई. को एक्स.ई.एन. और एक्स.ई.एन. को एस.डी.ओ. बना देंगे। मेरे ख़याल में लोक निर्माण विभाग पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। अगर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पूछें तो वह कहते हैं कि हम तो सड़क रिपेयर करने या पैच वर्क करने के लिए तैयार हैं; ऐन्वल सर्फेसिंग करने के लिए तैयार हैं लेकिन बजट का कोई प्रावधान ही नहीं है। यह जो कमियां हैं, अध्यक्ष महोदय, इन्हें मैं आपके माध्यम से सरकार तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि सड़कों की जो खस्ता हालत है, आप इसे सुधारेंगे। बाकी तो यह रूटीन का बजट है। जो योजनाएं पहले प्रोफ़ैसर प्रेम कुमार धूमल जी के समय में थीं वही योजनाएं आपने शुरू की हैं। यह तो वही बात है जैसे बॉल कैरी फॉरवर्ड की; आगे-से-आगे, आगे-से-आगे। मैं समझता हूं कि यह इसी प्रकार की बात है।

क्योंकि इस बजट में कोई नई योजना या नई दिशा देने वाली बात शामिल नहीं है, इसलिए मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जो सुझाव अपनी चर्चा में दिए हैं, मुझे आशा है कि उन सुझावों को आप बजट में शामिल करेंगे जिससे सबको लाभ होगा।\इन्हीं शब्दों क साथ, अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : मैं फिर से सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आप सभी समय का अवश्य ध्यान रखें क्योंकि अभी बहुत से सदस्यों ने बोलना है। अभी 15 माननीय सदस्य बोलने के लिए हैं। क्योंकि बहुत कुछ तो बोला जा चुका है इसलिए आप 10 मिनट में ही अपनी चर्चा में सब-कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय जारी ...श्री गर्ग जी

16/03/2016/1455/RG/AS/1

अध्यक्ष महोदय------क्रमागत

अब माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री सोहन लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सोहन लाल) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 मार्च, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में जो बजट पेश किया, उस पर यहां चर्चा चल रही है और मैं भी इसमें अपने आपको शामिल करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने प्रदेश की उन्नति और प्रगति के लिए एक सन्तुलित बजट यहां पेश किया। इस बजट में वैसे तो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, लेकिन विशेष फोकस किसानों, कर्मचारियों, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य पर इस बजट में ज्यादा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्रदेश के लिए कोई नई योजनाएं शुरू नहीं की गई हैं, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। इसी सदन में कई बार किसानों की आज जो दशा है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है। इसी से संबंधित माननीय मुख्य मत्री जी ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम 'मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना' है। इस योजना में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे निश्चित तौर तौर जो इस सदन की चिन्ता थी कि किसानों की हालत जो दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है उसे कैसे सुधारा जाए, तो मैं समझता हूं कि इसमें यह एक अहम् योजना सिद्ध होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में भी बातें उठती रही हैं, उस पर चर्चा होती रहीं। कल भी कोई सदस्य कह रहे थे कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए। इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक 'मुख्य मंत्री शिक्षक सम्मान योजना' शुरू की है। मैं समझता हूं कि इसके लागू होने से निश्चित तौर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार आएंगे। जो शिक्षक अपने स्कूलों में अच्छे परिणाम देंगे, उनको सम्मान देंगे और इस योजना में कहा गया है कि उन्हें सर्विस में एक वर्ष की ऐक्सटेंशन दी जाएगी। इसलिए निश्चित तौर से इसमें सुधार की बहुत आशाएं की जा सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम 'मुख्य मंत्री आदर्श विद्यालय योजना' है। इस योजना में अभी 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। तो यह भी शिक्षा के सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम है।

16/03/2016/1455/RG/AS/2

अध्यक्ष महोदय, अभी पीछे जो हमारी आवास योजनाएं थीं उनमें केवल आई.आर.डी.पी. के लोगों को ही शामिल किया जा रहा था और केन्द्र सरकार की तरफ से ऐसे दिशा-निर्देश आए जिसमें सिर्फ अनुसूचित जाति को ही मकान मिल रहे थे। सामान्य जाति के लोगों को आवास सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। मुख्य मंत्री महोदय इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों को भी इसमें शामिल किया है और अब उनको भी इस योजना से लाभ पहुंचेगा। इसलिए प्रदेश सरकार ने यह भी एक नई योजना शुरू की है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे, प्रदेश और पूरे देश के लिए यह एक चिन्ता का विषय है कि हमारा लिंग अनुपात घट रहा है इसको भी सुधारने के लिए एक नई योजना इनीशियेटिव के तौर पर पंचायतों में लागू होनी है जिसका नाम 'पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार' है। इस योजना को भी एक दूरदर्शी सोच के चलते शुरू किया गया है और इसका प्रारूप यहां दिया गया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में एक 'मुख्यमंत्री सड़क योजना' शुरू की है। इसमें कहा गया है कि कुछ माइल्ज़ जो कनैक्टिविटी के लिए रह गए हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा।

एम.एस. द्वारा जारी

16/03/2016/1500/MS/AS/1

श्री सोहन लाल जारी (मुख्य संसदीय सचिव)जारी---------

यदि हम अपने-अपने क्षेत्रों में देखें तो कई ऐसी सड़कें बनी हैं जो मात्र एक-एक, दो-दो या तीन-तीन किलोमीटर बनने से ही उस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा कनैक्टिविटी दे पाई हैं। इस योजना को इसी आश्य से शुरू किया है। यह बहुत ही अच्छी योजना शुरू हुई हैं। इसी तरह की कई अन्य योजनाएं भी शुरू हुई हैं। ऐसी 12-13 योजनाएं शुरू हुई हैं जिनमें "हिमाचल युनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन योजना" को भी शुरू किया गया है। ऐसी

बहुत सारी योजनाएं हैं जो नई योजनाएं हैं। जिनके लिए अभी नई सोच बनाई गई है और मुख्य मंत्री जी ने उनको शुरू किया है। हमारे विपक्ष के मित्र कहते हैं कि बजट में कुछ नया है ही नहीं। मुझे लगता है कि इन्होंने न तो बजट भाषण को सुना है और न ही पढ़ा है क्योंकि इन्होंने सिर्फ इसकी आलोचना ही करनी थी। अभी-अभी एक माननीय सदस्य जो 21 साल से इस सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहते हैं कि इसमें नया कुछ नहीं है। जबकि हमें तो इसमें सभी बातें नई लगी हैं और प्रदेश की जनता को भी इन नई योजनाओं से निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने जो अपने चुनावी वायदे किए थे हालांकि अभी हमारे पास दो साल का और वक्त है लेकिन हमने वे चुनावी वायदे तीन साल में ही पूरे कर लिए हैं। जैसे हमारी सामाजिक सुरक्षा पैंशन की योजना है तो इसमें हमने 600/-रुपये देने का वायदा किया था और अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 650/-रुपये किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने एक बड़ी ही संवेदनशील दृष्टि से जो 45 साल से कम उम्र की विधवाएं हैं उनकी पैंशन को 1200/-रुपये किया है। यह बहुत ही काबिले-तारीफे बात है। इस सदन में यह भी कहा गया कि पैंशन से क्या होता है। पैंशन के रूप में 500/-रुपये या 600/-रुपये देकर क्या होता है। लेकिन जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे सिर्फ पैंशन की ही मांग करते हैं। उनके लिए यह बहुत राहत की बात है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छी योजना मुख्य मंत्री जी ने दी है। इसके साथ दिहाड़ीदार मजदूरों की दिहाड़ी पहले 150/-रुपये से 180/-रुपये की और अब इसको 200/-रुपये कर दिया है। यह भी हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था। इसी तरह से

16/03/2016/1500/MS/AS/2

होमगाड्र्ज का दैनिक भत्ता 280/-रुपये से 350/-रुपये किया है। यह भी चुनावी वायदे के अनुसार हमने काम किया है। दूसरी तरफ यदि चुनावी वायदों की ही बात करनी है तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि अभी दो साल पहले आपकी पार्टी ने देश और प्रदेश की जनता से वायदा किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो अच्छे दिनों का सपना लोगों को दिखाया गया जोकि अब कहीं भी पूरा होते नहीं दिख रहा है।

जहां तक महंगाई की बात है। महंगाई आज उस दौर से तीन गुणा ज्यादा बढ़ी है

और जो अच्छे दिन का सपना था, मैं तो इसको दूसरे शब्दों में कहूंगा कि आम आदमी अब कह रहा है कि "कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन"। -(व्यवधान)- ये आप अपनी तर्ज़ में गा सकते हैं लेकिन हकीकत यह है कि आज आम आदमी बोल रहा है कि अच्छे दिन तो आए ही नहीं परन्तु यदि हमारे पुराने दिन लौट आएं तो बहुत बेहतर होगा।

इसके साथ-साथ जो यहां कालाधन लाने की बात थी, वह भी बात बनकर रह गई और जितने भी इनके चुनावी वायदे थे, वे पूरे नहीं हुए हैं। मैं वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो भी चुनावी वायदे किए थे, उन पर काम किया है और उनको पूरा करने का प्रयत्न किया है तथा हमने काफी हद तक उनको पूरा किया भी है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदे तो जुमले बनकर रह गए हैं।

इसी तरह से अभी प्रदेश में 13,000 विभिन्न कैटेगरीज के पदों को भरने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है और इसमें वे सारी कैटेगरीज हैं, जिनकी जरूरत आज प्रदेश में है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---------

16.03.2016/1505/जेएस/डीसी/1

श्री सोहन लाल (मुख्य संसदीय सचिव):-----जारी----

चाहे शिक्षकों की है, कामगारों की है। खास कर मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी को जिन्होंने 1120 पटवारियों के पदों को भरने का निर्णय लिया है। यह एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे लोगों को सबसे पहले काम पड़ता है, वह पटवारी के पास पड़ता है। आपके कार्यकाल में जो लगातार आपने पटवारियों के पद नहीं भरें उसका नतीजा है कि आज भी हमारे बहुत से ऐसे पटवार सर्कल है, जहां पटवारी नहीं है। इसके चलते, अब नये पटवारियों के 1120 पद भरे जाएंगे, मैं समझता हूं कि इससे हमारे ग्रामीण लोगों को काफी निज़ात मिलेगी। हमारी सरकार ने एक हजार से ज्यादा शिक्षा संस्थान अपग्रेड किए। 28 नये कॉलेज प्रदेश में खोलें। हालांकि इन कॉलेजों को या इन शिक्षा संस्थानों को उस तरफ से अपग्रेड करने के लिए कोई मुबारकवाद प्रदेश सरकार को नहीं मिली, अलबत्ता आलोचना ही मिली।

आज भी प्रदेश की जो हमारी भोगौलिक स्थिति है उसके अनुसार अभी भी हमारे प्रदेश में दूर-दूर तक बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए दूरी तय करनी पड़ती है। हमारे पास आए दिन शिक्षा संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए रिक्वैस्ट आती हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदय का कि तीन दिन पहले मेरी एक बैकवर्ड पंचायत बंदली है उसका एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने आया और उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में प्लस-2 स्कूल 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है वहां उसे अपग्रेड करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको अपग्रेड करने का आश्वासन दिया है। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके साथ ही जो प्रदेश ने 28 डिग्री कॉलेज प्रदेश में खोले,मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा हमारी जो बेटियां हैं उनको इन कॉलेजिज़ के खुलने से नज़दीकी स्थान पर शिक्षा प्रदान हो रही है। इस बात का सबूत है कि ये जो कॉलेजिज़ खुले हैं यहां 70 प्रतिशत जो एनरोलमैंट है वह लड़कियों की है। इससे सिद्ध होता है कि इन कॉलेजिज़ की क्या उपयोगिता है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ

16.03.2016/1505/जेएस/डीसी/2

हमारी सरकार ने युवाओं के लिए रोज़गार सृजित करने हेतु टैक्निकल ऐजुकेशन पर बहुत ज़ोर दिया है। हमारी सरकार ने अभी 28 नए आई0टी0आई0 संस्थान प्रदेश में खोले हैं जिसके चलते अब हर विधान सभा क्षेत्र में एक-एक आई.टी.आई. हो गया है और हर जिला में एक-एक पॉलिटैक्निक कॉलेज हो गया है। इस करके हमारे युवा वर्ग अब टैक्निकल ऐजुकेशन के माध्यम से रोजगार पाने के लिए सक्षम होगा। बेरोज़गारी दूर करने के लिए यह एक अहम् कदम प्रदेश सरकार की तरफ से होगा। अभी हमारे प्रदेश में एक नया इन्स्टिच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, बद्दी में खुला है। एक ट्रेनिंग इन्स्टिच्यूट फॉर वुमैन, रीज़नल वोकेशन सेन्टर शिमला में खुला है। यह भी इसी सन्दर्भ में एक कदम है। यहां उस तरफ से काफी बातें की गई कि प्रदेश सरकार भेदभाव से काम करती है। हमारी कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारें जब-जब प्रदेश में आई हैं, चाहे डॉ0 वाई0एस0 परमार के नेतृत्व वाली सरकार हो, चाहे ठाकुर राम लाल जी की सरकार थी और चाहे वर्तमान मुख्य मंत्री जी जिनको छठी बार इस प्रदेश को नेतृत्व मिला है कभी प्रदेश के किसी भी हिस्से से भेदभाव नहीं

हुआ। हमें अक्सर मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैं समग्र हिमाचल प्रदेश का विकास चाहता हूं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

16.03.2016/1510/SS-DC/1

श्री सोहन लाल, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

और वे इस पर काम भी करते हैं। इसका सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में पीछे नये इंस्टिट्यूटस आए। तीन मेडिकल कॉलेजिज़ आए। चम्बा, हमीरपुर और सिरमौर में आए। वे इस बात का सबूत हैं। फैशन टैक्नॉलोजी का इंस्टिट्यूट कांगड़ा में आया। होटल मैनेजमैंट का इंस्टिट्यूट हमीरपुर में आया। आई0आई0टी0 मंडी में आया। यह इस बात का सबूत है कि हिमाचल सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रदेश में नहीं कर रही है। आई0आई0एम0, सिरमौर खुला, यह इस बात का सबूत है कि कोई भेदभाव नहीं हुआ। यह आपकी तरफ से हमें देखने को नहीं मिला। बल्कि आपकी तरफ से तो भेदभाव सीधा प्रकट होता है। यदि आज प्रदेश में क्षेत्रवाद का ज़हर है तो इसको बी0जे0पी0 ने फैलाया है। इसको फैलाया ही नहीं बल्कि इसके ऊपर काम भी किया। जहां एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में था और दूसरा टांडा में था, वहां हमारी सरकार जब 2007 में सत्ता में थी तो तीसरा मेडिकल कॉलेज प्रदेश के मध्य क्षेत्र मंडी में दिया। लेकिन आपकी सरकार के आते ही आपने उस मेडिकल कॉलेज की नोटिफिकेशन रद्द की थी। यह इस बात का सबूत है कि आप क्षेत्रवाद की बात करते हैं। यह कांग्रेस पार्टी नहीं करती। हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने निर्णय लिया है कि जो मंडी में ई0एस0आई0 का हॉस्पिटल है उसे सरकार अपने सामर्थ्य से चलायेगी। इसके लिए हमें सरकार का धन्यवाद करना है।

अभी जो यहां प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने प्रदेश में 1231 बसों का फ्लीट ऐड किया है और 69 बसें अभी उसमें और शामिल होने जा रही हैं। इससे हमारे प्रदेश के लोगों को यातायात की सुविधा ठीक से मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर बातें की गई कि वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही

है मैं यह बता रहा हूं कि हमने क्या-क्या किया है और उसके आंकड़ें यहां दिये हैं। आपने कहा कि नई स्कीमें नहीं दी। हमारी सरकार ने नयी योजनाएं दी हैं जब ये लागू होंगी तो निश्चित तौर से प्रदेश की प्रगति होगी। मुख्य मंत्री महोदय ने जिन सीमित साधनों से यह संतुलित बजट पेश किया है इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अभी यहां बात की गई कि सरकार को सैंटर से मदद मिल रही है। अभी

16.03.2016/1510/SS-DC/2

इन दो सालों से जब से एन0डी0ए0 की सरकार दिल्ली में बनी है प्रदेश में अभी तक कोई स्कीम शुरू नहीं हुई। बल्कि जिन स्कीम्ज़ के लिए पैसा भी आ रहा था उस पर भी कट लगा है। इसका उदाहरण मनरेगा है। जिसके ऊपर सीधा 50 परसैंट कट लगा है जो प्रदेश को मनरेगा में नहीं मिला। ---(व्यवधान)--- अभी पीछे का ही बजट आ जायेगा तो ठीक है जैसा कि मंत्री महोदय कह रहे हैं।

सोलर लाइट्स की एक स्कीम थी, वह एन0डी0ए0 सरकार ने बंद कर दी है। जवाहर लाल सौर ऊर्जा मिशन को बंद कर दिया गया है। हम तो दो सालों की बात कर रहे हैं। किसानों को जो सपना दिखाया गया वह 2022 कर दिया गया है। मुख्य मंत्री महोदय ने जो यहां पर अपने सीमित साधनों में बजट पेश किया है वह इनका हौंसला दिखाता है और इनकी सोच दिखलाता है। यहां पर शेर की बात कही गई। यहां कहा गया कि शेर ठीक से नहीं पढ़े या उनको गलत ढंग से इंटरप्रैट किया गया,

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2016/1515/केएस/एजी/1

श्री सोहन लाल (मुख्य संसदीय सचिव) जारी----

मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं , जो मुख्य मंत्री जी ने किया हैः

मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है,

हौसला हो तो फासला क्या है।

यह हौसलों की उड़ान है। जो मुख्य मंत्री जी ने यहां पर बजट पेश किया है यह इनके हौसलों की उड़ान है और इससे निश्चित तौर पर प्रदेश तरक्की करेगा, उन्नती करेगा इसके लिए हम मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं बजट का समर्थन करता हूं।

16.03.2016/1515/केएस/एजी/2

अध्यक्षः अब श्री जय राम ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016-17 का जो बजट माननीय मुख्य मंत्री ने इस माह की 8 तारीख को माननीय सदन में प्रस्तुत किया, मैं भी उस पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, बजट भाषण के पहले ही पन्ने पर जहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि यह उनका 19वां बजट है और मुझे लगता है कि यह भी सच्चाई है कि आज तक के जितने भी मुख्य मंत्री रहे हैं सबसे ज्यादा बार इस माननीय सदन में बजट प्रस्तुत करने का अवसर माननीय मुख्य मंत्री जी को ही मिला है लेकिन यह भी संयोग है कि मैं इस माननीय सदन का सदस्य 1998 में बना था । मैं गिन रहा था कि 1998 के बाद आज तक जितने बजट हुए वे भी 19 हुए हैं। हमें भी यह सौभाग्य है कि लगातार इस माननीय सदन में 19 बजट भाषण में भाग लेने का हमें अवसर मिला है। जो बजट प्रस्तुत हुए उनको सुनने का मौका मिला है। मैं थोड़ा और इतिहास में जाने की कोशिश कर रहा था। जब से हिमाचल प्रदेश की विधान सभा अस्तित्व में आई है, मैंने यह जानने की कोशिश की कि आज तक इस माननीय सदन में कितने टोटल बजट प्रस्तुत हुए हैं। मुझे विधान सभा सचिवालय के माध्यम से जानकारी मिली है कि अभी तक 51 बजट प्रस्तुत हुए हैं। 51 बजट में से मात्र 16 बजट भारतीय जनता पार्टी ने, जिनमें आदरणीय धूमल जी ने 10 बजट पेश किए क्योंकि दो कार्यकाल ये मुख्य मंत्री रहे, श्रीमान शान्ता कुमार जी ने 6 बजट प्रस्तुत किए हैं । बाकी के 35 बजट कांग्रेस की सरकार ने प्रस्तुत किए। जब आपको इतना लम्बा अवसर इस प्रदेश की सत्ता में रहकर काम करने का मिला तो एक उम्मीद की जा सकती है कि परिस्थिति अलग होनी चाहिए थी। आज भी हमें इस बात का दुख होता है कि लम्बे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा लेकिन आज भी जो बच्चा हिमाचल प्रदेश की धरती पर

जन्म लेता है, वह लगभग 50 हजार के कर्जे के साथ पैदा हो रहा है। यह स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन यह सच्चाई है और जो परिस्थितियां है, मुझे आशंका है कि आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। हम ऋण पर आधारित है ।

16.03.2016/1515/केएस/एजी/3

अध्यक्ष महोदय, जब हम सत्ता पक्ष में थे और उस तरफ से जब हम बात करते थे तो यहां से हमारे मित्र जो आजकल सत्ता में हैं खड़े हो कर कहते थे कि यू.पी.ए. सरकार की वजह से हैं। अगर यू.पी.ए. की सरकार नहीं चाहती तो हम दो कदम नहीं चल सकते लेकिन अगर आज हम इसी बात को कहें कि केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार है और अगर वह आपको मदद न करें, आर्थिक दृष्टि से दिल खोल कर समर्थन और सहयोग न करें, क्या आप चलने की स्थिति में हैं? यहां पर जिक्र होता था, हर वक्ता यहां से भाषण देता था और नेहरू जी से शुरू करते थे, इंदिरा गांधी का जिक्र आता था, राहुल गांधी का जिक्र आता था, राजीव गांधी जी का जिक्र आता था।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2016/1520/av/ag/1

श्री जय राम ठाकुर क्रमागत

मनमोहन सिंह जी, जो उस समय प्रधान मंत्री थे उनका जिक्र अगर कहीं गाहे-बगाहे हो गया तो ठीक है वरना उनका जिक्र कहीं नहीं आता था मगर आप बाकी लोगों का धन्यवाद जरूर करते थे। (---व्यवधान---) नरसिम्हा राव जी का तो जिक्र ही नहीं होता था। आपकी सरकार ने जो कुछ अच्छे कदम उठाये हैं मैं उसके लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। इस संस्था में चुने हुए विधायकों को सशक्त करने की दृष्टि से जो आपने विधायक निधि को 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं एक और धन्यवाद करता हूं, पहले मैं धन्यवाद वाली बातें ही पूरी कर लेता हूं। आपने जो ऐच्छिक निधि शुरू की और उसके बाद उसको 4 से 5 लाख रुपये किया, वह भी स्वागत योग्य है और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मगर अब धन्यवाद करने की इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। हम बजट बुक में

तलाशने की कोशिश कर रहे थे मगर नहीं मिल पा रही है। आज केंद्र में नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार चल रही है और वह एन0डी0ए0 की सरकार हिमाचल प्रदेश को खुले मन से सहयोग रक रही है। मगर सरकार ने सिर्फ एक पैरा में और मुझे नहीं पता यह गलती कहां से हो गई। पेज नम्बर 7 के पैरा नम्बर 12 पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया है कि 'मैं इस अवसर पर केंद्रीय सरकार व नीति आयोग का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने हिमालय पर्वतीय प्रदेशों को सभी केंद्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर 90:10 के अनुपात में वित्त पोषित करने का निर्णय लिया है।' इसके सिवाय मैं इस बजट बुक का पेज पलटता रहा, पलटता रहा; सारे पेज बदल दिए मगर कहीं पर भी धन्यवाद का जिक्र नहीं मिला। यहां पर मेरे मित्र अनिल कुमार जी बैठे हैं और आप एक अच्छे आदमी है। मगर पिछली बार यहां पर उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे नहीं थे। यहां कोई दूसरे मंत्री भी नहीं बैठे थे, मुझे यहां पर केवल आप ही दिखे और मैंने सारा ठिकरा आपके ऊपर डाल दिया। वैसे मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी किसी को कुछ नहीं बोला। 13वें वित्तायोग में शहरी

16.3.2016/1520/av/ag/2

विकास निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए 642 करोड़ रुपये का प्रावधान था और 14 वें वित्तायोग में यह बढ़कर के 2011 करोड़ रुपये हो गया है। अगर हम सैंट्रल टैक्सिज के शेयर की बात करें तो वह 13वें वित्तायोग में 11327 करोड़ रुपये का था और एन0डी0ए0 की सरकार में यह बढ़कर 28107 करोड़ रुपये हुआ है। मगर आपकी तरफ से धन्यवाद का शब्द नहीं निकल पाया। इसके अतिरिक्त स्टेट डिजास्टर मेनेजमैंट के तहत 13वें वित्तायोग में 670 करोड़ रुपये का प्रावधान है और 14वें वित्तायोग में 1304 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इतनी इनक्रीज होने के बावजूद भी आपकी सरकार को धन्यवाद करने का एक शब्द नहीं मिल पाया। इससे आगे बढ़कर हम अगर 13वें वित्तायोग द्वारा दी गई टोटल ग्रांट के बारे में देखें तो 21691 करोड़ रुपये बनती है और 14वें वित्तायोग में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह ग्रांट बढ़कर 72047 करोड़ रुपये हुई है तथा इसमें 50356 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में इस प्रकार का आर्थिक सहयोग हिमाचल प्रदेश को कभी नहीं मिला जो

केंद्र की वर्तमान सरकार की ओर से मिला है। हम राजनैतिक बातें नहीं करना चाहते मगर यह सच्चाई है कि वर्तमान सरकार सत्ता में कैसे आई है? आपकी पार्टी की सरकार सत्ता में कैसे आई? उस समय एक प्रचार किया गया। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र

टीसी द्वारा जारी

16.03.2016/1525/TCV/AS/1

श्री जय राम ठाकुर-- जारी।

जिसका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बज़ट भाषण में भी किया है और बजट भाषण से पहले जो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, उसमें भी उसका जिक्र है। जिक्र क्या है कि हमने जो घोषणा पत्र में बातें की थी, उन तमाम वायदों को पूरा करने की हमने कोशिश की और उन वायदों को पूरा कर लिया। मैं सारी बातें छोड़ देता हूं लेकिन जिस एक वायदे के कारण आप सत्ता में आये हैं,वह सबसे बड़ा वायदा था कि हिमाचल प्रदेश के बेरोज़गार नौजवानों को आपने गुमराह करके उनसे वायदा किया कि हमारी सरकार आने के बाद आपको बेरोज़गारी भत्ता देंगे। आपने बात बेरोज़गारी भत्ते की कही थी, ये आपके घोषणा पत्र में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो बेरोज़गारी भत्ते का जिक्र जब हम लोग सत्ता में थे तब हमारी पार्टी की ओर से एक निर्णय हुआ और घोषणा पत्र कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोगों/नौजवानों/संस्थाओं के माध्यम से प्रस्ताव हमको मिले और कहा कि बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करो। हमने यह मुद्दा माननीय मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष कैबिनेट में रखा। माननीय मुख्य मंत्री ने उसी वक्त अधिकारियों की बैठक की और बैठक में पूछा गया कि क्या प्रदेश इस स्थिति में हैं? लेकिन सब अधिकारियों ने कहा कि यह संभव नहीं है, न किया जा सकता है और न ही इस प्रकार से करना चाहिए। हमारी सरकार/आदरणीय धूमल जी ने इस बात का निर्णय लिया कि जो हम नहीं कर सकते, वह हमें नहीं कहना चाहिए। यदि हम चाहते तो हम भी ऐसा कर सकते थे, घोषणा पत्र में एक लाईन जोड़ना कोई कठिन काम नहीं था बल्कि आसान काम था। जब हमारा घोषणा पत्र का ड्राफ्ट फाईनली तैयार हुआ तो हमने खुद

इस बात को स्वीकार किया कि जो वायदा हम कर सकते हैं वह हमें पूरा करना चाहिए। इसलिए इसको हम घोषणा पत्र में नहीं डालेंगे। हम बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं कहेंगे। आपने बेरोजगारी भत्ते की वज़ह से प्रदेश के नौजवानों को गुमराह कर डाला और कहा कि आप खाता खोल रखो जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, एक हजार रूपया आपके खाते में आता रहेगा और जो ग्रेजुएट थे,उनको कहा कि आपके खाते में 1500 रूपया आता रहेगा। ये आपके नेता बोल रहे थे। आपने भी ऐसा बोला होगा।

16.03.2016/1525/TCV/AS/2

मुख्य मंत्रीः मैंने कभी ये नहीं कहा। मैं यहां कहता रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनीफेसिटो है, इसमें कभी भी यह नहीं कहा गया कि बेरोज़गारों को भत्ता दिया जाएगा। कोई भी सरकार इस बात को नहीं कर सकती है। दूसरी बात यह है कि यह ऐसा ही वायदा है जो मोदी जी ने किया था "सत्ता में आने दो आपके बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रूपया आ जाएगा।" वह आ गया क्या?

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं तो घोषणा पत्र का जिक्र कर रहा हूं लेकिन मोदी जी ने इस तरह से घोषणा पत्र में नहीं कहा है। अध्यक्ष महोदय, इनका घोषणा पत्र शायद बाली जी ने बनाया था, वह इस कमेटी के चेयरमैन थे और आपको उन्होंने गुमराह किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमुख कारण कह रहा हूं अगर हम आगे की बातें करें, जिक्र आया कि यहां हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए और चुनाव में सब कुछ अच्छा हुआ। मैंने उन बातों का जिक्र महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी काफी हद तक कर दिया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये तो सच्चाई है कि वर्तमान में भी जो सरकार सत्ता में है, हो सकता है कि मुख्य मंत्री तक जानकारी नहीं पहुंचती होगी। लेकिन आपके नीचे के नेता क्या करते है? इन सब बातों की जानकारी आपको इन लोगों के माध्यम से मिल सकती है या फिर हम जानकारी दे देंगे। कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हुए, ठीक है हम इस बात को मानते हैं कि चुनाव तो निष्पक्ष हुए होंगे लेकिन उसके बाद ये भी सच्चाई है कि जब जिला परिषद्/बी0डी0सी0 का चेयरमैन का बनाने की बात आई, हमारे गोहर ब्लॉक का एक बी0डी0सी0 मैंबर, उसकी पत्नी नौकरी करती थी, उसकी पत्नी को धर्मपुर में ट्रांस्फर कर दिया। उस बी0डी0सी0 मैंबर

को उठाया और गाड़ी में लेकर चले गये

श्री आर0के0एस0 ---द्वारा जारी।

16.03.2016/1530/RKS/AG/1

श्री जय राम ठाकुर द्वारा जारी....

और एक वोट से इनका चेयरमैन बना। यह गोहर ब्लॉक की बात है।

मुख्य मंत्रीः अपना रोना यहां पर क्यों रो रहे हो?

श्री जय राम ठाकुरः मैं अपना रोना नहीं रो रहा हूं, मैं सरकार का रोना रो रहा हूं।

मुख्य मंत्रीः अपना रोना मेरे कमरे में आ के रोना मैं आपके आंसू पोंछ दूंगा।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, एक बी.डी.सी. का मैम्बर जिसका भाई इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड में जे.ई. था। उसको बोला गया कि वह अपने भाई को इधर लाएं। अध्यक्ष महोदय, उसके ऑर्डर डोडर क्वार में कर दिए। यह मैं कह रहा हूं। बाद में आपने वह ऑर्डर शायद कैंसल कर दिए थे।

मुख्य मंत्रीः शायद आपको अपना वक्त याद आ रहा होगा। आपके वक्त ऐसा हुआ होगा। I can tell you मेरी सजैशन में चाहे वह जिला परिषद् का इलैक्शन है, चाहे पंचायत समिति का इलैक्शन है या उसके पदाधिकारी बनने का प्रश्न है। मैंने कहीं भी इंटरफेयर नहीं किया और न ही सरकार ने इंटरफेयर किया।

श्री जय राम ठाकुरः सच्चाई अलग है, शायद इस तरह की जानकारी आप तक नहीं पहुंची होगी। आप वैरिफाई कर लें। मैं उनका नाम बता दूंगा। उनका नाम नरेंद्र है। जो इलैक्ट्रिसिटी में जे.ई. है जिसके ट्रांसफर ऑर्डर डोडरा क्वार कर दिए गए। जब चेयरमैन हमारी पार्टी का बन गया तो उसके बाद आपने यह ऑर्डर कैंसल कर दिए।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप कितना समय और बोलेंगे। बहुत समय हो गया है।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, अभी मैं 10 मिनट ही बोला हूं।

अध्यक्षः आपको 15 मिनट हो गए हैं, आप कितनी देर और बोलेंगे?

श्री जय राम ठाकुरः मुझे 10-15 मिनट और बोलने में लगेंगे।

16.03.2016/1530/RKS/AG/2

अध्यक्षः मैं आपको इतना समय नहीं दे सकता हूं। अगर आपके दूसरे सदस्य नहीं बोलेंगे तो मैं उन सदस्यों का समय आप को दे सकता हूं। you can ask others not to speak and they can give you their time.

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, यहां 35-35 मिनट तक सदस्य बोले हैं और आप हमें 10 मिनट में रोक रहे हैं।

अध्यक्षः जो सदस्य अभी बोलने वाले हैं वे फिर मुझे बाद में न कहें कि हमें समय नहीं दिया गया।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, हम इस मान्य सदन में चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमको प्लानिंग की तरफ से कहा जाता है कि आप विधायक प्राथमिकता दीजिए। हम विधायक प्राथमिकताएं देते हैं। ठीक है, पीछे जो हुआ उसे छोड़िए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि वे इस संस्थान को मजबूत करने के पक्षधर रहे हैं। लेकिन इसमें आप एक कदम उठा सकते हैं। अगर किसी विधान सभा क्षेत्र में कोई विधायक प्राथमिकता की योजना है चाहे यह योजना सड़की की हो या बिजली की हो या पानी की हो जब यह योजना बनकर तैयार हो जाती है और जब आप उसका शिलान्यास करते हैं तो उस विधायक का नाम भी वहां पर डालने की जरूर कोशिश करें। मुझे लगता है कि इस बात से सारा हाऊस सहमत होगा। लोक सभा यानी केंद्र सरकार का एक सैट सिस्टम है। योजनाएं हम लोगों ने तैयार की है और आज जो जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं वे उन योजनाओं का शिलान्यास और उद्‌घाटन कर रहे हैं। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं इस बात को मानता हूं कि यह सब पहले भी होता रहा। लेकिन मैं इस पक्षधर में हूं कि अगर पहले हुआ है तो आगे इसमें सुधार किया जाना चाहिए। कम से कम एक विधायक जो जीत कर आया है चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो अगर वह योजना विधायक

प्राथमिकता की है तो उस योजना मे उस

16.03.2016/1530/RKS/AG/3

विधायक का नाम अंकित होना चाहिए। इस परंपरा को आगे बढ़ाकर के लिए आप कदम उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आप इस दिशा में बात करेंगे।

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी

16.03.2016/1535/SLS-DC-1

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

आप सुधार करिए।...(व्यवधान)... रिजिड होकर यह नहीं होगा। आप शुरुआत कीजिए, हम इसका समर्थन करेंगे। हमेशा के लिए यह एक नियम बन जाए।

अध्यक्ष महोदय, अब किसानों और बागवानों की बात आती है। मुख्य मंत्री जी ने एक योजना मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना नाम से शुरू की। इसमें 25 करोड़ रुपये के आबंटन का आपने ज़िक्र किया है। प्रदेश के लिए 25 करोड़ रुपया शुरुआत के लिए काफी है। लेकिन उसमें एक विचित्र बात लग रही है कि आप सौर ऊर्जा के माध्यम से बाड़ में करंट पास करने की बात कर रहे हैं। मुझे यह व्यवहारिक बात नहीं लगती। आप योजना बनाइए और इस दिशा में हम भी आगे बढ़कर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि इसमें व्यवहारिक पक्ष छूट रहा है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने 10.03.2016 को इस माननीय सदन में एक प्रश्न संख्या 2823 पूछा। उसमें बागवानों का ज़िक्र था। एंटिहेल नैट पर सब्सिडी देने की जो आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने जानकारी चाही थी। अध्यक्ष महोदय, शोर तो यह किया जा रहा है कि हम एंटिहेल नैट पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उस 80 प्रतिशत में से 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार का है, केवल 30 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का है। जब मैंने पूछा कि कितने लोगों को सब्सिडी दी गई? अध्यक्ष

महोदय, मुझे सचमुच में इस बात का दुख होता है कि अभी तक केवल 994 लोगों को ही एंटिहेल नैट पर सब्सिडी दी गई है। उनमें से 697 शिमला जिले के ही हैं जबकि कुल्लू के 150, मण्डी जिले के 107, हमीरपुर के 16, बिलासपुर के 11, सिरमौर के 7, ऊना के 4, सोलन का एक किन्नौर का एक, और चम्बा, कांगड़ा तथा लाहौल-स्पिति शून्य। ...(व्यवधान)... ठीक है, यह डिमांड बेसड है। अध्यक्ष महोदय, अब सच्चाई सामने आ गई। मेरे क्षेत्र के लोगों ने एंटिहेल नैट के लिए इतने ज्यादा प्रस्ताव भेज रखे हैं लेकिन पिछले तीन सालों में उनको एक भी पैसा नहीं मिला। इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कम-से-कम

16.03.2016/1535/SLS- DC -2

इसको बराबर करने की कोशिश तो करें। फिर बात उठती है कि आप केवल ऊपर का ही देखते है। मैं समझता हूं कि इस बात को समाप्त करना चाहिए; इस दृष्टि से आप आगे बढ़े। कुल्लू और मण्डी जिलों के ऐसे बहुत सारे मामले लंबित पड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम और आगे जाएं तो स्वास्थ्य की बात आती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अभी यहां नहीं हैं। यहां पर मैडिकल कॉलेज खोलने की बात आई, चाहे वह नेरचौक का ई.एस.आई. मैडिकल कॉलेज है या नाहन, हमीरपुर और चम्बा में नए मैडिकल कॉलेज खोलने की बात हो। क्या यह सत्य नहीं है कि जो दो मैडिकल कॉलेज इस समय चल रहे हैं, उन्हीं में सरकार हांफ रही है। यह सच्चाई है क्योंकि मैं इस महकमें से बहुत नजदीकी से जुड़ा हूं। हमको जानकारी मिलती रहती है। हम कई बार भावावेश में आकर बहुत सारी संस्थाएं खोलने के लिए व्यवहारिक पक्ष को भूलकर घोषणा कर देते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि हम दो मैडिकल कॉलेज भी ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप आई.जी.एम.सी. जाएं, वहां 2-2 दिन तक बीमार स्ट्रेचर पर पड़ा रहता है। इस तरह की ख़बरें अख़बारों में भी लगी होती हैं। उस स्थिति में उनका ईलाज नहीं हो पा रहा है।

मुख्य मंत्री : आप बात को exaggerate कर रहे हैं, चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर कह रहे हैं। हमारा इंदिरा गान्धी मैडिकल कॉलेज is one of the best in the country. इसी तरह ही हमारा टाण्डा मैडिकल कॉलेज है। जो दूसरे कॉलेज हम खोल रहे हैं वह हमने

हिम्मत की बात की है। हम चम्बा में खोल रहे हैं, हमीरपुर में खोल रहे हैं. We are spreading the medical education and along with that, जो हॉस्पिटल्ज होंगे they will be specialized hospitals to give service to the patients. आप तो हर चीज को क्रिटिसाईज करना चाहते हैं। अगर आपकी फिलौसफी मानी जाए तब तो हमें संस्थानों पर ताला लगाकर केवल राम नाम की धुन की ही रटन करनी पड़ेगी।

जारी ...श्री गर्ग जी

16/03/2016/1540/RG/DC/1

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि संस्थान खोलना अच्छा लगता है, कहने में भी अच्छा लगता है, सामने से तालियां भी बजती हैं और जिन्दाबाद के नारे भी लगते हैं, लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि बहुत सारी संस्थाएं खोलते-खोलते जो चली हुई संस्थाएं हैं, वे भी बन्द होने के कगार पर हैं।

मुख्य मंत्री : ऐसी कोई नहीं है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। इसी माननीय सदन में मैंने प्रश्न किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों के कुल कितने पद खाली हैं? तो पता चला कि मेरे क्षेत्र में लगभग 374 पद अध्यापकों के खाली हैं। आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं। हमारे कई साथी इस बात को कह रहे थे कि जहां मैदानी इलाका है, वहां पहले कोई पद खाली नहीं होता था, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि संस्थाएं इतनी खुल गई हैं जिसके कारण मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों में भी अब अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं। जिससे बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त और भी मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : हरेक को सीमा के अंदर बोलना चाहिए।

श्री जय राम ठाकुर : माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं अपनी सीमा जानता हूं और मैं अपनी सीमा के अंदर ही बोल रहा हूं।

मुख्य मंत्री : मैं समय-सीमा की बात कर रहा हूं। वैसे जो आपकी मर्जी है, वह कहें। लेकिन समय का भी ध्यान रखिए। इधर के लोगों को भी तो बोलना है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करिए। आपको बोलते हुए बीस मिनट हो गए हैं। बाकी लोगों को भी बोलना है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने, ठीक है कि पंचायती राज संस्थाओं में मानदेय को कुछ थोड़ा-थोड़ा बढ़ाया गया। लेकिन आज की तारीख में उस पैसे से क्या होने वाला है? अगर आपने पेन्शन में 200/-रुपये बढ़ा दिए या दिहाड़ी में आपने 180/-रुपये में 20/-रुपये बढ़ा दिए, तो एक रुपये प्रतिदिन का भी दिहाड़ीदार का नहीं बढ़ा। यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है

16/03/2016/1540/RG/DC/2

जिससे हम यह कह सकें कि उनको इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ठीक है कि आपने इस दिशा में प्रयत्न किया और इसको बढ़ाने की कोशिश की, आपने इस बजट में सबको समेटने की कोशिश की है। क्योंकि चार साल के बाद बजट ऐसा ही रहता है और आपका एक और बजट पेश करने को है। उसके बाद चुनाव होगा, तो चुनाव से पहले का बजट इस तरह का रहता ही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्तमान में परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। आज की तारीख में आर्थिक दृष्टि से जो सुझाव हमारे सब साथियों ने दिए हैं, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। मंत्री तो ठीक है, संख्या निर्धारित है। लेकिन हमारे मित्र जो आपने सी.पी.एस. बना दिए हैं और उसके बाद चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन की संख्या इतनी बढ़ा दी। उसमें कुछ कटोती करें। जब आपको लगता है और बहुत पीड़ा के साथ कहते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तो यही से शुरूआत करें। हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप इस दिशा में कोई कदम उठाने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, एक बात कहकर समाप्त करुंगा।

अध्यक्ष : जय राम जी आप समाप्त करिए। आपको बोलते हुए पच्चीस मिनट हो गए हैं। You want other Members should not speak?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा :-

कुछ जुदा सा दिखता है नज़रिया उनका, मेरे नज़रिये से,
शायद उन्हें वक्त गुज़ारना था और मुझे सारी जिन्दगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16/03/2016/1540/RG/DC/3

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूं और मैं यह बात ऑनैस्टली कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा संस्थान अगर खोले गए हैं, तो माननीय सदस्य के हल्के में खोले गए हैं। अगर इनको उसके बारे में कोई ऐतराज़ है, तो ये लिखकर दें, हम उन्हें बन्द कर देते हैं। जिनको ये बन्द करना चाहते हैं, उनके बारे में ये मुझे लिखें, मैं कल ही ऑर्डर करके उनको बंद कर देता हूं। क्यों, उनको खोलने से इनको तकलीफ हो रही है, तो उन्हें बंद कर देते हैं। Inspite of the fact, you were the Minister from there. Your area was one of the most backward areas of Himachal Pradesh. अगर आप देखेंगे कि किस चुनाव क्षेत्र में कितने स्कूल खोले गए हैं, तो इनके चुनाव क्षेत्र में अधिकतर सबसे ज्यादा संस्थाएं खोली गई हैं। वह एक बैकवर्ड है। मैं तो कहता हूं कि अगर इनको उनसे तकलीफ है या हमारे स्कूल खोलने से इनको कोई कष्ट हुआ हो, तो कृपा कीजिए। आप उसकी सूची दीजिए, मैं कल ही बंद कर दूंगा और मैं कहूंगा कि आपके विधायक साहब नहीं चाहते हैं, कल ही उनको बंद कर दूंगा।

एम.एस. द्वारा अगले वक्ता शुरू

16/03/2016/1545/MS/AG/1

अध्यक्षः ठीक है। No arguments. यह सब लाइटर वे में था।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष जी, मैं एक छोटी सी बात माननीय मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वहां पर संस्थान खोले हैं लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उनको चलाने का इंतजाम भी कीजिए। नहीं तो वहां फट्टे लगाकर ताले लग रहे हैं। वह आपके लिए भी शोभा नहीं दे रहा है और मेरे लिए भी शोभा नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ इतनी ही बात कह रहा हूं।

मुख्य मंत्रीः जहां ताले लगे हैं उसकी सूची मुझे दे दीजिए। मैं उन स्कूलों को भी बन्द कर देता हूं। मेरे पास तो ऐसी कोई सूची नहीं है। अगर आपकी नज़र में कहीं ताले लगे हैं तो मुझे बताइए? हम आपको खुश करने के लिए उस स्कूल को बन्द कर देंगे।

16/03/2016/1545/MS/AG/2

अध्यक्षः अब चर्चा में माननीय किशोरी लाल जी भाग लेंगे।

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष जी, 08 मार्च, 2016 को आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो वर्ष 2016-17 का बजट अनुमान इस मान्य सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में हाल ही में अपना 19वां बजट अनुमान इस सदन में पेश किया है। इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं।

अध्यक्ष जी, बजट सरकार का आइना होता है। बजट से पूरे वर्ष में होने वाले विकास का चेहरा देखने को मिलता है जो इस बजट बुक में शामिल है। जो बजट अनुमान आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार बजट विकासोन्मुखी, संतुलित, हर वर्ग को राहत देने वाला और कर-मुक्त है। यह बजट गरीबों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला

परिषद के चुनाव सम्पन्न हुए। साथ ही जो हमारे निकाय हैं उनके चुनाव भी सम्पन्न हुए और चुनावों में जो तीन वर्ष का कार्यकाल आदरणीय मुख्य मंत्री जी का विकास का रहा है, उसमें जनता ने मोहर लगाई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवार ही ज्यादा जीतकर आए हैं। मैं अपने चुनाव क्षेत्र का जिक्र करना चाहता हूं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से बैजनाथ पपरोला में नगर पंचायत बनी और उसके नौ वार्डों के चुनाव हुए। वहां पर सभी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हमारी कांग्रेस पार्टी का जीता है। साथ ही पंचायत समिति के जो चुनाव हुए उसमें 21 पंचायत समिति के सदस्य थे जिनमें से 13 सदस्य हमारी कांग्रेस पार्टी के जीतकर आए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वहां पर चुना है। इससे साबित हो जाता है। इसी तरह से ग्राम पंचायतों में बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में 80 प्रतिशत प्रधान कांग्रेस पार्टी के जीतकर आए हैं। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व में यह सब सम्पन्न हुआ है।

16/03/2016/1545/MS/AG/3

अध्यक्ष जी, मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के समय की वर्ष 1990 बात करना चाहता हूं। उस समय मैं ग्राम पंचायत का प्रधान था और प्रदेश में आदरणीय शांता कुमार जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने बेवजह पांच बार मेरे खिलाफ विजीलैंस के इन्सपैक्टर्ज से मेरी जांच करवाई। वजह कोई भी नहीं थी इसलिए किशोरी लाल पाक-साफ निकला। बाद में भी मेरे खिलाफ ऐसे ही मन-गढ़न्त केस एस0डी0एम0 पालमपुर के कोर्ट में लगाते रहे। यह बड़ी शर्म की बात है। मैं उसके बाद की बात भी करना चाहता हूं। जो पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में रही है उसमें आदरणीय पंचायत राज मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी थे। वह अभी सदन में मौजूद नहीं है। उस समय आदरणीय धूमल जी प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। उस समय दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक सेमिनार हुआ। मुझे भी बतौर प्रधान वहां जाने का मौका मिला। माननीय जय राम ठाकुर जी भी अपने प्रधानों को लेकर दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली में एक मैडल और एक प्रशस्ति पत्र हमें मिलना था लेकिन मुझे वह नहीं दिया गया। जय राम ठाकुर जी अब सदन में मौजूद हैं, तो मुझे वह मैडल और एक सर्टिफिकेट जो मिलना था, वह नहीं मिला। वह आपने अपने प्रधानों को दिला दिया। ऐसा मेरे साथ आपके समय में हुआ है। आप सामने बैठे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो

सकती है?

मैं दिल्ली की बात करना चाहता हूं। जब आदरणीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री थे और इनके पास इस्पात विभाग था, उस समय दिल्ली में एक सेमिनार हुआ।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

16.03.2016/1550/जेएस/एजी/1

श्री किशोरी लालः-----जारी--------

मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं । आप ले कर आए आपने मुझे नहीं दिया। मैं सामने बात कर रहा हूं। चोरी-छिपे बात नहीं करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये जो यहां पर पैंशन की बात कर रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा पैंशन आदरणीय मुख्य मंत्री जी की बदौलत जो 450 रूपए थी वह अब 650 रूपए पहुंच गई है। 80 वर्ष के ऊपर के जो वृद्ध थे तथा 70 प्रतिशत अपंग व्यक्ति थे उनको आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पैंशन 450 रूपए से 650 रूपए तक पहुंचाई है और जो 1100 रूपए थी वह अब 1200 रूपए की गई। भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर किसी ने पैंशन लेनी होती थी, जब पैंशन होल्डर मर जाए तब दूसरों को पैंशन लगती थी। ऐसी भी सरकार आपकी रही है। उस वक्त को आप याद करिए। आप उस वक्त को क्यों नहीं याद करते? बड़ी-बड़ी बातें यहां पर करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने यहां 35 बार बजट पेश किया लेकिन जो असलियत है उसको तो आप समझिए। आपके समय में क्या होता था, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रधान होते थे उनको टॉर्चर किया जाता था, उनके ऊपर मुकद्में बनाए जाते थे? मैं, आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इनके शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ। ये सबको समान दृष्टि से देखते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं। आप सुनने की थोड़ी क्षमता रखें। जिन नगर पंचायतों का गठन हुआ है, वहां पर मनरेगा की स्कीम बन्द हुई है। मैं, आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इनकी कृपा से वहां लक्ष्य लाल बहादुर शास्त्री कामगार एवं शहरी आजीविका योजना की घोषणा की गई है, उससे 365 दिन लोगों को रोज़गार मिलेगा।

यहां पर पिछले दिनों जो चुनाव नगर पंचायतों के हुए वहां हमारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा बहकाया गया कि मनरेगा बन्द हो जाएगी। आपकी कुकड़ियों और मुर्गियों पर टैक्स लग जाएगा। आपकी बकरियों के ऊपर टैक्स लग जाएगा। आपके पशुओं के ऊपर टैक्स लग जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पांच साल तक वहां कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं, आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता

16.03.2016/1550/जेएस/एजी/2

हूं कि बैजनाथ में इन्होंने 19 जनवरी को घोषण की कि वहां पर बहुमंजिला पार्किंग बनाई जाएगी। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि पार्किंग का शिलान्यास शहरी विकास मंत्री जी ने अभी हाल ही में 11 मार्च, 2016 को बैजनाथ में किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है और जो भी घोषणा मुख्य मंत्री जी करते हैं वह पत्थर की लकीर होती है। कोई भी ऐसी घोषणा नहीं होती है जिसमें इम्पलीमैंट न हुआ हो।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में महिलओं का मान-सम्मान आदरणीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से बढ़ा है। प्रदेश में 58 प्रतिशत महिलाएं ग्राम पंचायत में जीत कर आई हैं। काई समय था महिलाएं ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं लड़ती थीं। लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सोच से ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला है। आज उसी का नतीज़ा है कि 50 प्रतिशत महिलाएं ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ करके पुरूषों के बराबर काम कर रही हैं। महिलाएं पुरूषों से भ्रष्टाचार में कम संलिप्त हैं। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार के मामले आए भी हैं तो वे दूसरे लोगों के हैं जो यहां पर विरोध कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्री जी की सोच से यहां पर इस बात का स्वागत हुआ कि विधायक निधि जो 75 लाख थी वह 1 करोड़ रूपए हुई है। इसी के साथ जो 4 लाख ऐच्छिक निधि थी वह 5 लाख हुई है। इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। विपक्ष के हमारे साथियों ने भी इसका स्वागत किया है। इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में जो मंहगाई बढ़ रही थी उसको मध्यनज़र रखते हुए वर्ष 2007 में राज्य खाद्यान्न उपदान योजना आरम्भ

की थी। प्रत्येक राशन में घर को 3 दालें, 2 खाद्य तेल, 1 किलो आयोडीन युक्त नमक उपदान पर उपलब्ध करवाया जाता था। उसे वर्ष 2016-17 में भी जारी रखने हेतु 210 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान है।

श्री एस0एस0द्वारा जारी-------

16.03.2016/1555/SS-AS/1

श्री किशोरी लाल क्रमागतः

इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी पहल से प्रदेश में योजना शुरू हुई है। राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत राज्य में 37 लाख लोगों को 3 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो तथा दो किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह के हिसाब से प्रदान किया जा रहा है। सभी बी0पी0एल0 परिवारों को 35 किलोग्राम राशन प्रतिमाह दिया जा रहा है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां शिक्षा की बात हमारे विपक्ष के साथी करते रहे हैं कि शिक्षा में कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में 100 के करीब कॉलेज खोले और 28 तो इन तीन वर्षों में खोले हैं। बैजनाथ का जो पंडित संत राम डिग्री कॉलेज था, वहां पर एम0ए0 इंग्लिश की कक्षाएं भी शुरू की हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इनके आशीर्वाद से बैजनाथ का कॉलेज पोस्ट ग्रैजुऐट हुआ है। वहां पर दो सब्जैक्टस इस वर्ष एम0ए0 (इंग्लिश) और एम0ए0 (इकोनॉमिक्स) की क्लासें भी शुरू होंगी। मुझे खुशी है कि वहां जो छात्र एम0ए0 इंग्लिश कर रहे हैं वे दूसरी जगह पढ़ाई नहीं कर सकते थे क्योंकि वे गरीब लोग थे। दूसरी जगह जाकर पढ़ नहीं सकते थे। मुख्य मंत्री जी की एक सोच है कि इस प्रदेश के जो बच्चे हैं वे उच्च पढ़ाई करें और घर के नज़दीक पढ़ाई करें। इस उद्देश्य से इन्होंने बैजनाथ में कॉलेज खोला है। इसके लिए मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं कि वहां पोस्ट ग्रैजुऐट कक्षाएं शुरू हुईं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई स्कीमें आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू की हैं जिसमें कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर पहले नकद राशि 10 हजार मिलती थी जो उसकी जानकारी देता था। अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया है वह बहुत पनीत

कार्य है। कन्या भ्रूण से बड़ा पाप कोई नहीं है। इस प्रथा को रोकने के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 10 गुणा राशि बढ़ाई है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही नारी सेवा सदन में रहने वाली महिलाएं हैं उनके विवाह पर अनुदान पहले 25 हजार रुपये मिलता था, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने उसे 51 हजार रुपये किया है। इसके साथ ही जो हमारी मुख्य मंत्री कन्यादान योजना है, उसके अन्तर्गत जो 25 हजार रुपये का अनुदान था, उसे बढ़ाकर 44 हजार रुपये किया है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

16.03.2016/1555/SS-AS/2

साथ ही जो हमारी 45 वर्ष से कम उम्र की विधवाएं हैं उन्हें जो पैंशन राशि 600 रुपये मिलती थी उसे बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है। वह बहुत पनीत कार्य है। इसी तरह से गृह रक्षक का दैनिक भत्ता 280 रुपये से 350 रुपये किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में 13 हजार से अधिक पदों को भरने का निर्णय जो आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने लिया है मैं समझता हूं कि वह कर्मचारियों के हित में है। प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी तथा पैंशनर्ज़ हैं उन्हें 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है। नियमित कर्मचारी तथा पैंशनर्ज़ को 5 प्रतिशत मूल वेतन भत्ता सहायता प्रदान करना भी बजट में प्रस्तावित है। इसके लिए भी मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में जहां हर स्कीम में इजाफा हुआ है वहीं पर मैं अपने चुनाव क्षेत्र का भी ज़िक्र कर देना चाहता हूं। यहां जो पीछे पांच साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रह कर गई, उस समय बैजनाथ में कोई विकास के काम नहीं हुए। उलटे इन्होंने क्या किया कि बैजनाथ डी0एस0पी0 का जो दफ्तर था उसे बदल कर दाड़लाघाट विद पोस्ट ले गये। बैजनाथ का सॉयल कंजरवेशन का दफ्तर था उसको बंद कर दिया। बैजनाथ में कैफे वैरंग था उसे कौड़ियों के भाव बेच दिया। बैजनाथ में जो वहां हॉस्पिटल था उसके सब डॉक्टरों को बदल दिया। बैजनाथ की गत्ता फैक्टरी को बंद कर दिया। मशीनरी को कौड़ियों के भाव बेच दिया। जो वहां पर फॉरैस्ट कारपोरेशन के लकड़ी-कोयले के डिपो थे उनको बंद कर दिया। बैजनाथ में कोई नया दफ्तर पांच सालों में नहीं खुला। बैजनाथ की सड़कों की हालत बहुत खराब थी, कोई नहीं बनी। लेकिन आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी की कृपा से बैजनाथ चुनाव विधान सभा क्षेत्र में ये जो तीन साल निकले हैं वहां करोड़ों रुपये

के विकास के काम हो रहे हैं। आपके समय में वे स्कीमें कहां पर थीं?

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2016/1600/केएस/एएस/1

श्री किशोरी लाल जारी----

भाषण तो आप बड़े-बड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कर्जा अब बढ़ा। क्या तीन सालों में कर्जा बढ़ा या आपके समय में भी कर्जा लिया जाता रहा? जरा उस बात को सोचिए। उस बात को आप लोग क्यों ध्यान में नहीं रखते कि हमारे कार्यकाल में भी कर्जा बढ़ा है। विकास के लिए कर्जा लेना पड़ता है लेकिन विकास को जो गति इस पूरे प्रदेश में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने दी है वह सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं कि यह बजट हर वर्ग को राहत देने वाला है। विपक्ष के मेरे कई भाई बोलते रहे कि मुफ्त में वर्दी क्यों दे रहे हैं? मुफ्त में किताबें व खाना क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, अभी भी कई गरीब लोग हैं उनका ध्यान रखिए। गरीबों के मसीहा राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, आप लोग नहीं हो सकते क्योंकि आप लोग तो इसका विरोध करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में आवागमन का एक मात्र साधन बस सुविधा है। मुख्य मंत्री जी की कृपा से प्रदेश में 1300 नई बसें आई हैं। आपके समय में बसें खटारा थी, नहीं चलती थीं, कंडम हो जाती थी। रूट भी बन्द हो जाते थे और लोग देखते थे कि एच.आर.टी.सी. की बस आएगी लेकिन वह नहीं आती थी। आज पूरे प्रदेश में बसों का पूरा बेड़ा चल रहा है, बेड़ा बढ़ा है, बसें हर क्षेत्र में है, बाली जी ने अपने घर में खड़ी नहीं की। डिपो का विरोध हुआ कि वह नगरोटा में क्यों खुल गया? अरे भाइयों अपनी तरफ भी देखो। महेन्द्र सिंह जी ने उस वक्त कहां खोला था? एक खड्ड में ही डिपो बना दिया, बरसात में बसें बह गई। आपके समय में क्या होता रहा, वह आप नहीं देखते। मैं अधिक न कहता हुआ इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एक ऐसी स्कीम गांव के लिए शुरू की है, मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जहां पर गांव में सड़कें नहीं हैं, वहां सड़कें बनेगी और जहां बसें नहीं चलती है, बेरोज़गार युवाओं को बस परमिट दिए जाएंगें। वे बसें

चलाएं, स्वरोज़गार अपनाएं इसके लिए भी बजट में प्रावधान है कि उनको टैक्स में छूट होगी।

16.03.2016/1600/केएस/एएस/2

अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी बहुत बड़े आदमी है। चुनाव से पहले बड़े-बड़े भाषण करते थे कि अरे भाई, मुझे सत्ता दो मैं विदेशों से काला धन ला दूंगा और प्रत्येक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रु0 जमा करवा दूंगा। वह पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास आया होगा तो पता नहीं लेकिन बाकियों को तो मिला ही कुछ नहीं। प्रदेश की जनता इंतज़ार कर रही है। और कहते थे कि बहुत हुआ नौकरियों का इंतज़ार, अबकी बार मोदी सरकार परन्तु कितने लोगों को नौकरियां मिली? कहां है वह योजना? दो साल निकल गए, पांच साल भी ऐसे ही निकल जाएंगें। मंहगाई की बात करते थे कि बहुत हुई मंहगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार। कहां कम हुई मंहगाई? 200 रु0 तक तो अरहर की दाल बिकी है। 160 रु0 माश की दाल बिकी। कोई चीज़ सस्ती नहीं है। लोग हाहाकार कर रहे हैं, सरकार को रो रहे हैं। साथ में क्या मिला, बड़ी छाती ढोकते थे कि पाकिस्तान युद्ध में सक्षम नहीं है। अरे, पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा है। शर्म करो मेरे विपक्ष के भाइयों, देश चलाना आसान नहीं, उनको सलाह दो कि मुल्क को चलाओ। लोगों को ठगो मत। अध्यक्ष महोदय, अधिक न कहता हुआ यह जो बजट मुख्य मंत्री जी ने पेश किया, इसका समर्थन करता हूं । धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ।

16.03.2016/1600/केएस/एएस/3

अध्यक्षः माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपने समय का ध्यान रखें। अब श्री रिखी राम कौंडल जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को इस माननीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वर्ष 2016-17 का बजट पेश किया है, बजट अनुमानों पर बोलने के लिए मुझे आपने अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, जो भी सरकार आती है, वह अपने बजट को कंसोलिडेट करके लोगों के हित के लिए

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2016/1605/av/ag/1

श्री रिखी राम कौंडल क्रमागत

हर वर्ष मार्च के महीने में जब बजट सैशन होता है तो सरकार एक दस्तावेज पेश करती है। उस बजट में जो खामियां या कमियां होती है उस बारे में विपक्ष अपनी बात रखता है। उन बातों को सत्ताधारी दल मानें या न मानें; यह सत्ता पक्ष पर निर्भर करता है। यदि विपक्ष की उन अच्छी बातों को मान लिया जाए तो पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ नहीं आना पड़ता। मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों को 476 करोड़ रुपये के घाटे के साथ पेश किया जबकि 14वें वित्तायोग के अंदर केवल 47 करोड़ रुपये राजस्व अभिलेख था तथा अर्थ व्यवस्था की हालत सरकार का ऋण बोझ की वजह से पैरा नम्बर 14 के अनुसार 2016-17 में ब्याज लगभग 34000 करोड़ रुपये रहने की सम्भावना है। इस बजट बुक के अंदर कुछ ऐसे सुझाव एवं योजनाएं भी हैं जिनका सीधा सम्बंध गरीबों से हैं। इसमें संसाधन बढ़ने की वजह से कुछ पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी हुई है बाकी कोई भी मद ऐसी नहीं है जिसमें थोड़ी-थोड़ी बढ़ोतरी की हो। इस बजट में पहले की स्कीमों के नाम बदलकर नये नाम रखे गये हैं। इसमें 8-9 ऐसी स्कीमें हैं जो केंद्र की हैं मगर यहां पर उनके नाम बदल कर मुख्य मंत्री योजना के नाम से शुरू कर दी गई है। इसमें जो ऐच्छिक निधि को 4 लाख रुपये से 5 लाख रुपये किया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसके अतिरिक्त विधायक निधि को भी 75 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये किया है और इसका सीधा सम्बन्ध प्रदेश की जनता के साथ है क्योंकि प्रदेश की जनता ने हम सबको यहां चुनकर भेजा है। वह पैसा विकास के कार्यों में लगेगा। एक और बात की है कि अब हैंड पम्प को विधायक निधि के पैसों से भी लगाया जा सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं। किसी भी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि सरकार के होते हुए प्रदेश के लोग सुरक्षित रहे। कर्मचारी के साथ-साथ गांव का किसान और बागवान भी सुरक्षित हो; यह सरकार का पहला दायित्व बनता है। इलाके में अमन हो, जान-माल

की सुरक्षा हो, क्राइम कम हो तथा लोग सरकार आने के बाद सुरक्षित महसूस करें। मगर मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि यहां इस

16.3.2016/1605/av/ag/2

सरकार ने बड़े आंकड़े पेश किए हैं। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी बोलते हैं कि जब से उनके नेतृत्व में यहां पर सरकार बनी है क्राइम कम हुए हैं। मैंने वैब साइट से वर्ष 2014 की एनुअल रिपोर्ट निकाली। अभी वैब साइट पर आपके होम डिपार्टमैंट ने वर्ष 2015 की रिपोर्ट तो डाली नहीं है। मैं उसके आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें आई0पी0सी0 के 14160 केसिज हैं जिसमें 3 प्रतिशत की इनक्रीज हुई है। फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि इस प्रदेश के अंदर कानून-व्यवस्था ठीक है। एनुअल रिपोर्ट वर्ष 2014 के अनुसार टोटल क्राइम में 8.33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न क्राइमों में 19355 पर्सन अरैस्ट किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है तो उसका चालान अदालत में पेश होता है। उसकी पैरवी सरकारी वकील करते हैं और यह सरकार का दायित्व होता है। वर्ष 2014 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार कनविक्शन रेट आई0पी0सी0 केसिज में 26.5 प्रतिशत है और इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आपकी पारदर्शिता कहां चली गई है क्योंकि आप यहां पर होम डिपार्टमैंट के बारे में बड़े जोर-शोर से बोलते हैं। ये आंकड़े होम डिपार्टमैंट की तरफ से डाले गये हैं, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। ऐसे केसिज में केवल 40 प्रतिशत की कनविक्शन मात्र हुई है।

टीसी द्वारा जारी

16.03.2016/1610/TCV/DC/1

श्री रिखी राम कौंडल --- जारी

ये होम डिपार्टमैंट के थोड़े से आंकड़े मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा 'क्राइम अंगेस्ट चिल्ड्रन', जो देश का भविष्य है, वह कल को नौजवान होकर देश का भविष्य बनेगा। इनमें क्राइम अंगेस्ट चिल्ड्रन के 467 केसिज़ हुए हैं और 6.13 परसेंट की इसमें इनक्रीज हुई है। सुसाईड के 644 केसिज़ हुए हैं, जिसका जिक्र वार्षिक रिपोर्ट 2014 में है और उसमें 16.2 परसेंट की बढ़ौतरी हई है। अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि जब से

हमारी सरकार आई है तब से होम डिपार्टमैंट में सुधार हुआ है और क्राइम के केसिज़ कम हुए हैं। मेरा इस मान्य सदन के अन्दर एक आरोप है कि कानून व्यवस्था की हालत प्रदेश के इतनी खराब है कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी आपके जो पुलिस के बड़े अधिकारी है, उनको आप निर्देश दीजिए कि थोड़ा पारदर्शिता के साथ काम करें। कुछेक अधिकारी हिमाचल प्रदेश में बाहर से आते हैं, वह टूरिस्ट के नाते आते है, मैं किसी बड़े अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, उनको थोड़ा कसने की आवश्यकता है। मुझे पता है कि प्रशासनिक दृष्टि से आप सक्षम है और इस बारे में आप सुधार अवश्य करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के हमारे कर्मचारी सुबह से शाम तक काम करते है, सन् 2007 का एक्ट आपने इस प्रदेश के अन्दर लागू कर दिया और आज 2016 का पे-कमिशन आने वाला है। लेकिन उन अधिकारियों/कर्मचारियों को आप इन्सेन्टिव 1996 के पे-कमिशन के हिसाब से दे रहे हैं। पुलिस के जवान जो 12-12 या 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उन कर्मचारियों को अगर 2016 का नहीं तो कम से कम 2006 के पे-कमिशन के हिसाब से तो इन्सैंटिव दीजिए। आपने इस प्रदेश के अन्दर जो 2007 का एक्ट लागू किया, उसमें जो सज़ाएं हैं, पनिशमेंट का जो दायरा आपने लागू किया है, वह तो लागू हो रहा है, परन्तु उन पुलिस कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी, 5 दिन के बाद एक दिन की छुट्टी और एक साल के बाद उनको एक महीने की तनख्वाह का इन्सैंटिव मिलना था वह नहीं मिल रहा है। ये जो आपने 2007 के एक्ट में प्रावधान किया है, मैं

16.03.2016/1610/TCV/DC/2

धन्यवाद देता हूं कि आपने 2007 का एक्ट लागू किया। लेकिन उसमें जो प्रावधान रखे गये हैं उनको लागू करने की आवश्यकता है ताकि जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, उनमें काम करने की दक्षता आये और वे हिम्मत और मेहनत से काम करें क्योंकि वही सारे प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था को देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि 2007 के एक्ट में इन्होंने 60:40 की रेशो रखी है। उस एक्ट में आपने जो 60:40 की रेशो तय की है, उसको भी लागू करने की कोशिश करे, ताकि जो प्रमोशन के लिए बैठें है और जिनकी 10 या 12 साल की नौकरी हो गई है, वे उस प्रमोशन का लाभ उठा सकें। इनकी वार्षिक रिपोर्ट में क्राइम रेट का एक डिस्ट्रक्ट-

वाइज इंडैक्स दिया है, इसमें सबसे ज्यादा क्राइम 310.2 परसेंट बिलासपुर जिला में हैं। वह क्यों है? वह इसलिए है कि वहां जो भी पुलिस के अधिकारी लगाये जाते हैं, वे सिफारिश से लगाये जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो व्यक्ति सक्षम है, उसको वहां लगाया जाये ताकि क्राइम रेट कम हो सके। इसके अलावा क्राइम में नंबर-II पर सोलन और नंबर-III पर लाहौल-स्पिति है। जो आपकी वार्षिक रिपोर्ट 2014 की है अगर क्राइम का एवरेज देखा जाये तो 206.5 परसेंट है। ये मैंने आपके सामने होम डिपार्टमैंट का विवरण रखा। बाकी अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण के बारे में 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सड़कें हमारी भाग्य रेखा हैं। सड़कों के क्षेत्र में जो-जो मुख्य मंत्री आया उसने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया। हो सकता है आपने उनसे ज्यादा काम किया हो। इसकी गणना तो हम नहीं कर सकते लेकिन जो सड़कें बनी है उन सड़कों का रखरखाव करना जो

श्री आर0के0एस0 --द्वारा जारी

16.03.2016/1615/RKS/AG/1

श्री रिखी राम कौंडल .... जारी....

मौजूदा सरकार होती है उसको करना पड़ता है। आज प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप इसके लिए एक टीम गठित कीजिए, जिसमें कुछ विधायक सत्ता पक्ष के हों और कुछ विपक्ष के हों। जो पूरे प्रदेश का भ्रमण करें कि सड़कों की दशा आज क्या बनी हुई है? जो टारिंग की जाती है वह एक सप्ताह के बाद उखड़ जाती है। जैसा कि माननीय गुलाब सिंह जी ने कहा जो टेलीफोन विभाग द्वारा सड़कों को उखाड़ा जा रहा है इससे हमको बहुत दिक्कत आ रही है। इस विभाग में किस तरह पारदर्शिता आएगी? आप कहत हैं कि हमने बहुत सारी पोस्टे भरी हुई हैं। आज भी 679 पद पी.डब्ल्यू. डी. विभाग में खाली पड़े हुए हैं। जिसमें से 300 पोस्टें जे.ई. की खाली है और 40 पोस्टें एस.डी. ओ. की खाली है। जिस प्रदेश के अंदर 300 पोस्टें जे.ई. की खाली हो, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में सुधार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे चुनाव क्षेत्र मे गए। बखालपुर का विषय हमारी सरकार के समय में आया उसमें तकनीकी खराबी की वजह

से काम बंद करना पड़ा। राजनैतिक लाभ लेने के लिए यह मुद्दा बन गया कि जब भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव आया तो कहा गया कि बखाल का पुल धूमल जी ने बंद कर दिया और इसको बंद कराने में कौंडल जी का हाथ है। चुनाव क्षेत्र में हर व्यक्ति, हर पार्टी का व्यक्ति ऐसे दाव -पेंच लगाता है। आप भी लगाते हैं, जब हमारा दाव लगता है तो हम भी लगाते है। परन्तु व्यक्ति को वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी आप मेंरे चुनाव क्षेत्र में गए और आपने सार्वजनिक भाषण में कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम इस पुल का काम शुरू कर देंगे। इसके बारे में मैंन प्रश्न किया, प्रश्न संख्याः 1286। इस प्रश्न में मैंने इस पुल की वस्तुस्थिति के बारे में पूछा। आपने इसके बारे में विस्तृत जवाब दिया जिसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। जब नलवाड़ी के मेले में आप बिलासपुर गए तो आपने वहां पर सार्वजनिक घोषणा की कि तकनीकी खराबी के कारण हम उस पुल को दुसरी जगह बनाएंगे। इसके बाद मैने पुनः प्रश्न किया और उस प्रश्न में, मैंने आपसे पूछा कि क्या दूसरी जगह पुल बनाने के लिए सर्वेक्षण

16.03.2016/1615/RKS/AG/2

किया जा रहा है?उत्तर में मुझे मिला कि कोई सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है। उसके बाद मैंने तीसरी बार पुनःप्रश्न किया। उसका उत्तर मुझे यह मिला कि हम पुल दुसरी जगह बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक पत्र कोड करना चाहता हूं । माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने 8 जुलाई, 2015 को माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि बड़सर से लेकर टू लेन जैसे बंगाणा की सड़क बनी हुई है भड़ोलीकलां और बबखाल तक इनक्लूडिंग ब्रिज और जो जंक्शन फोर लेन का दूसरे चुनाव क्षेत्र में बन रहा है वहां तक इंटर स्टेट कनैक्टिविटी में इसकी डी.पी.आर. बनाकर केंद्र को भेजी जाए, ताकि इसके पुल के लिए केंद्र सरकार से हम सारे बजट का प्रावधान करवाएं। मुझे मालूम है कि इंटर स्टेट कॉनैक्टिविटी में माईलेज के हिसाब से पैसा मिलता है। उसका सारा पैसा प्रदेश को मिल चुका था। लेकिन इस पत्र का जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को नहीं मिला। अगर इस पत्र के तहत इसकी डी.पी.आर.नहीं बन सकती थी तो किसी और हैड में डिपार्टमेंट को बुलाकर आप इसकी डी.पी.आर.बनवाते। जब तक आप यहां से प्रपोज करके कुछ नहीं

भेजेंगे तो केंद्र सरकार सुओ मोटा डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकती है। इस देश में संविधान के मुताबिक फैड्रल सिस्टम है। जब तक आपकी डी.पी.आरज. नहीं जाएगी, आपकी प्रपोजल नहीं जाएगी तब तक दिल्ली से पैसा नहीं मिल सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी स्टेट बजट में पुल बनना संभव नहीं है। गैमन एण्ड कंपनी जिसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, उनको हम आज तक 18 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। उसके लिए आपने आरबिट्रेटर बनाने की बात की थी। अभी तक आरबिट्रेटर नहीं लगाया गया है।

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी

16.03.2016/1620/SLS-AS-1

श्री रिखी राम कौंडल ...जारी

अप्रोचिज के लिए हम 6.00 करोड़ रुपया ख़र्च कर चुके हैं। अब जो पुल दूसरी जगह बनेगा उसकी फोरैस्ट क्लीयरैंस के लिए भी समय लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी और मद में आप इसकी डी.पी.आर. बनाकर केंद्र सरकार को भेजें। हम माननीय नड्डा जी को साथ लेकर, धूमल जी का सहयोग लेकर और माननीय गडकरी जी से मिलकर केंद्र से इस पुल के लिए धन का प्रावधान करवाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लोगों को इसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग को लेकर कौल सिंह जी बड़ी ढींगें मारते हैं कि मेरा स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं इसको ठीक नहीं समझता। आज भी स्वास्थ्य विभाग में 3740 पोस्टें खाली पड़ी हैं। ...(व्यवधान)... पठानिया जी, मैं गलत नहीं बोल रहा बल्कि एक कागज़ देख रहा था। जिस प्रकार सवाल का उत्तर देते समय आपसे कागज़ इधर-उधर हो जाता है उसी तरह से मैं भी अपना कागज़ देख रहा था। जिस विभाग में इतनी ज्यादा पोस्टें खाली हों, उस विभाग के लिए कैसे कहा जा सकता है कि बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं इस विभाग के बारे में और ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता।

परिवहन विभाग के बारे में बाली जी बहुत दक्षता के साथ उत्तर देते हैं। अभी वह सदन में नहीं हैं। आज परिवहन विभाग की स्थिति क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी परिवहन विभाग में कंडक्टरों के 1200 पद खाली हैं। JNNURM के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो 800 बसें दीं, उनमें से आज भी 200 बसें डिपुओं में खड़ी हैं। फिर कैसे इस विभाग को सही कह सकते हैं। मंत्री जी ने स्वयं इस माननीय सदन में मान लिया कि इस विभाग की बहुत बुरी हालत है। पिछले कल के एक उत्तर में उन्होंने यह माना, जो आज की अख़बारों में भी आया है। परिवहन निगम में 4-4 महीनों से रिटायर कर्मचारियों को पैंशन नहीं मिल रही है। परिवहन निगम कर्मचारियों को बिल पिछले 2 वर्षों से मैडिकल नहीं मिल रहे है। लेकिन जो लाखों-करोड़ों लेने वाले उच्च अधिकारी हैं उनको रि-इंबर्समैंट बिल मिल रहे हैं। जिन

16.03.2016/1620/SLS-AS-2

गरीब कर्मचारियों ने सारी आयु परिवहन निगम की नौकरी की है, उनको 4-4 महीनों से पैंशन तक नहीं मिल रही है। परिवहन निगम के 5000 रिटायर कर्मचारियों को 4 महीनों से पैंशन नहीं मिल रही है। धर्माणी जी, एक बात की ओर आप भी ध्यान दें। आप कभी-कभी लोगों को आंकड़ों में उलझा कर फंसा लेते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। JNNURM बसों का जो MoU sign हुआ, उसमें कैरियर लगाने का प्रावधान था। एक कैरियर लगाने पर 50,000 रुपये ख़र्च होता है। फिर यह बसें कलस्टर के अंदर चलनी थीं। इन्होंने कलस्टर तोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में यह बसें चला दीं। ग्रामीण क्षेत्र में जो बसें चली हैं उनमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो किसान अपना सामान या सब्जी बगैरह लेकर आएगा, वह कैरियर के बिना उसे कैसे ले जाएगा? MoU कैरियर के साथ साईन हुआ लेकिन जब बॉडी लगी तो कैरियर नहीं लगे। इसमें मुझे घोटाले की बू आती है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, इसमें थोड़ा गौर करें और छानबीन करें। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं केवल 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

धर्माणी जी, आप कहते हैं कि केंद्र से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जय राम जी ने अभी ज़िक्र किया कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जो 90:10 की स्कीम बनाई, उससे 72000 करोड़ रुपये आपको मिलेंगे जबकि पहले आपको केवल 21000 करोड़ रुपये मिलते थे। मनरेगा के बारे में अनिल जी बड़े ज़ोर से जवाब

देते हैं। मनरेगा के अंदर 724 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था जबकि आपने केवल 334 करोड़ रुपया ख़र्च किया। आप मनरेगा के लिए कहते हैं कि इसमें दिल्ली से बजट नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्दी योजना चालू की गई। मैं बताना चाहूंगा कि 10वीं कक्षा तक यह वर्दी हमने शुरू की थी। बाद में आपने प्लस वन तथा प्लस टू के लिए शुरू की जिसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। लेकिन यह वर्दी कब मिली? वह पूरे साल में अभी मिली है जबकि पूरा साल बच्चों ने अपनी वर्दियां खरीद कर गुज़ारा किया।

जारी ...श्री गर्ग जी

16/03/2016/1625/RG/AS/1

श्री रिखी राम कौंडल------क्रमागत

इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वर्दी योजना जो शुरू की गई है उसका नाम बदलकर 'मुख्य मंत्री वर्दी योजना' जो +1 और +2 के लिए किया है, तो इसमें समय पर वर्दी मिले। अध्यक्ष महोदय, धर्मशाला में भी माननीय सदन में एक विषय उठा था कि वर्दियों के सैंपल में घोटाला हुआ है। इन्होंने आदेश किया था कि मैं इसकी एफ.आई.आर. करुंगा, लेकिन आज तक हमें उस बारे में पता ही नहीं लगा कि उस बारे में क्या छानबीन हुई और किस प्रकार घटिया वर्दियां खरीदी गईं? यह तो शिक्षा विभाग ने स्कूल खोले। स्कूल खुलने भी चाहिए। हमारा एक पहाड़ी राज्य है और लोग दूर-दूर नहीं जा सकते। इसलिए स्कूल खुलने चाहिए। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है और शिक्षा का सुधार कैसे होगा? स्कूल खोलने के लिए आपका धन्यवाद। आज भी सारे प्रदेश में टी.जी.टी. के 1500 पद खाली हैं, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? लैक्चजर्ज के 900 पद खाली हैं, मुख्य अध्यापक के 150 और प्रिंसीपल के भी लगभग 10 से 25 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग की यह स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, धर्माणी जी ने केन्द्र पर पर आरोप लगाया कि हमें केन्द्र से कुछ नहीं मिल रहा है। यह 22 दिसम्बर, 2015 का पत्र है। आपने अम्रुत योजना में डी.पी.आर. भेजी और 158.82 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. भेजी जिसमें 79.41 करोड़ रुपये आपको

एक किस्त का मिला और जब इस किस्त को आप खर्च करेंगे, तो दूसरी और उसके बाद तीसरी किस्त मिलेगी। यह सारा-का-सारा पैसा केन्द्र की तरफ से आपको मिल रहा है। तो इस माननीय सदन के अंदर यह कहना कि केन्द्र हमें कुछ नहीं दे रहा है, ठीक नहीं है।

मुख्य मंत्री : हमने कभी यह नहीं कहा कि केन्द्र हमको कुछ नहीं दे रहा है, मगर जिस मात्रा में हमको मिलना चाहिए था और पहले मिलता था, उस मात्रा में नहीं आ रहा है।

श्री रिखी राम कौंडल : मुख्य मंत्री जी, आपके चेलें-चांटें बोल रहे हैं और किशोरी लाल जी ने अभी कहा कि केन्द्र ने हमें कुछ नहीं दिया। जबकि मनरेगा का इस समय सबसे ज्यादा बजट प्रपोज़ करके भेजा। माननीय मुख्य मंत्री जी आप इस बात को मानते हैं कि फैडरल सिस्टम है, इस प्रदेश में संविधान के मुताबिक फैडरल सिस्टम है या नहीं? जब तक आप केन्द्र को प्रस्ताव नहीं भेजेंगे, तो आपको केन्द्र से कैसे पैसा मिलेगा? आप डी.पी.आर. बनाकर भेजिए, प्रस्ताव बनाकर भेजिए।---(व्यवधान)---

16/03/2016/1625/RG/AS/2

आप जितना पैसा मनरेगा का खर्च करेंगे, उतना पैसा आपको मनरेगा का मिलेगा। आप यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट भेजिए, आपको केन्द्र से पैसा मिलेगा।

अध्यक्ष : माननीय कौंडल जी, अब आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया। Now, I will not allow.

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, अब मैं समाप्त करने जा रहा हूं। मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष : अब आप कितनी देर बोलेंगे?

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में प्रश्न संख्या 2935 आज ही लगा था।--(व्यवधान)---- सोहल लाल जी, सुन लीजिए।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सोहन लाल) : हम तो 15 मिनट बोले, आप 25 मिनट से बोल रहे हैं।

श्री रिखी राम कौंडल : यह तो अध्यक्ष का prerogative है, यह इनका अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। आप बैठे रहिए।

अध्यक्ष : आप बहस क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात रखिए।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इनको रोकिए। मैं समाप्त कर रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग से संबंधित श्री महेन्द्र सिंह का पानी के बारे में प्रश्न संख्या 2935 लगा था। पता चला कि इस प्रदेश में 616 स्कीमें बहाव और लिफ्ट की हैं जिनमें से 383 योजनाओं के फिल्टर बैड्ज बंद पड़े हैं। कहां से आप क्लेम कर सकते हैं कि हम स्वच्छ पानी लोगों को दे रहे हैं? बिलासपुर में वर्ष 2013-14 में माण्डवा में पीलिया फैल गया था जैसे आज शिमला में पीलिया फैला है। जब आपके 383 फिल्टर बैड्ज बंद पड़े हैं, तो कहां से क्लेम कर सकते हैं कि इसमें पारदर्शिता है? यह आज सरकार का उत्तर है, मेरा उत्तर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पानी की जो पुरानी ग्रेविटी की स्कीमें बनी हैं उनमें सबमें चूना जमा हुआ है।

16/03/2016/1625/RG/AS/3

मुख्य मंत्री : आप महेन्द्र सिंह जी को कोट कर रहे हैं, मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि श्री महेन्द्र सिंह जी बढ़ा-चढ़ाकर बात करते हैं, वे बढ़ा-चढ़ाकर बात करते हैं।

श्री रिखी राम कौंडल : यह आपकी सरकार का जवाब है।

मुख्य मंत्री : अगर हमने नुक्ता-चीनी करनी हो,

एम.एस. द्वारा जारी

16/03/2016/1630/MS/AS/1

मुख्य मंत्री जारी---------

तो हम भी कर सकते हैं। We should base our speeches on some facts. चलो आप 15 प्रतिशत झूठ भी बोल लो लेकिन 80 प्रतिशत झूठ बोलोगे तो क्या फायदा है?

श्री रिखी राम कौंडलः यह आज का प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब सरकार की तरफ से मैं कोट कर रहा हूं। मैं महेन्द्र सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूं। यह आज का सवाल था। -(व्यवधान)-

मुख्य मंत्रीः आप बजट पर बोलिए।

श्री रिखी राम कौंडलः मैंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को बोला है कि जो खराब पड़े हैं इनको ठीक करवा दीजिए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिले। जहां पर पुरानी ग्रेविटी की स्कीमें बनी हैं, उनका सारे प्रदेश का सर्वे करवाइए। उन पाइपों में चूना जमा है इसलिए उन पाइपों को बदलने का प्रबंध कीजिए। तो ये कुछ बातें थीं।

मैं अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए कृषि विभाग के बारे में कहूंगा कि आपने गौ-सदनों के बारे में उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना की है। -(घण्टी)- किसानों और बागवानों का थोड़ा तो ध्यान रखिए। अध्यक्ष जी, आपने घण्टी बजाई है इसलिए मैं इस आसन की कद्र करता हुआ केवल यही कहूंगा कि यह जो बजट इस मान्य सदन में पेश किया गया है, यह आंकड़ों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। इसमें जो कुछ अच्छी बातें हैं, उनका मैंने स्वागत किया और जो कुछ सुझाव देने की बात थी, मैंने सुझाव दिए हैं। आप इन सुझावों पर अमल करें। यदि आप अमल नहीं करेंगे तो जैसे हम भी आपकी बातों पर थोड़ा कम अमल करते थे इसलिए इधर आ गए हैं। अगर आप भी हमारी बातों पर अमल नहीं करेंगे तो आपको भी इस तरफ आना पड़ेगा। यह प्रजातंत्र है। इसमें किसी की स्थायी कुर्सी न इस तरफ है और न ही उस तरफ है। जब आप लोग सुझाव देते थे तो हमारे लोग भी माननीय मुख्य मंत्री तथा सदन के नेता का गुणगान करने में लगे रहते थे। ऐसे ही आपके लोग भी गुणगान करने में लगे रहते हैं। ध्यान कीजिए

16/03/2016/1630/MS/AS/2

और जो हमने सुझाव रखे हैं उन सुझावों को अमल में लाइए। इससे आपका भी सुधार होगा, हमारा भी सुधार होगा और लोग भी सुखी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16/03/2016/1630/MS/AS/3

Speaker: Please restrict yourself to time.

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष जी, एक बात है। माननीय सदस्यों के बोलने के समय का थोड़ा बैलेंस तो रखिए। कोई माननीय सदस्य 20 मिनट, कोई 30 मिनट और कोई 18 मिनट ही बोल रहे हैं। पक्ष के माननीय सदस्यों को बोलने के लिए 15 मिनट भी नहीं मिलते हैं। हरेक माननीय सदस्य को यहां बोलने का हक है लेकिन उसका रेशो होता है। जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे, सबको बोलने का एक बराबर समय मिलना चाहिए।

अध्यक्ष: There is a suggestion, I will stop recording thereafter, उस समय के बाद मैं रिकॉर्डिंग बन्द कर दूंगा।

अब चर्चा में मुख्य संसदीय सचिव, श्री मनसा राम जी भाग लेंगे।

16/03/2016/1630/MS/AS/4

मुख्य संसदीय सचिव (श्री मनसा राम): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने

मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मैं इस मान्य सदन का वर्ष 1967 का सदस्य हूं। मुझे गर्व है कि उस वक्त हिमाचल निर्माता डॉ0 वाई0एस0 परमार हिमाचल के मुख्य मंत्री थे और उनके मंत्रि-मण्डल में वर्ष 1972-77 तक मुझे काम करने का मौका मिला। हमें खुशी है कि डॉ0 परमार के बाद हिमाचल की जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को आज मुख्य मंत्री के रूप में चुना है जो छः बार हिमाचल के मुख्य मत्री रहे हैं। भारत सरकार में भी दो बार ये मंत्री रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता को इस बात पर गर्व है। मैं समझता हूं कि छः बार मुख्य मंत्री रहने के बाद बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से यह बजट तैयार किया गया है। इस बजट में गरीबों की भावनाओं और हिमाचल प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। अध्यक्ष जी, मैंने कई बजट पढ़े हैं। मैंने कम-से-कम 30 बजटों पर भाषण भी दिए हैं और पढ़े भी हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि इस बार जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है यह इनको "मील का पत्थर" साबित होगा और इस तरह सातवीं बार हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बनने का ये रास्ता बना रहे हैं। हमें गर्व है कि इनकी योग्यता, कूट राजनीति व कुशल प्रशासक होने के कारण सातवीं बार ये हिमाचल के मुख्य मंत्री बनेंगे। आप हैरान होंगे। आप जो मर्जी बोलो राजनीति है। लेकिन जब ये विपक्ष में होते थे तो इनको पक्ष वाले गाली देते थे और जब पक्ष में होते हैं तो विपक्ष वाले गाली देते हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

16.03.2016/1635/जेएस/एजी/1

श्री मनसा राम (मुख्य संसदीय सचिव)ः----जारी-----

आप देखेंगे कि इस उम्र में ये बजट पर साढ़े तीन घंटे बोले हैं। ज़वान आदमी भी साढ़े तीन घंटे खड़े हो कर नहीं बोल सकता है। उस दिन आप लोग बैठे-बैठे तड़फ रहे थे जब माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे। हमें गर्व है इनको देव शक्ति है और वह देव शक्ति उन लोगों को भगवान देता है जो कि लोगों के शुभ-चिन्तक होते हैं। गरीब लोगों की तरफ जिनका मन होता है । उनके लिए काम करने की इच्छा होती है। इसलिए

अध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है कि प्रदेश को एक बहुत सशक्त और सौभाग्यशाली मुख्य मंत्री प्राप्त हुए हैं। इन्होंने इस बजट के निर्माण में इतना परिश्रम किया है और हिमाचल प्रदेश की जनता की भावना को समझ कर उनके आधार पर यह बजट तैयार किया है। दिन-रात कार्य करने कि क्षमता प्रभु कृपा और देवी-देवताओं के आर्शीवाद से मिलती है। सत्र में सारे दिन भर काम करने के बाद आप देखेंगे ये हजारों लोगों को मिलते हैं। हम हैरान होते हैं कि इतना काम सदन के अन्दर करते हैं और उसके बाद बाहर लाईन लगी होती है और हम तो थक के यहां से भाग जाते हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी हजारों लोगों की भावनाओं को, हजारों गरीब लोगों की बातों का समाधान करते हैं और वे भी इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बजट गागर में सागर की तरह बना है। इससे हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्यों की गति तेज़ होगी। अस्पतालों में 56 दवाईयां मुफ्त मिलेंगी। दवाईयां ही नहीं मिलती और गरीब लोग तड़फते हैं, लेकिन अब 56 दवाइयां मुफ्त मिलेगी। कोई बीमारी ऐसी नहीं रहेगी जिसमें ये दवाइयां गरीबों को न मिलें और उनको उससे लाभ न पहुंचे। एक हैरानी की बात और है कि यह कर मुक्त बजट है। कर मुक्त बजट लोगों के लाभ के लिए है, माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। बस अड्डों के लिए भी उन्होंने 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है क्योंकि हमारे प्रदेश में कई जगह बस अड्डे नहीं है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि करसोग में भी बस अड्डा नहीं बना है। इनकी कृपा से वहां पर हमें बस डिपो मिला, लेकिन वहां पर भवन नहीं है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि करसोग में भी बस अड्डे के भवन के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। हमें खुशी

16.03.2016/1635/जेएस/एजी/2

है कि इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने 13 हजार नौज़वानों के लिए रोजगार का इन्तज़ाम किया है। यह भी बधाई की बात है। 12वीं कक्षा तक वर्दी फ्री देने का निर्णय किया है। गरीब बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। कुछ कहते हैं कि इस तरह से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन जो अमीर लोगों के बच्चे हैं उनके पास तो वर्दी बगैरह सब कुछ होती है क्या वे नहीं बिगड़ते? गरीब बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। वर्दी देने से वे खुश होते हैं। स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मिल भी मिलता है। ये सरकार गरीबों के हक की है। जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं उनके लिए ये सरकार काम करती है।

ऐजुकेशन लोन में भी छूट दी गई। इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। एक रूपये में स्वास्थ्य बीमा। यह एक अनोखी योजना गरीबों के लिए है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने नई बात कर दी क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी के समय में भी 50 लाख रूपया विधायक निधि में था लेकिन वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री जी ने 75 लाख किया और अब 1 करोड़ रूपए कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में बहुत कुछ है। पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा है। 400 किलोमीटर नई सड़कें, बीच में पुल और 500 किलोमीटर नए मार्गों को पक्का करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्लैक स्पॉट पर क्रैश बेरियर लगाने के लिए 50 करोड़ रूपए रखे गए हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के रख-रखाव के लिए भी 20 करोड़ रूपए की योजना। लोक निर्माण विभाग को 3 हजार 54 करोड़ रूपए का बजट। सस्ती बिजली के लिए 410 करोड़ रूपए। गैर हिमाचली से शादी की ग्रांट पर भी 20 हजार रूपए से 40 हजार और जो नारी सदन में शादियां होती हैं उसके लिए तो 51 हजार रूपए कर दिया। इसके लिए मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

16.03.2016/1640/SS-DC/1

श्री मनसा राम, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

कि गरीब महिलाओं के लिए उन्होंने अच्छा प्रबंध किया है। बेटियों को नौकरी में आरक्षण, यह भी बजट के अंदर बहुत बड़ी बात है। इसमें गरीब बच्चियों को नौकरी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के जो देवी-देवता हैं उनमें बहुत से मंदिरों का निर्माण माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। अभी मैं मंडी में था, देवता के कारदार और बजंतरी इनकी बहुत तारीफ करते हैं। सारे देवताओं का आशीर्वाद माननीय मुख्य मंत्री जी पर है। इन्होंने इनका (कारदार) 10 प्रतिशत नज़राना भी बढ़ाया है।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन और डाकखाना खाता योजना शुरू की। यह भी बहुत सराहनीय योजना है। किसान स्वरोजगार योजना के लिए 111 करोड़ रुपया, बेसहारा पशुओं द्वारा खेती को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए खेती में बिजली वाली तारें लगाने के लिए 60 प्रतिशत उपदान दिया जायेगा। जोकि गांव के किसानों के हित में है।

खेतों में सिंचाई के लिए कुएं, टयूबवैल आदि लगाने के लिए 80 प्रतिशत उपदान दिया जायेगा। पंचायत चौकीदार, सिलाई टीचर, जलवाहकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गई है। पांच साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुके कर्मचारी नियमित होंगे। यह कर्मचारियों के लिए एक नयी उपलब्धि है। कर्मचारियों को एक अगस्त, 2016 से 50 प्रतिशत अंतरिम राहत दी गई है। 31 मार्च, 2016 से तथा 30 सितम्बर, 2016 से पांच साल पूरे करने पर अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, अनुबंध कर्मचारियों की पारिश्रमिक ग्रेड पे 50 प्रतिशत बढ़ाई जायेगी। यह बजट हिमाचल प्रदेश के गरीबों के लिए है। हिमाचल प्रदेश के उन लोगों के लिए है जोकि गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। दिहाड़ीदार की दैनिक मजदूरी 180 से 200 रुपये बढ़ाना प्रस्तावित है। 31 मार्च, 2016 तथा 30 सितम्बर, 2016 को 7 साल का सेवाकाल पूर्ण करने वाले सभी दिहाड़ीदारों को नियमित किया जायेगा। 31 मार्च, 2016 तथा 30 सितम्बर, 2016 को 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले अंशकालिक कर्मियों को दिहाड़ीदार बनाया जायेगा। अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 1700 रुपये से बढ़ाकर 1900 रुपये किया जायेगा। वाटर गार्डों का सहायता अनुदान 1350 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किया जायेगा। सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 2000 रुपये से बढ़ाकर 2300 रुपये किया जायेगा।

16.03.2016/1640/SS-DC/2

पंचायत चौकीदारों के लिए सहायता अनुदान प्रतिमाह 1850 से 2050 किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इतना बढ़िया बजट मैंने पहली बार देखा है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं समझूंगाकि भगवान् की कृपा से वे मनोवैज्ञानिक हो गये हैं और लोगों की भावनाओं को समझते हैं। गरीब लोगों का उन पर बहुत आशीर्वाद है। अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से अर्ज करना चाहूंगा कि आई0टी0 भवन निर्माण करसोग में शुरू करने के लिए पैसा भी आया है। उसको शुरू करने के लिए मैंने बाली जी को कहा था, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री मेरी इसमें मदद करेंगे। मिनी सचिवालय जो इन्होंने करसोग में लिया है उसके निर्माण में भी ये मेरी सहायता करेंगे। तत्तापानी जल स्त्रोत के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का अत्यंत आभारी हूं। जमदग्नी ऋषि ने वहां पर तप किया है और वहां पानी के चश्मे दरिया के

साथ-साथ थे और अब माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से उनको आम लोगों के नहाने के लिए जैसे वे पहले थे उसी तरह से उसके लिए प्रावधान कर रहे हैं। जिसके लिए मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मेरे पास 11 सड़कें हैं जिनकी पिछले तीन सालों से एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस नहीं हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगाकि इसमें मेरी मदद करने के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश करें। मेरा इमला-बिमला खड्डों का तटीयकरण ज़रूरी है। करसोग में दो बड़ी सुन्दर खड्डे बहती हैं उसके तटीयकरण के लिए भी केस चला है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसमें मेरी मदद करेंगे। करसोग में फायर ब्रिगेड, सॉयल टैस्टिंग, सीवरेज प्रारम्भ करने के लिए,

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2016/1645/केएस/एजी/1

श्री मनसा राम (मुख्य संसदीय सचिव) जारी----

बस अड्डे का निर्माण करने के लिए, डिम लाईट प्रॉब्लम, उठाऊ पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए मैं प्रार्थना करुंगा और मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस तरह से हम पर कृपा रखते हैं और जिस तरह से करसोग क्षेत्र में काम किया है उसी तरह से सारे हिमाचल प्रदेश में इन्होंने काम किया है। ये किसी से भेदभाव नहीं करते। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी ने देश में इतने साल काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग देश में सिर्फ 1/3 है और उसमें भी आप कुछ नहीं कर सके। आप कहते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते लेकिन अगर मोदी जी ने झूठ नहीं कहा होता कि 15 लाख रु0 प्रत्येक के अकाऊंट में जाएगा और अच्छे दिन का वायदा न किया होता तो आपकी सरकार केन्द्र में सत्ता में आनी ही नहीं थी। आप केवल इन दो प्वाईंट्स पर जीते हुए हैं, यह झूठ है या नहीं? दो साल हो गए हैं लेकिन आप एक बात बताओ कि अच्छे दिन कहां आए? 15 लाख रु0 जो प्रत्येक के अकाऊंट में आना था वह कहां गया? एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करना बहुत आसान है और राम मंदिर को भी देखो फिर यह भी देखो, जैसे आप कहते हैं कि हिमाचल सरकार ने तो ऋण ले लिया। क्या आपने भारत सरकार का बजट पढ़ा? भारत सरकार को भी कर्जा लेना है और सरकार चलाने

के लिए यह करना पड़ता है। बाहर के मुल्कों से उधार लाना पड़ता है और देना भी पड़ता है। एक-दूसरे की मदद करनी पड़ती है। राज्यों में भी प्रत्येक राज्य को दूसरी जगह से पैसा आता भी है और दूसरे राज्यों को देना भी पड़ता है। यह कौन सी नई बात है? यह तो आप भी करते आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी सी बात कह कर समाप्त करता हूं कि

खुशहाल होगा हिमाचल, राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में,

बहारें लाएगा बजट मुख्य मंत्री जी के परिश्रम से।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16.03.2016/1645/केएस/एजी/2

अध्यक्षः अब डॉ0 राजीव सैजल चर्चा में भाग लेंगें। कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें क्योंकि समय बहुत हो गया है। अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

डॉ0 राजीव सैजलः माननीय अध्यक्ष जी, 8 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के अंदर जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए, मैं उन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि सदन में कहा जा रहा था और यह फैक्ट भी है कि यह माननीय मुख्य मंत्री जी का 19वां बजट है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से बधाई देता हूं लेकिन जो बजट का सार है, अगर सत्ता पक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि यह बजट प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने वाला बजट है तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट को शेरो-शायरी के माध्यम से सजाने की चेष्टा की है और आंकड़ों के माध्यम से भी इसको सजाने का प्रयास किया है। Wilhelm Stekel एक ऑस्ट्रीयन विचारक हुए उन्होंने कहा "statistics is the art of lying by means of figures" और यहां पर जो यह बजट प्रस्तुत किया गया, उसको देखकर यहां पर उनकी यह उक्ति मुझे बिल्कुल ठीक नज़र आती है। जैसा कि कई सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि आज प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लगभग 47,284/- रुपये का ऋण है। विकास तब तक रफ्तार नहीं पकड़ेगा जब तक हम प्रदेश के आय के साधन बढ़ाने

पर विचार नहीं करेंगें, उसके लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाएंगें और इस ऋण से भी हमें तभी मुक्ति मिलेगी जब हम प्रदेश की आय के साधनों को संसाधनों का बढ़ाने का प्रयास करेंगें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2016/1650/av/ag/1

डॉ.राजीव सैजल ....क्रमागत

परंतु आय बढ़ाने के जो साधन है उसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? यह बहुत गम्भीर बात है मगर इसके बारे में इस बजट बुक में कुछ नहीं बताया गया है। यहां पर विपक्ष के हमारे सभी साथियों ने चिन्ता व्यक्त की है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में विकास का आधार और जिसको हम अपनी किस्मत की रेखाएं भी कहते हैं, वह सड़कें हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सड़कों की हालत खराब है और अभी माननीय सदस्य श्री कौंडल जी ने जो यहां पर डाटा दिया है कि प्रदेश में वर्तमान में कितने पद खाली है। वह पद जिनकी सड़कों को बनाने में अहम भूमिका होती है। उनकी डी0पी0आर0 और ऐस्टिमेट बनाने में मुख्य भूमिका होती है। उन अधिकारियों के कितने पद इस प्रदेश के अंदर रिक्त पड़े हैं, यह एक चिन्ता का विषय है। मैं इसके लिए एक सुझाव देना चाहता हूं कि इन पदों को भरने के लिए सरकार को आवश्यक पग उठाने चाहिए। अगर हम वास्तव में सड़कों को अपनी किस्मत की रेखाएं मानते हैं, उनको विकास का आधार मानते हैं तो सरकार को इसके ऊपर गम्भीरता से काम करना चाहिए। मैं कसौली विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। कसौली एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और मुझे लगता है कि इस बात से यहां बैठे मेरे सारे मित्र सहमत होंगे। मगर नेशनल हाई-वे 22 से कसौली को जो सड़क जोड़ती है अगर माननीय अध्यक्ष, आप कभी वहां जाएं। उसकी

हालत देखें तो आप पायेंगे तथा मुझे लगता है कि कसौली में जो पर्यटक एक बार आ जाता है वह सड़क की हालत देखकर शायद दोबारा कभी नहीं आना चाहेगा। हमें अपने प्रदेश में पर्यटन से आय के संसाधन बढ़ाने की सम्भावना नजर आती है। मगर जब सड़कों की स्थिति इतनी खराब है तो हम यहां पर पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे प्रसिद्ध स्थान है उनको देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी हैं और ऐसे स्थानों को जो सड़कें जोड़ती हैं वे सड़कें निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया होनी चाहिए। यहां पर हमारे प्रदेश में जो बाहर से लोग आते हैं और हमारी सड़कों की हालत देखते हैं तो वह इसकी चर्चा अन्य प्रदेशों में करते हैं जिससे हमारे प्रदेश की अच्छी छवि प्रस्तुत नहीं होती। मैं यहां पर एक दूसरी सड़क की चर्चा भी करना चाहूंगा जो कि परवाणू-बरोटीवाला वाया पट्टा-

16.3.2016/1650/av/ag/2

महलोग और कोट-बैजा है। जब से यहां पर सरकार बदली है वहां उस सड़क की एक बार भी टारिंग नहीं हुई। उसके गड्ढे नहीं भरे गये। इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि आज वहां यह कल्पना करना कठिन होता है कि क्या यह सड़क कभी पक्की भी रही होगी। इस सड़क की हालत कच्ची सड़क से ज्यादा खराब है। इसी तरह से धर्मपुर से कुनिहार वाया स्पाटू सड़क है। इस सड़क की हालत भी बहुत खराब है और यही सड़क कुनिहार से भराड़ीघाट चली जाती है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि सरकार इस सड़क को डबल लेन बनाने का प्रयास करे। हमारे दाड़लाघाट के सीमेंट प्लांट से सिरमौर और दूसरे प्लेन एरियाज में सीमेंट की पूर्ति के लिए वाहन इस सड़क का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस सड़क पर वाहनों की बहुत बड़ी तादाद है। मुझे लगता है कि अगर यह डबल लेन हो जायेगी तो निश्चित तौर से एक अच्छी सड़क के रूप में विकसित होगी और इससे हमारा क्षेत्र भी विकसित होगा। नेशनल हाई-वे परवाणू से चम्बाघाट को फोर लेन किया जाना प्रस्तावित है। उसका टैंडर हो गया है। जिस फर्म को इसका टैंडर गया है उसने इस पर काम करना शुरू कर दिया है तथा वह बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें केवल अवरोध यह है कि उसमें प्रदेश सरकार अभी निजी भूमि

का अधिग्रहण नहीं कर पाई है। यह अधिग्रहण न होने की वजह से वह ठेकेदार सड़क निर्माण के लिए प्राइवेट एरिया को टच नहीं कर पा रहा है।

टीसी द्वारा जारी

16.03.2016/1655/TCV/AS/1

डॉ0 राजीव सैजल --- जारी

जिस गति से ये सड़क बन रही है उस गति से ये सड़क नहीं बन पाएगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध रहेगा कि यह जो प्राइवेट लैंड है इसमें कम्पनसैशन का मामला है। उसकी वज़ह से यह कार्य अभी तक अटका हुआ है। सरकार इस लैंड का शीघ्रातिशीघ्र ऐक्वाजिशन करें ताकि इस सड़क का निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो। पीलिया जिस प्रकार से हमारे निर्वाचन क्षेत्र में फैला वह किसी से छुपा नहीं है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहां बार-बार दावे करते हैं , उनके दावों की पोल यहां पर खुल जाती है। पीलिया शिमला में तो फैला ही लेकिन हमारा सोलन भी इससे अछूता नहीं रहा । सोलन में पानी के सैंपल फेल हुए और पीलिया के अनेकों केसिज़ रिपोर्टिड है। नाहन और मेरे अपने क्षेत्र परवाणु में पानी के सैंपल फैल हो गये और धर्मपुर में भी अनेकों केसिज़ पीलिया के हुए। इसलिए इसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। आज जब हम इतना आगे बढ़ चुकें है, तकनीक भी इतना आगे बढ़ चुकी है और हम कहते हैं कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। यह प्रदेश के लिए चिन्ता का विषय है और शर्मनाक भी है। माननीय अध्यक्ष जी, धर्मपुर हमारे निर्वाचन क्षेत्र का केन्द्र है और धर्मपुर शिमला और चंडीगढ़ से बराबर दूरी पर है। ये जो अपना एन0एच0 है इस पर अनेकों दुर्घटनाएं होती है। मैं बार-बार यहां सदन में कहता रहा हूं, जब हम रूलिंग में थे तब भी और आज भी इस बात को बार-बार यहां उठाता हूं कि धर्मपुर में एक ट्रामा सैंटर का होना बड़ा आवश्यक है। सोलन अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है। सोलन अस्पताल हमारा रीजनल अस्पताल है और इसमें हमारी जो अनेकों PHCs हैं, वहां से लोग रैफ़र होकर जाते हैं। अभी नाहन के अन्दर जो नया डा0 वाई0एस0 परमार मैडिकल कॉलेज खुला है, 4 विशेषज्ञ सोलन से वहां पर स्थानांतरित कर दिए हैं। सरकार उन पदों को भरने पर विचार करें क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई

है। धर्मपुर में अगर हम इस ट्रामा सैंटर को खोलते हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाएं जो हो जाती है और उनको तुरन्त चिकित्सीय सहायता चाहिए होती है। जब पैशेंट चण्डीगढ़ पहुंचता है, तब तक उसकी मृत्यु

16.03.2016/1655/TCV/AS/2

हो जाती है। इस प्रकार से धर्मपुर में ट्रामा सैंटर खोलने से जो इस प्रकार की मृत्यु हो जाती है उसमें कमी आएगी। पर्यटन की दृष्टि में से चुनाव क्षेत्र में अन्नत संभावनाएं हैं, वैसे तो पूरा प्रदेश हमारा बहुत सुन्दर है और इस प्रदेश का कौना-कौना प्राकृतिक सुन्दरता को लिए हुए हैं। जहां तक हमारी संस्कृति का सवाल है, उसमें हमारा एक विशिष्ट स्थान है। हमारी इसी विशिष्टता को देखते हुए डॉ0 वाई0एस0 परमार ने एक अलग राज्य की कल्पना की थी और उनकी कल्पना मूर्त भी हुई और हिमाचल अस्तित्व में आया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां तक मैं पढ़ रहा था, अनेकों योजनाएं माननीय मुख्य मंत्री जी ने पर्यटन को लेकर शुरू करने का विचार किया है। लेकिन वास्तविकता में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। हजारों टूरिस्ट परवाणु से लेकर बड़ौग तक आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई वे साइड एमेनिटी नहीं है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य जरा संक्षेप में बोलिए। टाईम बहुत हो गया है, एक मिनट बैठिए ।

अभी 5.00 बजे का टाईम हो गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संक्षेप में बोलें और 10-10 मिनट से ज्यादा न बोलें। सब कुछ पहले बोला गया है लेकिन आप वहीं बातें दोहरा रहें हैं।

(सदन की बैठक 6.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

सैजल जी बोलिए । Please finish within a short time.

डॉ0 राजीव सैजलः मैं तो समय सीमा में रहकर ही बोलता हूं, आप चाहे यहां रिकार्ड में भी देख लें ।

श्री आर0के0एस0 --- जारी

16.03.2016/1700/RKS/AS/1

डा0 राजीव सैजल द्वारा जारी....

मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्षः बहुत अच्छी बात है।

डा0 राजीव सैजलः मुझे लगता है हमारे निवार्चन क्षेत्र में जिस प्रकार से जो पर्यटन को लेकर संभावना है उसमें सरकार बड़ा अन्याय कर रही है। बजट अनुमानों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में रज्जू मार्ग खोलने के लिए चर्चा की है। मेरे चुनाव क्षेत्र में कालूझंडा से कसौली हेतु एक रज्जू मार्ग की संभावना है। हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग और जो अन्य हमारे नजदीक के प्रदेश हैं वहां के अनकों पर्यटकों के लिए यह एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। गम्भर पुल जहां देव ब्रिजेश्वर महाराज जोकि शिमला के अनकों लोगों का श्रद्धा का केंद्र है, उस स्थान को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। जो श्रद्धालू वहां पर आते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं क्रिएट की जाएं। माननीय अध्यक्ष जी (घंटी) परवाणु एक आद्यौगिक नगर है। माननीय वाजपेयी जी के आर्शीवाद से इस प्रदेश को जो पैकेज मिला था उसके कारण से परवाणु काफी विकसित हुआ था। वहां पर काफी इंडस्ट्रीज आई थी। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय रहा कि यू.पी.ए. सरकार ने उस पैकेज को वापिस लिया, अनेकों उद्योग परवाणु से, बद्दी से, बरोटीवाला से वापिस चले गए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और जैसा कि प्रश्न के उत्तर में भी आया कि हम दूसरे प्रदेशों को बिजली 2.20 रुपए की लागत से बेच रहे हैं। इंडस्ट्री को हम यह बिजली साढ़े 5 रुपए की दर से उपलब्ध करवा रहे हैं। इसको लेकर आप एक नीति बनाएं। 500 से 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट के उद्योग, जो नॉन पोल्यूटिड इंडस्ट्रीज हैं वे हिमाचल में आएं। उन्हें आप कहीं भी स्थापित करें। उसमें आप तय करें कि साढ़े 3 रुपए या 4 रुपए की दर से पर यूनिट हम उनको बिजली उपलब्ध करवायेंगे। उससे जहां एक ओर हमारे प्रदेश में उद्योग आएंगे वहीं हजारों बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार भी मिलेगा। इसके ऊपर सरकार एक नीति

16.03.2016/1700/RKS/AS/2

बनाएं, ऐसा मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। (घंटी) हमारे सोलन का मेला मां शूलनी की याद में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह एक प्रदेश स्तरीय मेला है। माननीय अध्यक्ष जी चिंता का विषय यह है कि इस मेले में राजनीतिकरण हो गया है। एक ही दल के लोग इस मेले में प्रभावी रहते हैं। हालांकि इस जिला से भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं। लेकिन कभी भी इस मेले को बेहतर बनाने के लिए उनके सुझाव नहीं लिए जाते हैं। हालांकि वे भी उस जिला का हिस्सा हैं। वह मेला उनका भी उतना ही है जितना अन्य दल के लोगों का है। इसमें मेले में दल को बीच में नहीं लाना चाहिए। इसमें हमारा भी सुझाव लिया जाना चाहिए। इसमें हमें कभी भी बुलाया नहीं जाता, हमसे विचार नहीं किया जाता है। हमारे कार्यकाल में यह मेला 10-12 लाख में निपटा करता था, सम्पूर्ण हुआ करता था, सम्पन्न हुआ करता था। आज इस मेले के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होता है। जिस तरह से उद्योगपतियों को निचोड़ा जा रहा है तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस मेले के लिए जो पैसा एकत्रित किया जाता है वह पैसा इस मेले मे प्रयोग भी होता है या नहीं? यह बड़ा चिंता का विषय है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच करवाएं और इस मेले को पारदर्शी बनाया जाए। कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, कितना पैसा कंहा लग रहा है इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए (घंटी)। अध्यक्ष महोदय, आपकी घंटी बार-बार बज रही है।

अध्यक्षः वैसे तो हजारों बातें कहने को हैं आप रैलिवेंट बोलिए, आप Wind up कीजिए।

डा0 राजीव सैजलः जहां सदस्य 20-25 मिनट बोल देते हैं, मेरे तो 16 मिनट ही हुए हैं, मैं अपनी बात समाप्त करने वाला हूं।

अध्यक्षः आप बताइए आप कितनी देर बोलेंगे मैं उतना एक्सटेंड कर देता हूं। आप कितनी देर यहां बैठेंगे। क्या आप रात के 10 बजे तक यहां बैठना चाहते हैं?

16.03.2016/1700/RKS/AS/3

डा0 राजीव सैजलः सर, मुझे समापन तो करने दीजिए।

अध्यक्षः आप समाप्त कीजिए। You can sit throughout the night. कोई बात नहीं

आप फैसला कर लीजिए कितनी देर बैठना है।

डा0 राजीव सैजलः नहीं सर, आप मुझे समापन तो करने दो।

अध्यक्षः करिए-करिए।

डा0 राजीव सैजलः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं।

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी

16.03.2016/1705/SLS-DC-1

डॉ0 राजीव सैजल ...जारी

निश्चित तौर पर यह बजट प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने वाला बजट नहीं है इसलिए मैं इस बजट से सहमत नहीं हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद। लेकिन मुख्य मंत्री जी का मैं इस बात के लिए ज़रूर धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने विधायक निधि बढ़ाई है, हमारी ऐच्छिक निधि भी बढ़ाई है और निश्चित तौर पर, प्रदेश के लिए उनकी भावना अच्छी है। इसके लिए मैं उनको शुभ-कामनाएं और बधाई देता हूं।

इन्हीं शब्दों क साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिंद।

16.03.2016/1705/SLS-DC-2

अध्यक्षः अब श्री बम्बर ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। आप संक्षेप में बोलें; बहुत लंबा न बोलें।

श्री बम्बर ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का अवसर प्रदान किया जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं कि उन्होंने विधायकों की चिंता को समझते

हुए हमारी विधायक निधि को 1.00 करोड़ रुपये किया और साथ में 5.00 लाख रुपये ऐच्छिक निधि देने का ऐलान किया ताकि हम प्रदेश के अंदर सड़कों के लिए, रास्तों के लिए, कुंओं के लिए, बाबड़ियों के लिए पैसा दे सकें, इसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। यह पैसा हम अब गरीब लोगों के उत्थान के लिए ख़र्च कर पाएंगे। मैं माननीय धूमल साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी इस कदम के लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद किया है। यह निधि प्रदेश के अंदर वीरभद्र सिंह जी ने ही शुरू की थी और इन्होंने इसको 1.00 करोड़ रुपये तक पहुंचाया है। इसके लिए हम पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों की ओर से भी राजा साहब के धन्यवादी हैं। पहले विधायकों के लिए ऐच्छिक निधि नहीं होती थी जिसको आपने पहले एक साल के अंदर 2.00 लाख रुपये किया जिसे बाद में 5.00 लाख रुपये कर दिया। यह एक बहुत बड़ा कदम है।...(व्यवधान)... बढ़ा देंगे। आप मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते रहिए। मुख्य मंत्री जी आपकी भावनाओं का भी ख़याल रखते हैं। मैं कह सकता हूं कि यह भारतवर्ष के अंदर ऐसे अकेले मुख्य मंत्री हैं जिनको जवाहर लाल नेहरू जी के साथ काम करने का मौक़ा मिला। पूरे देश के अंदर ऐसे अकेले मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ही हैं जो सबका ख़याल रखते हैं। इनकी डिक्सनरी में कोई भेदभाव नहीं है। बढ़ाई गई इस निधि का फायदा न केवल कांग्रेस पार्टी के विधायकों को मिलेगा बल्कि आपको भी इसका बराबर का लाभ दे रहे हैं। इसके लिए अगर आप इनका धन्यवाद करते हैं तो मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने अच्छे काम के लिए पहली बार मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद किया है। जो बजट उन्होंने दिया है, इसके अंदर हर वर्ग का जो ख़याल रखा गया

16.03.2016/1705/SLS-DC-3

है, उसके लिए भी आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। आप छठी बार मुख्य मंत्री बने हैं। कोई व्यक्ति छठी बार यों ही मुख्य मंत्री नहीं बनता। हम और आप लोग विधायक बन कर आए हैं। हमने कितनी मेहनत की होगी, तब जाकर हम विधायक बने; यह हम अपनी आत्मा से पूछें। जो दूसरी या तीसरी बार विधायक बने हैं, उनको मालूम है कि कैसे बनते हैं। जो छठी बार मुख्य मंत्री बना, उनके तजुर्बे के लिए भी आप लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। यह अवसर बार-बार

नहीं मिलते। हम और आपको इस सदन में बैठने का मौक़ा बार-बार नहीं मिलेगा। और इस प्रकार के तजुर्बेकार नेताओं के साथ बैठने का मौक़ा भी नहीं मिलता जिन्होंने प्रथम प्रधान मंत्री के साथ काम किया हो। वाजपेयी साहब के साथ भी इन्होंने काम किया है। वह भी इनका सम्मान करते हैं। प्रदेश को इस प्रकार के मुख्य मंत्री इस मिले हैं जो प्रदेश के हित के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और दिन-रात काम कर रहे हैं। उनके बारे में इस हाऊस में कभी-कभी जब कई लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो दुख होता है। मैं समझता हूं कि इस हाऊस के अंदर वरिष्ठ नेता तो कम-से-कम भाषा का ध्यान रखें।

जारी ...श्री गर्ग जी

16/03/2016/1710/RG/AS/1

श्री बम्बर ठाकुर------क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, कल श्रीमती सरवीन चौधरी बात कर रही थीं कि मुख्य मंत्री तो फट्टों के मुख्य मंत्री हो गए। उनको यह मालूम होना चाहिए कि प्रदेश में कोई जिला या गांव ऐसा नहीं है जहां मुख्य मंत्री की पट्टिकाएं नहीं लगी हों। जिलों या गांवों के अंदर ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों के अंदर भी उनकी पट्टिकाएं लगी हैं तब जाकर वे छठी बार मुख्य मंत्री बने हैं। ऐसे मुख्य मंत्री नहीं बनते। वे लोगों के दरबार लगाते हैं। रात को जब पूरा हिमाचल प्रदेश सो जाता है और राजा वीरभद्र सिंह जी लोगों की फाईलों पर साईन कर रहे होते हैं। जो मुख्य मंत्री एक-एक बजे तक काम करता हो, उनके बारे में आपको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आपकी पार्टी सत्ता में थी, तो चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन आपने भी बनाए थे। उस समय को भी यादि करिए। आपने भी सी.पी.एस. बनाए थे। आप कोर्ट में भी गए, लेकिन फिर जब आपकी पार्टी सत्ता में आई, तो फिर आपने क्यों बनाए? इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करुंगा कि उन्होंने 'मुख्य मंत्री कन्यादान योजना' को 25,000/-रुपये से बढ़ाकर 40,000/-रुपये

किया। पहले इसको 21,000/-रुपये से 25,000/-रुपये किया था और अब 25,000/-रुपये से 40,000/-रुपये किया है। आपने क्या किया, आप बताइए? आपने अपने शासन में कितना किया? काम कुछ करते नहीं, केवल मात्र हल्ला करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि देखा जाए, तो स्कूलों में वैसे वाटर कैरियर की जरूरत नहीं है। हर जगह नलके लगे हैं। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने देखा और विधवा और बेसहाराओं या अपंग लोगों को रोजगार देने के लिए उन्होंने वाटर कैरियर नाम का एक पद शुरू किया। उन्होंने बेसहारा, विधवाओं और अपंगों को रोजगार दिया। इसमें प्रदेश में हजारों बेसहारा लोगों को रोजगार मिला। ये उसका विरोध करते हैं। अब इनके मानदेय को भी 1700/-रुपये से बढ़ाकर 1900/-रुपये किया गया है। ये इसका विरोध कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने वाटर गार्ड को 1350/-रुपये से 1500/-रुपये किया। मुझे नहीं समझ आता कि आप इन चीजों का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि बजट कुछ नहीं है। हमने वाटर कैरियर

16/03/2016/1710/RG/AS/2

लगाए और उनका मानदेय बढ़ाया और वाटर गार्ड का मानदेय बढ़ाया, तो क्या यह गलत
काम है? यह मैं इनसे जानना चाहता हूं। सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय भी 2000/-रुपये से बढ़ाकर 2300/-रुपये किया। लेकिन ये इसका भी विरोध कर रहे हैं। पंचायत चौकीदार का मानदेय 2050/-रुपये किया। ये इसका भी विरोध कर रहे हैं। विद्या उपासकों का मानदेय दोगुणा किया गया। अब आपने कितना किया, बताइए। आप केवल मात्र विरोध नहीं कर रहे हैं, यदि समर्थन करते हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यदि आप विरोध कर रहे हैं, तो इसके लिए आप अपनी आत्मा को देखिए। श्री इन्द्र सिंह जी इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं इसलिए मैं भी इनका धन्यवाद करता हूं। ये कह रहे हैं कि श्री वीरभद्र सिंह जी ने इस बजट में जो विभिन्न श्रेणियों के मानदेय बढ़ाए हैं, ये इस सबका समर्थन करते हैं। इसलिए मैं भी इनका धन्यवाद करता हूं। ऐसा होना चाहिए। आप अभी नए विधायक हैं, आप इनसे सीखिए, ये पुराने आदमी हैं। अच्छे कामों का धन्यवाद करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'मुख्य मंत्री सड़क योजना' चलाई। कुछ हमारी ऐसी सड़कें हैं जो लिंक रोड्ज हैं। अन्तिम गांव जो हमारा बचता है उसको सड़क से जोड़ने के लिए यह योजना चलाई गई है। क्या ये इसका भी विरोध कर रहे हैं? इस योजना का तो समर्थन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 'मुख्य मंत्री आवास योजना' भी इस बजट में शुरू की है। पहले कल्याण विभाग की तरफ से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों मकान बनाने के लिए पैसा मिलता था, लेकिन अब सामान्य वर्ग को भी मकान बनाने के लिए 75,000/-रुपये मिलेंगे। यदि हम माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सबको श्रेय न दें, इनका धन्यवाद न करें, तो मैं समझता हूं कि उनके साथ यह बेईमानी होगी, प्रदेश की जनता के साथ बेईमानी होगी। यदि हमने जनरल कम्युनिटी के लोगों के गरीब लोगों को इस प्रकार से 75,000/-रुपये मकान बनाने के लिए देने का इन्तजाम किया है, तो इसके लिए यदि हम उनको मुबारकवाद न दें, उनका धन्यवाद न करें, तो यह ठीक नहीं है।

एम.एस. द्वारा जारी

16/03/2016/1715/MS/AS/1

श्री बम्बर ठाकुर जारी---------

मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आप इसका विरोध करते हैं? क्या इसका विरोध होना चाहिए या इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए? प्रदेश के स्वर्ण लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनको पहले इसमें शामिल नहीं किया जाता था। अब उनको मकान देने का फैसला मुख्य मंत्री जी ने किया है इसके ऊपर ज़रा आप चिन्तन कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विरोध करने के लिए आप खड़े हो जाएं। कल गोविन्द सिंह ठाकुर जी कह रहे थे कि यह बजट महिला विरोधी, मज़दूर विरोधी और कर्मचारी विरोधी है। इन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसके बारे में यह न बोला हो कि ये विरोधी नहीं है। सबका विरोध बता दिया। मज़दूरों की दिहाड़ी मुख्य मंत्री जी ने बढ़ाई

है क्या यह बजट विरोधी है? ये हमारा जो बजट है जिसमें मज़दूरों की दिहाड़ी बढ़ाने का प्रावधान किया है, अब आपके सदस्य कह रहे हैं कि यह बजट मज़दूर विरोधी है। किसानों के खेतों में आवारा पशु घुस जाते थे और उनकी फसलें बर्बाद करते थे इसलिए किसानों के बारे मुख्य मंत्री जी ने सोचा और बाड़ लगाने की बात की है। आप इसका विरोध कर रहे हैं? -(व्यवधान)- नहीं कर रहे हैं तो आपका धन्यवाद। लेकिन यहां पर माननीय सदस्य गोविन्द सिंह ठाकुर जी ने कहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको समझाइए कि मुख्य मंत्री जी ने किसानों के हित में बाड़ लगाने का इंतजाम करने के बारे में सोचा है। यदि आप उसका धन्यवाद कर रहे हैं तो मैं आपका आभारी हूं लेकिन जो सदस्य इसका विरोध करते हैं उनको थोड़ा समझाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा 35 करोड़ रुपये का इंतजाम हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्य मंत्री जी ने हैण्ड पम्प लगाने के लिए किया है। अभी महेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि हैण्ड पम्प के लिए एक-मुश्त पैसा क्यों रखा, उसकी एलोकेशन चुनाव क्षेत्रवार करनी चाहिए। उनको यह मालूम होना चाहिए कि ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर, ये जिले हिमाचल प्रदेश के सबसे गर्म हैं। यहां पर ज्यादा हैण्ड पम्प लगते हैं और किन्नौर, शिमला तथा लाहौल-स्पिति में कम लगते हैं। इसलिए इसके लिए एलोकेशन एक-मुश्त नहीं हो सकती है। यह एलोकेशन गर्म क्षेत्रों के

16/03/2016/1715/MS/AS/2

मुताबिक ही होनी चाहिए और मुख्य मंत्री जी ने ठीक की है। जो लोग इसका विरोध करते हैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि उनको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। यह पहली बार हुआ है कि 35 करोड़ रुपये का प्रावधान हैण्ड पम्प लगाने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्य मंत्री जी ने किया है। इसका विरोध मत कीजिए।

इसी तरह से मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर नये बस अड्डे बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। हमारे बिलासपुर में जो बस अड्डा है उसकी 18 वर्षों के बाद आज हमने काया-कल्प कर दी है जबकि आपके राज में ऐसा था कि जब बस स्टैंड के अंदर हम छोटी गाड़ी लेकर जाते

थे तो बम्पर को सिर पर उठाकर लाना पड़ता था। गाड़ी वहां से पूरी साबूत नहीं आती थी। वहां पांच-पांच और छः-छः फुट के गड्ढे पड़े थे। अभी महेन्द्र सिंह जी सदन में नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं क्योंकि वे बस अड्डों के ऊपर कह रहे थे। आज आप बिलासपुर के बस अड्डे में जाकर देखिए। वहां हमने 35 लाख रुपये से इंटरलॉक टाइलें तथा अन्य काम करवाकर उस बस अड्डे की काया-कल्प कर दी है। इसके लिए भी हम मुख्य मंत्री जी का और बाली जी का धन्यवाद न करें तो किसका धन्यवाद करें? इसके लिए उनको मुबारकवाद न दें तो किसको दें, यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं? इसलिए आप लोगों को बजट का समर्थन करना चाहिए। यह बजट बहुत बढ़िया है और सब लोगों के लिए है। जो नये बस अड्डे बनेंगे उनमें कांग्रेस पार्टी के लोगों की गाड़ियां भी जाएंगी और भाजपा के लोगों की गाड़ियां भी जाएंगी यानी सबकी गाड़ियां वहां जाएंगी। इसलिए सड़कें और बस अड्डे ठीक होने चाहिए और उसके लिए यदि मुख्य मंत्री जी पैसा दे रहे हैं तो सबको दिल खोलकर इनका धन्यवाद करना चाहिए।

इसके अलावा हमारे मुख्य मंत्री जी ने जमा दो के बच्चों को फ्री में वर्दी देने की बात की है और बजट के अंदर इसका इंतजाम किया है। लेकिन उसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये इंतजाम हमने क्यों किया? फ्री बस यात्रा का इंतजाम क्यों किया? बच्चें को जगह-जगह पर हम कॉलेज क्यों खोल रहे हैं?

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

16.03.2016/1720/जेएस/एजी/1

श्री बम्बर ठाकुरः-------जारी-----

हम क्यों जगह-जगह पर आई0टी0आई0 खोल रहे हैं? इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूं कि केरल के बाद हम हिमाचल प्रदेश को साक्षर करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का साक्षर दर केरल के बराबर आए। हिन्दुस्तान में नम्बर एक पर हिमाचल प्रदेश आए। इस दिशा में श्री वीरभद्र सिंह जी काम कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने इतनी मंहगाई कर दी कि आज यदि गरीब किसान, गरीब मज़दूर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है वह बस में सफ़र नहीं कर सकता है। आपने मंहगाई कर दी। हमारा गरीब अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। गरीब का बच्चा भी आई0ए0एस0 बने, आई0पी0एस0 बनें और

एम0एल0ए0 बनें, लेकिन वह कैसे पढ़ें? केन्द्र सरकार ने इतनी मंहगाई कर दी इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी जगह-जगह पर स्कूल खोल रहे हैं ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े। यदि जाना पड़े तो बसों में फ्री यात्रा मिले। आप लोग मुझे बताईये कि केन्द्र सरकार ने जिस तरह से मंहगाई की है यदि किसी का बच्चा दूर ट्रेनिंग के लिए जाता है तो कैसे वह कमरा बाहर किराए के ऊपर लेगा? 200 से 250 रूपए तक आपने दालें कर दी। किस तरह से किसान,मज़दूर और गरीब का बच्चा बाहर ट्रेनिंग करेगा। यह इन्तजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में कर रही है। हिमाचल प्रदेश के अन्दर मुख्य मंत्री जी जगह-जगह पर कॉलेजिज़ खोल रहे हैं ताकि बच्चा घर की रोटी खा करके हमारे किसान,गरीब और मज़दूर का बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण करें। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने 200-250 रूपए किलो दालें कर दी । 47 साल की उम्र में मैंने पहली बार सुना कि 200 रूपए किलो दाल हुई हो। अगर श्री वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्य मंत्री यहां पर नहीं होते तो हिमाचल प्रदेश का गरीब और मज़दूर उनकी आप लोगों ने रीड़ की हड्डी तोड़ देते। हमने यहां पर सस्ते राशन का इन्तज़ाम किया है तब गरीब रोटी खा रहे हैं। तब जा करके मज़दूर रोटी खा रहा है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो आपने श्रमिक बोर्ड बनाया है उसके अन्दर गरीब

16.03.2016/1720/जेएस/एजी/2

को मज़दूर को आश्रय दिया है। जो मज़दूर मज़दूरी करता है उसका पंजिकरण हो रहा है। श्रमिक बोर्ड में हम गरीब के बच्चों को पढ़ाई के लिए भी पैसा दे रहे हैं। चाहे बच्चा पहली से पांचवीं तक पढ़ रहा है या पी0एच0डी0 कर रहा है। सरकार 15000 रूपए यदि बच्चा पी0एच0डी0 कर रहा है। माननीय उद्योग मंत्री माननीय मुख्य मंत्री महोदय की कृपा से उन गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है। यही नहीं यदि किसी मज़दूर के घर में कोई बीमार हो जाता है 30 हजार रूपए तक उसके ऊपर दवाईयों का खर्चा हो रहा है, ये पैसा भी श्रमिक बोर्ड में मिल रहा है। यह इन्तज़ाम हमारी सरकार कर रही है। आप इन चीजों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम इन चीजों के लिए धन्यवाद इनका न करें, माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद न करें, फिर किसका धन्यवाद करें? क्या आपका धन्यवाद करें? मज़दूरी करने के लिए हमारे भाई और बहन यदि अपने काम पर जाता है उसके लिए हमने साइकिल का इन्तज़ाम भी इस बोर्ड के

अन्दर किया है। इन्डक्शन चूल्हे का इन्तजाम भी किया है ताकि हमारी बहन जल्दी खाना बनाए। हमारा भाई और बहन जल्दी अपनी डियुटि पर साइकिल पर जाए। इसके अलावा वाशिंग मशीन तक का इन्तज़ाम हमारे माननीय मंत्री जी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस श्रमिक बोर्ड के अन्दर कर दिया है ताकि जब हमारा मज़दूर, हमारा मिस्त्री घर आए तब अपने कपड़े भी जल्दी से साफ हो, जल्दी सुबह खाना बनें और यह इन्तज़ाम माननीय मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं। ये इन्तज़ाम माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी कर रहे हैं और आप लोग इन चीजों का विरोध कर रहे हैं। मैं आप लोगों को यह सलाह देता हूं कि आप इसके लिए हमारी सरकार का धन्यवाद करें। ये बजट में इन्तज़ाम सारा आता है। तभी यह पैसा मिलता है। यदि बजट में प्रावधान न हो तो यह पैसा नहीं मिल सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं और आप लोग मत डरो। आप लोग अपने दिल में इस बात को बिठाईये और अपनी आत्मा के ऊपर हाथ रख कर कहें कि जो मुख्य मंत्री कर रहे हैं और जो माननीय उद्योग मंत्री जी कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। ये बातें मैं आपके दिल व ज़हन में बिठना चाहता हूं। मैं मुकेश अग्निहोत्री जी की तारीफ नहीं कर रहा हूं बल्कि इनके कामों की तारीफ कर रहा हूं

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

16.03.2016/1725/SS-AS/1

श्री बम्बर ठाकुर क्रमागतः

क्योंकि यह पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है कि किसी गरीब को, मजदूर को वाशिंग मशीन दे रहे हैं। यही नहीं है जिस मजदूर के घर में डिलीवरी होनी हो, उसमें 10 हजार रुपये का डिलीवरी के लिए प्रावधान किया है। अगर किसी का जन्म हुआ है तो मौत भी होनी है अगर उस मजदूर के घर में किसी की डैथ हो तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपये का प्रावधान भी किया है। अगर नैचुरल डैथ होती है तो उसके लिए 50 हजार रुपये और यदि एक्सीडैंटल डैथ होती है तो उसमें एक लाख रुपया चार लाख रुपये के अतिरिक्त मिलेगा। एक्सीडैंटल डैथ होती है तो उसमें चार लाख रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन यदि श्रमिक बोर्ड के अंदर हमारा कोई मजदूर पंजीकृत है तो उसके एक लाख रुपया और मिलेगा। यह किसने सोचा? यह वीरभद्र सिंह जी ने

सोचा। यह उनकी सोच है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तजुर्बे को आप अपने ज़हन में बिठाईये। इस प्रकार का मुख्य मंत्री जो हमें मिला हो, जिनकी यह सोच हो, जो गरीब, मजदूर और किसान के बारे में सोचता हो, उन सोचों को आप अपने ज़हन में बिठाईये। इस तजुर्बे को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। यह मैं विपक्ष के विधायकों से कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्षः प्लीज वाइंड अप। आप वाइंड अप करिये अन्यथा मैं अगले वक्ता को बोलने के लिए बुलाऊंगा।

श्री बम्बर ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलते हुए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं। मैं पांच मिनट और बोलूंगा क्योंकि आपने अन्य सदस्यों को 25-25 और 35-35 मिनट दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। मेरे ऊपर थोड़ी-सी कृपा करिये।

हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय के धन्यवादी हैं। अब मैं केन्द्र की तरफ जा रहा हूं। गोविन्द सिंह ठाकुर जी कह रहे हैं कि यह महिला विरोधी बजट है। माननीय मुख्य मंत्री और सुधीर शर्मा जी ने हिमाचल के 10 शहरों के अंदर एन0यू0एल0एम0 (National Urban Livelihood Mission) प्रोजैक्ट दिया। जिसके अंदर जो गरीब किसान हैं, गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है जिसने

16.03.2016/1725/SS-AS/2

मैट्रिक या प्लस-टू कर रखी है अपने बच्चे को ट्रेनिंग नहीं करवा सकता, उसमें मुफ्त ट्रेनिंग करवाई जायेगी। पलम्बर, फीटर, बैल्डर, इलैक्ट्रीशियन की मुफ्त ट्रेनिंग करवाई जायेगी और प्लेसमैंट भी दे रहे हैं। यह 10 शहरों के अंदर चालू कर दिया है। हमारे बिलासपुर के अंदर भी चालू हो गया है। आपको उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। जो हमारी गरीब बहन ब्यूटी पालर की ट्रेनिंग करना चाहती है उसके लिए बिलासपुर के अंदर मुस्कान नामक संस्था है उसमें ब्यूटी पालर की मुफ्त में ट्रेनिंग करवाई जा रही है। अब इसके लिए हम धन्यवाद वीरभद्र सिंह जी का न करें तो किसका करें। आपने जो केन्द्र में बजट दिया उसमें आपने महिलाओं पर टैक्स लगा दिया। अगर कोई ब्यूटी पालर की ट्रेनिंग करना चाहेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। गहनों पर आपने टैक्स लगा दिया। हम यहां ब्यूटी पालर की ट्रेनिंग मुफ्त में करवा रहे हैं और प्लेसमैंट भी दे रहे

हैं इसके लिए हम अपने मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद न करें तो किसका धन्यवाद करें, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप सुनते नहीं हैं। आप ज़रा सुनिये। क्योंकि आपका जो केन्द्र से बजट आया उसमें आपने महिलाओं को नहीं बख्शा। आपने मजदूरों को नहीं बख्शा। आपने गरीबों को नहीं बख्शा। आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाये जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जो स्कीमें दिल्ली को गईं आपने उनके ऊपर टैक्स लगा दिये। आपने हमारे स्वां नदी के प्रोजैक्ट के पैसे को रोक कर रखा है। अगर आपकी दिल्ली के अंदर इतनी चलती है तो माननीय धूमल साहब से मैं कहना चाहूंगा कि आप मोदी साहब से कहिये कि हमारा जो स्वां नदी के प्रोजैक्ट का पैसा रोका है उसको जारी करिये। तब हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल प्रदेश के हितों के प्रति सजग हैं। आप दिल्ली में जाकर बात करिये तो सही। मैं खुद समझता हूं और मुझे मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के हितों पर केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से कुठाराघात कर रही है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। किसी के इशारे की बात नहीं है। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2016/1730/केएस/एएस/1

श्री बम्बर ठाकुर जारी----

हिमाचल प्रदेश के अंदर यदि किसानों के हित में, गरीब के हित में, मज़दूरों के हित में और बच्चों के हित में बड़े-बड़े फैसले लिए हैं तो वीरभद्र सिंह जी ने हमारी केबिनैट ने लिए हैं, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश की स्कीमों के ऊपर कट लगा रही है, पैसा नहीं दे रही है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा जो स्वां का प्रोजैक्ट है, उसका पैसा रोक कर रखा है। मैं विपक्ष के भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप दिल्ली जाइए, बात करिए। हमारे हिमाचल प्रदेश से केन्द्र में स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन मैडिकल कॉलेज दिए। 189 करोड़ रुपया उसके लिए हमने दिया । चम्बा में मैडिकल कॉलेज दिया, हमीरपुर को मैडिकल कॉलेज दिया और सिरमौर को मैडिकल कॉलेज दिया।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री बम्बर ठाकुरः उपाध्यक्ष जी, विपक्ष के लोग एम्ज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछिए कि हमने जब एम्ज़ के लिए जमीन दे दी है तो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं ? 1200 बीघा जमीन है उसको हमने आपके नाम कर दिया है, आप बताएं उसके लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? अनुराग ठाकुर जी कहते हैं कि यह हर्षवर्धन चौहान जी ने दिया और आप कहते हैं कि नड्डा जी ने दिया, हम जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश को एम्ज़ किसने दिया? हम जमीन दे रहे हैं केन्द्र पैसा नहीं दे रहा है। आप अपने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछिए । यदि आपकी दिल्ली के अंदर चलती है तो आप हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज़ दिलाइए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाइए।

श्री बम्बर ठाकुरः हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर, उनके इशारे पर मुख्य मंत्री जी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। उनके खिलाफ

16.03.2016/1730/केएस/एएस/2

मुकद्दमें बना रहे हैं। ऐसे मुकद्दमें बनाकर आप हमारे मुख्य मंत्री जी को नहीं डरा सकते। जितना आप उन्हें दबाएंगें हमारे मुख्य मंत्री जी उतने ही शक्तिशाली हो कर सातवीं बार मुख्य मंत्री बनेंगें यह मैं आपको बताना चाहूंगा। आप केवल मात्र मुख्य मंत्री जी के ऊपर मुकद्दमें बना कर सी.बी.आई. का दुरुपयोग करके हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराना चाहते हैं लेकिन आप गिरा नहीं सकते क्योंकि यह बहुमत से बनी हुई सरकार है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुमत से हमें जीत दिलाई है और हम सातवीं बार फिर से मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी को मुख्य मंत्री बनाएंगें। आप दिल्ली में जेटली जी को समझाइए, मोदी जी को समझाएं, जो साजिशे यहां पर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर कर रहे हैं, सफेद चद्दर के ऊपर जो दाग लगाना

चाहते हैं, आप दिल्ली जा कर उनसे कहिए कि इस प्रकार आप हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर नहीं कर सकते। केन्द्र सरकार ने जो पैसा हमारा रोका है, उसको दिलाइए और जो वीरभद्र सिंह जी के ऊपर साजिशें कर रहे हैं, उनके ऊपर जो आप मुकद्दमें चला रहे हैं इससे हिमाचल प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। आपने हिमाचल प्रदेश की सड़कों का ख्याल नहीं रखा और आज आप यहां पर मैच करवाने की बात कर रहे हैं। कितने लोग हमारे यहां पर शहीद हो गए लेकिन आप कह रहे हैं कि मैच कराइए। आप उसके लिए शांता कुमार जी को पूछिए। मैच का विरोध तो उन्होंने किया। आप राकेश पठानिया जी को पूछिए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करिए। अगले वक्ता श्री इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगें। कृपया समाप्त करें।

श्री बम्बर ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

अगले वक्ता श्रीमती अ0व0 की बारी में--

16.3.2016/1735/av/as/1

श्री इन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस मान्य सदन में बजट अनुमान वर्ष 2016-17 पर जो चर्चा हो रही है मैं उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ नई योजनाएं, लगभग 8-9 योजनाएं मुख्य मंत्री योजनाओं के नाम पर लोंच करने की बात की है। कुछ पुरानी योजनाओं के नाम बदल कर उनको नये नाम देने की कोशिश की है। बजट में थोड़ी-बहुत बढ़ोतरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में की है। मगर कुल मिलाकर यह बजट एक रूटीन बजट है तथा शेरो-शायरी से भरा हुआ बजट है। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें केक कम और आइसिंग ज्यादा की हुई है। अगर बजट के आंकड़ों को देखें तो

वर्ष 2016-17 में बजट अनुमान 32593 करोड़ रुपये का है तथा वित्तीय घाटा 4076 करोड़ रुपये का है। अगर हम सौ रुपये के हिसाब से देखें तो सौ रुपये के मुकाबले 80.60 रुपये केंद्र और प्रान्त से आने वाली प्राप्तियों से पूरा किया जायेगा तथा 19.40 रुपये ऋण पर लिया जायेगा। अगर खर्चा देखें तो एक रुपये में से 29 पैसे वेतन पर जायेंगे, 13 पैसे पैंशन पर, 11 पैसे ब्याज अदायगी पर तथा 7 पैसे ऋण की अदायगी पर जायेंगे। कुल मिलाकर इस बजट में 12.39 रुपये प्रदेश के विकास के लिए दिखाए गए हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यहां पर *थोथा चना, बाजे घना* वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। इस बजट में रोजगार पैदा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस बजट में रोजगार का कोई नया मोडल देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर ऐक्सचेंजिज में जो 8-9 लाख बेरोजगार पंजीकृत है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह सरकार सत्ता में यह वायदा करके आई थी कि हम बेरोजगारों को एक हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। मगर वह नहीं दिया गया और इस तरह से हमारे बेरोजगारों के साथ इन्होंने बहुत धोखा किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने हेतु कोई कोशिश नहीं की गई है। यह प्रदेश उधार के सहारे चल रहा है। इस प्रदेश पर 35151 करोड़ रुपये ऋण हो गया है। बजट का जितना ऐनुअल ले आउट होता है उससे ज्यादा तो इस प्रदेश ने कर्ज देना है।

16.3.2016/1735/av/as/2

आपको हर वर्ष 3400 करोड़ रुपये ऋण के ब्याज के रूप में देना पड़ता है। आज 'पंजाब केसरी' में आया था कि 'कर्ज की मर्ज से बेजार होता जा रहा है हिमाचल प्रदेश'। बिल्कुल सही लिखा है कि यह प्रदेश केवल कर्ज और केंद्र के सहारे चल रहा है। इस प्रदेश ने अपनी आर्थिकी मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया। यहां महंगाई कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। जहां फिजूलखर्ची कम होनी चाहिए वहां फिजूलखर्ची बढ़ाई जा रही है। इस प्रदेश की 70 लाख के करीब आबादी है। यहां पर 12 मंत्री महोदय बने हैं। इसके अतिरिक्त 9-10 मुख्य संसदीय सचिव बना दिए तथा 40-45 के हिसाब से आपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना दिए। साथ में सलाहकार भी जोड़ दिए और सलाहकार तथा चेयरमैन्ज उनको बनाया गया है जिनको जनता ने

रिजैक्ट किया हुआ है। (--व्यवधान--) धर्माणी जी, मैंने आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। हम एक ही फ्रैटरनिटी के आदमी है और मैंने आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया।

टीसी द्वारा जारी

16.03.2016/1740/TCV/DC/1

श्री इन्द्र सिंह --- जारी

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कमी-शमी रही थी वह सलाहकार बनाकर माननीय मुख्य मंत्री ने पूरी कर दी और ये जो जनता द्वारा रिजेक्ट किए हुए हमारे नेता है, उनको ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठा दिया। ये बड़ी दुःखद बात है और इसमें पब्लिक मनी को लुटाया जा रहा है। I would like to say to the Hon'ble Chief Minister, Sir, you have got the prerogative to place anybody in any position you wish to but people have not given you mandate to waste public money like this as you are wasting out. Yes, it is a fact. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आय के संसाधन वर्तमान परिस्थितियों में तभी बढ़ेंगे जब प्रदेश सरकार किसी दिशा में कोई ठोस काम करेगी और इरादे के साथ करेगी। जिन राज्यों में कोयला प्रोडयुस होता है, उन राज्यों को कोयले की रॉयल्टी मिलती है। हमारे डेढ़ लाख करोड़ के जंगल/वन संपत्ति है जिसको पर्यावरण संरक्षण के नाम पर उस वन संपत्ति को पिंजरे में बंद करके रखा है। इन जंगलों की वज़ह से पंजाब/चंडीगढ़ और हरियाणा का सारा वातावरण साफ-सुथरा रहता है लेकिन इन जंगलों में न तो हम पाईप लाईन बिछा सकते हैं,न सड़कें निकाल सकते हैं। इसके एवज़ में केन्द्र की तरफ़ से हमें कुछ नहीं मिलता है। मैं समझता हूं, इसके एवज़ में हमें विशेष राहत मिलनी चाहिए। सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। जैसा डॉ0 सैजल ने यहां पर कहा कि बिजली उत्पादन इस प्रदेश में होता है लेकिन जो बिजली प्रदेश से बाहर जाती है उसको आप 2 रूपये या 2.50 रूपये में बेचते हैं। जो इंडस्ट्रीज में जाती है उसको 4.50 या 5.75 रूपये में बेचते हैं। उस बिजली को अगर आप 5.75 के वजाय 4.50 रूपये कर दे तो कितनी इंडस्ट्रीज़ यहां आएगी और उससे फायदा होगा और जो बिजली आप बाहर को बेचते हैं, उसका पैसा

भी आपको नहीं आता है। बहुत सा पैसा बिजली विभाग का फंसा हुआ है। इस प्रकार अगर सरकार कोशिश करें तो हम आमदनी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपका जो प्रशासनिक खर्चा है, उसको भी कम करना पड़ेगा। आर्थिक सुधारों के लिए केन्द्र से जो मैसिज़

16.03.2016/1740/TCV/DC/2

है उसको भी आपको फॉलो करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हिमाचल अपने आर्थिक कद के अनुसार नये कॉलेज़/स्कूल खोलने चाहिए और उसके मुताबिक आपको अपना आर्थिक ढ़ाचा एक्सपेंड करना चाहिए। लेकिन ऐसा माननीय मुख्य मंत्री जी नही कर रहे हैं। जहां बोले स्कूल खोल दो, वहां बिना सोचे -समझें स्कूल खोल देते हैं।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अगर ट्राइबल में दो बच्चे हैं तो कहते हैं कि दो बच्चों के लिए भी हम स्कूल खोलेंगे। ये माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में पिछले सैशन में बुस्टफूली कहा था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता था लेकिन वह अभी बैठे नहीं है कि अगर आप ट्राइबल में जिस स्कूल में दो बच्चें होंगे वहां स्कूल खोल देंगे तो वह बच्चा किस से क्लास में इन्टरऐक्शन करेगा क्योंकि बच्चा बच्चों के बीच में रह कर सीखता है। क्या वह अपने टीचर से इन्टरऐक्शन करेगा? यदि वह खेलना चाहता है तो वह किसके साथ खेलेगा।उसकी कोई एक्टिविटी डैवैल्प नहीं होगी। अगर आपने ट्राइबल में स्कूल ही खोलने हैं तो नवोदय टाईप स्कूल वहां पर खोलिए उनको सारी फैसीलिटी दीजिए। एक बच्चे के लिए आप 50-60 हजार रूपये वहां प्रतिमाह खर्च कर रहे हैं। What is the result, there is no result at all. मैं समझता हूं कि इस दिशा में माननीय मुख्य मंत्री जी को सोचने की आवश्यकता है। 2015-16 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी। उसके मुताबकि माननीय अध्यक्ष महोदय अनाज और फलों का जो उत्पादन है वह हर साल कम हो रहा है। ये जो विलेज़ की इकोनोमी है, वह शरिंक हो रही है। जैसे उसमें लिखा गया है कि सन् 2000-2001 में हमारी जो जी0डी0पी0 होती थी उसमें कृषि

क्षेत्र का योगदान 21 परसेंट था लेकिन 2014-15 में ये घटकर 10.4 रह गया।

श्री RKS द्वारा जारी....

16.03.2016/1745/RKS/AG/1

श्री इन्द्र सिंह द्वारा जारी....

Every year it is coming down. मुख्य मंत्री जी किसान दुःखी हैं। किसानों ने खेती करना छोड़ दी है। बहुत सी खेती बंजर पड़ी हुई है। लोग खेती नहीं करना चाहते हैं। आपने एक अच्छी योजना दी है कि जिस खेती पर बेसहारा जानवर उजाड़ करते हैं वहां पर फेंसिंग लगाई जाए। उसमें आप 60% सब्सिडी भी दे रहे हैं। पर मैं ऐसा समझता हूं कि यह व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि कंसोलिडेटिड लैण्ड होल्डिंग नहीं है। किसान का एक खेत इधर है, दूसरा उधर है। आप उसमें नाजायज भी कर रहे हैं चाहे सौर एनर्जी से करें, चाहे विद्युत एनर्जी से करें। इस योजना के तहत जो किसान ने 40% पैसा अपनी जेब से डालना है, वह उसे देने में भी असमर्थ होगा। इस योजना में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। आप 40% पैसे को विधायक निधि से देने की व्यवस्था कीजिए या किसी ओर ढंग से देने की व्यवस्था कीजिए। तभी किसान इस योजना को अडॉप्ट कर सकता है। आपने कहा जो आवारा पशुओं से मुक्त पंचायत होगी उस पंचायत को हम 5 लाख रुपया देंगे। This is a very good suggestion. इसमें कोई दो राय नहीं है। बेसहारा जानवर बंधे हुए नहीं है। यह दिन को इधर-उधर घुमते रहते हैं। इनको एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप किस पंचायत को यह पैसा देंगे। This scheme will also not come in practice. I am telling you. यह सब कागजी घोड़े हैं। अध्यक्ष जी, आर्थिक सर्वेक्षण जो 2015-16 का हुआ उसमें सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। सिंचाई विभाग जो है it is in deep slumber. वह खर्राटे मार रहा है। मैं आपको प्रोमोज देता हूं माइनर इरिगेशन के लिए पिछले साल Let us be serious Dharmaniji. मैं आपकी सरकार की परफोरमेंश देना चाहता हूं। माइनर इरिगेशन में 152 करोड़ 45 लाख रुपया लास्ट बजट में मंजूर हुआ था। इसमें 33 करोड़ 78 लाख का खर्चा हुआ। 120 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा हुआ है and you have left with three

months to perform. How will you perform? It is all *nakli*. मेजर और माइनर इरिगेशन स्कीमों के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान था। 3 क्वार्टरज में 45 करोड़ में से 3 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च हुए हैं। एक क्वार्टरज में आप कितना खर्च कर पाएंगे यह बताइए? You are throwing money like this. कमांड एरिया डवेलपमेंट के लिए 50 करोड़ अलौट किया है and you have spent only Rs. 1.63 crores. 1 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किया है। बाकि कब खर्च किया जाएगा? इस सरकार की क्या परफोरमेंस है?

16.03.2016/1745/RKS/AG/2

फ्लड कंट्रोल के लिए आपने 190 करोड़ 5 लाख रुपए रखा है और उसमें से 3 क्वार्टरज में 14 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च हुआ। कुछ पैसा सीर खड्ड की चैनलाइजेशन के लिए हमें भी दे दीजिए। वहां आपकी जेब ढीली नहीं होती है। फिर यह पैसा कंहा जाएगा, यह आप मुझे बताइए? क्या यह सारा पैसा कैरी फॉरवर्ड होगा। आपने कौशल विकास भत्ते के लिए 100 करोड़ रुपए रखा है। इसमें 3 क्वार्टरज में 26 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च हुए। It is dismal performance, I must say. I wish Chief Minister would have been here. स्वास्थ्य विभाग के ठाकुर कौल सिंह जी यहां नहीं बैठे हैं। आई.जी.एम.सी. के लिए आपने 143 करोड़ 28 लाख रुपए रखा है उसमें से 93 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 50 करोड़ रुपया इसमें अभी खर्च करने के लिए बचता है। टांडा मैडिकल कॉलेज के लिए 71 करोड़ रुपए रखा है उसमें 51 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 20 रुपए इसमें अभी खर्च नहीं हुए हैं। डैंटल कॉलेज के लिए 13 करोड़ 12 लाख रुपए रखें हैं उसमें 9 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सरकार की क्या परफोरमेंस है you tell me. It is extremely poor. I think there has been some word invented below poor. Bumberji, it is very sad display of performance of this Government.

श्री एस.एल.एस.द्वारा जारी

16.03.2016/1750/SLS-AG-1

श्री इन्द्र सिंह ...जारी

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पिछले साल बजट रखा था उसमें लिखा था - हजारों ऐब ढूंढ़ते हैं हम दूसरो में। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, सीट खाली है लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि हम आपमें ऐब नहीं ढूंढ़ रहे बल्कि आपको आगाह कर रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में बड़ा फासला हो गया है। जब सत्ता आती है तो सिर ऊंचा हो जाता है और जब सिर ऊंचा होता है तो धरातल नज़र नहीं आता। इसमें कोई दोराय नहीं है।

आपके 11 निगम और बोर्ड हैं जिनमें 3166 करोड़ रुपये का घाटा है। यह कौन-कौन से हैं, यह मैं बताना चाहूंगा। प्रदेश वित्त निगम में 145 करोड़ रुपये का घाटा है। मैं पॉवर मीनिस्टर को बधाई देना चाहूंगा जो अभी यहां पर नहीं है। वह लिस्ट को टॉप कर रहे हैं। बिजली बोर्ड का घाटा 2000 करोड़ रुपये है। जब एक बॉस होता था . . . (Interruption) . . . Please let me speak. जब एक बोर्ड होता था तो इतना घाटा नहीं होता था। अब ट्राईफर्केशन कर दिया गया है और इसमें 3 बोर्ड हैं। इसलिए अब 3 बॉसिज हो गए हैं। More the bosses, more the losses. What is this? There is no control. There is no monitoring. माननीय बाली जी यहां पर नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी दुकान बंद होने वाली है।...(व्यवधान)... यहां वाली। एच.आर.टी.सी. का घाटा 1020 करोड़ रुपये है। बाली जी बड़े अच्छे हैं और मैं इनकी तारीफ करता हूं। He is very receptive. लेकिन इसको भी कंट्रोल करो। मैं मानता हूं कि यह आपका कमर्शियल वैंचर नहीं है। It is associated with lot many welfare activities. लेकिन फिर भी इतनी घाटा? डिपो में आपकी बसें खड़ी हैं क्योंकि आपके पास ड्राईवर-कंडक्टर नहीं हैं। उनकी खड़ी-खड़ी की इनवैंटरी कॉस्ट कितनी हो रही है? Unnecessary you are carrying the dead inventory that way. इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। एस.सी.एस.टी. वित्त निगम का घाटा 154 करोड़ रुपये है। एग्रो इंडस्ट्रीज का घाटा 192 करोड़ रुपये का है। वन मंत्री जी यहां नहीं हैं। He is also topping the list. पेड़ कट रहे हैं, बिक रहे हैं जबकि घाटे बढ़ रहे हैं। What is this? वन निगम का घाटा 527 करोड़ रुपये का है। यह क्या है? What is Marketing Processing Corporation? इस कार्पोरेशन का घाटा 760 करोड़ रुपये का है। माननीय मुख्य मंत्री जी, इस लॉयबिलिटी और इस डैड लोड को प्रदेश कब तक

16.03.2016/1750/SLS-AG-2

उठाता फिरेगा? Kindly let us not reinforce the failures. यह फेल्योर्ज़ हैं। इनके जो एम.डी. हैं उनमें जो इधर फेल हो गया उसको सकसैसफुल कार्पोरेशन में भेज देते हैं। वह वहां पर उस कार्पोरेशन को भी फेल कर देता है और फिर आप उसको आगे भेज देते हैं। यह क्या चक्कर है? जो कैपेबल व्यक्ति है don't send him at the key post? There has to be end to it. कहीं-न-कहीं तो इसको फुल स्टॉप लगाने की आवश्यकता है।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की भी थोड़ी-सी बात करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... धर्माणी जी, वह रोड कर्नल इंद्र सिंह की देन है। I can say it with full force. That is my *den.* You accept it or you don't accept it. सर, मैं अपने डिविजन में आई.पी.एच. की बात करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बर्वली तो सब झूठ बोल सकते हैं लेकिन यह विभाग तो लिखित में झूठ बोलता है। जो सूचना आप विधान सभा के अंदर देते हैं I take it for gospel truth. लेकिन वह बिल्कुल गलत होती है। जैसे मेरी 3 स्कीमें लिफ्ट इरिगेशन की हैं। ये 80-80 लाख रुपये की स्कीमें हैं। मैंने यहां प्रश्न संख्या 427 रखा था जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2013 को मिला है। मुझे बताया गया कि यह तीनों स्कीमें मार्च, मई और जून माह, 2014 में पूर्ण हो जाएंगी।

जारी ...श्री गर्ग जी

16/03/2016/1755/RG/AS/1

श्री इन्द्र सिंह------क्रमागत

अब वर्ष 2016 चल रहा है और दो साल के बाद भी अभी ये नहीं चल रही हैं। बिल्कुल यह झूठ बोला है। उसी प्रकार से मेरे यहां पीने-के-पानी की तीन बड़ी-बड़ी स्कीमें है, करोड़ों रुपये की स्कीमें हैं जो कांडापतन से पानी व्यास नदी से ला रहे हैं। उनमें से पहली 15 करोड़ रुपये, दूसरी 29 करोड़ रुपये और तीसरी 40 करोड़ रुपये की स्कीम है। इन्होंने मान लिया कि यह धूमल साहब की देन है। आपका तो इसमें कुछ लेना-देना नहीं है,

आपका सिर्फ एक ही लेना-देना है कि आप इन स्कीमों को चालू नहीं कर रहे हैं। You have stop the funds for these schemes. और मुझे यह भी लिखित में जवाब दिया गया कि ये तीनों स्कीमें 31 अक्तूबर, 2014 को कम्पलीट हो जाएंगी। क्या सबका एक ही दिन उद्‌घाटन हो जाएगा? What is this? लेकिन वे स्कीमें अभी वैसी-की-वैसी ही पड़ी हुई हैं। मेरे क्षेत्र में L.W.S.S की 17 स्कीमें निर्माणाधीन हैं उनके लिए आप लोग कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। जितनी भी मेरे यहां Flow drinking water schemes हैं उनमें किसी में फिल्टर नहीं है, टैंकों के ढक्कन नहीं हैं। बार-बार बोलने के बावजूद भी मैडम तो हां कर देती हैं और कहती हैं कि हमें पत्र लिखकर दो। मैंने पत्र भी लिखकर दिया, but no action.

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो विधायक प्राथमिकताओं में स्कीमें देते हैं, उनमें कूहलें प्राथमिकताओं में देते हैं, तो जवाब मिलता है 'infeasible' because there is no perennial source of water. I don't know who does it? The Section Officer does it or the Executive Engineer does it? I don't know. Those schemes are not feasible because there is no perennial source of water. What is this? जो हमारी कूहलें हैं वे सीजनल कूहलें हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में राजस्व अभिलेख के अनुसार 52 कूहलें हैं। सब सीजनल कूहलें हैं। हमें धान के लिए पानी चाहिए होता है और वह बरसात के समय में खड्डों में होता है, हमें गन्ना बीजने के लिए नवम्बर महीने में पानी चाहिए और वह खड्डों में होता है, हमें नवम्बर महीने में ही गन्दम बीजने के लिए पानी चाहिए और वह खड्डों में होता है। What is this perennial कि यह पैरीनियल नहीं है। इसलिए यदि यहां कोई अधिकारी बैठे हैं, तो मैं अनुरोध करुंगा कि जिन कूहलों की स्कीमों को आपने इनफिजिबल किया है, उनको रिवाइज करिए। मैं उनको रिपलेसमेंट नहीं करूंगा। इसके अतिरिक्त पानी इकट्ठा करने के लिए मैंने एक अच्छी स्कीम दी थी। मैं स्वयं साईट पर गया, मैंने देखा कि दोनों

16/03/2016/1755/RG/AS/2

तरफ 90-90 मीटर का रॉक का हार्ड स्ट्रक्चर है और वहां कैचमेंट एरिया बहुत है और वहां बहुत पानी इकट्ठा हो सकता है। लेकिन कहा गया कि It is not accessible
लोग चन्द्रमा तक पहुंच गए हैं, लेकिन वह अधिशाषी अभियन्ता खड्ड तक नहीं जा

सकता। it is very bad. वे दफ्तर से ही नहीं निकलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक शिक्षा की बात करूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए बैठिए। अब छः बज रहे हैं और अभी 2-3 सदस्य और बोलने को हैं। इसलिए इस सदन का समय अब पौने सात बजे तक बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्य कृपया अब आप समाप्त करिए।

Sh. Inder Singh : Thank you, Sir for giving one hour more. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्कूलों की अपग्रेडेशन की बात हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 150 प्राईमरी स्कूलों से मिडिल स्कूल बना दिए हैं, यह बहुत जरूरी विषय है, 336 मिडिल स्कूलों से हाई स्कूल बना दिए, लेकिन जो 336 मिडिल वाले हाई स्कूल बने हैं उनमें से 327 स्कूल निर्धारित मापदण्डों को क्वालीफाई नहीं करते। फिर भी बना दिए। आप सिस्टम को You can't bypass the system, if you bypass the system there is chaos. और यह सरकार ने क्योस पैदा कर दिया है in every field, you have created chaos. आपने 292 हाई स्कूल से सीनियर सैकण्डरी स्कूल बना दिए। उनमें से 271 क्वालिफाई ही नहीं करते। यह चक्कर क्या है? something wrong somewhere मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने सही ढंग से शिक्षा प्रदान करनी है, तो you reinforce your primary system, your elementary education is so poor कि पांचवी जमात का बच्चा पहली जमात का टैक्स्ट नहीं पढ़ सकता who is to be blamed.. आप एक बच्चे पर 30-35 हजार रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन what is your out come? जीरो ऑऊट कम है। उस पैसे से उस बच्चे को आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो इस सरकार को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों में दो-दो या तीन-तीन मॉडल स्कूल आप बनाइए। बाकी स्कूल बंद करिए। मॉडल स्कूल बनाइए, give everything there, Infrastructure facilities, teaching facilities, सब कुछ दीजिए।

एम.एस. द्वारा जारी

16/03/2016/1800/MS/AS/1

श्री इन्द्र सिंह जारी-----

आपने बच्चों को स्कूल आने-जाने की कागजों में परिवहन की सुविधा तो दी हुई है लेकिन आपके स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? Despite everything आप बच्चों को फ्री का खाना, वर्दी और किताबों के अलावा अच्छा वातावरण देते हैं लेकिन फिर भी आपके स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? you have to think over it. This is a very serious issue. क्योंकि अगर बच्चे ठीक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? आपने कहा कि हम 13000 नौकरियां देंगे तो टीचर्स कितने रखेंगे? क्योंकि हर साल 10,000 अधिकारी/कर्मचारी रिटायर होते हैं और 13,000 आप रख रहे हैं? यह पीनट है क्योंकि आपके पास 8-9 लाख जो बेरोज़गार हैं वे नौकरी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपने बैचवाइज भर्तियां भी बन्द कर दी हैं। एस0एम0सी0 के द्वारा आप टीचर्स रख रहे हैं लेकिन किसको रख रहे हैं जो मुझे पसन्द है, उसको मैं रख रहा हूं। I have seen, जो पी0टी0ए0 की सलैक्शन करते हैं। इससे ज्यादा ह्यूमिलेशन क्या हो सकती है कि एक आठ जमात पढ़ा हुआ आपका पी0टी0ए0 अध्यक्ष एक पोस्ट ग्रेजुएट का इंटरव्यु ले रहा है? It has happened in my Constituency, he was asking him a question कि हॉकी में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? वह कहता है कि हॉकी में तो गोल बनते हैं। तो वह कहता है कि ठीक है अगर तुझे पता नहीं है तो कोई बात नहीं है। What is this? I am telling a correct thing . I am not telling a lie. और उसने पूछा कि शिक्षा मंत्री कौन है तथा उनका नाम क्या है? उसने पूछा कि सर, देश का या प्रदेश का आप पूछ रहे हैं। तो उसने कहा कि कोई भी बता दे, चलेगा। ये क्या चक्कर है? ऐसी अटर ह्यूमिलिएशन कौन सह सकता है। एक पोस्ट ग्रेजुएट का इंटरव्यु आठवीं पास ले रहा है? ये आपका कारनामा है। आप इसको दिल से स्वीकार कर रहे हैं।

जहां तक स्वास्थ्य की बात है। सरकाघाट में रैफरल अस्पताल है। हर विधान सभा सत्र में मैं इस बारे में प्रश्न करता हूं और प्लानिंग की मीटिंग में भी प्रश्न करता हूं कि वहां जो आउट डोर ब्लॉक बना है, उसमें रैम्प की आवश्यकता है या फिर लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि सबसे ऊपर चौथे फ्लोर में जाकर सारे डॉक्टर्ज बैठते हैं। जिस व्यक्ति को हार्ट की समस्या होती है वह इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता है और तीन-चार लोगों की वहां डैथ भी हो गई है।

16/03/2016/1800/MS/AS/2

आप बार-बार आश्वासन देने के बाद वहां पर रैम्प नहीं बना रहे हैं। बल्द्वाड़ा में जो सी0एच0सी0 है उसके लिए आज से चार साल पहले 40 लाख रुपये आए हैं लेकिन उसका युटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। माननीय आयुर्वेद मंत्री जी मेरी तरफ देख रहे हैं। आपने 250 करोड़ रुपया बजट में रखा है लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में आप इन्फ्रास्ट्रक्चर पर एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। it is gross injustice to my Constituency. I am sure with your liberal heart you will rectify this.

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए।

श्री इन्द्र सिंहः It is a sorry state of affairs. No action. This Government is struck in amnesia. It has got an amnesia problem, I can safely say that.सरकाघाट में एक मिनी सेक्टेरिएट है उसमें प्रोविजन है और सब कुछ है तथा 15 लाख रुपया उसके लिए आया हुआ है लेकिन वहां लिफ्ट नहीं लग रही है। क्योंकि आपको काम के लिए कोई ठेकेदार ही नहीं मिल रहा है। सीवरेज हमारी वैसे ही पड़ी है। कार पार्किंग का मैंने आज प्रश्न किया था और उसका मुझे जवाब भी मिला है लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। It is a sorry state of affairs. No action. This Government is struck in amnesia. It has got an amnesia problem, I can safely say that. सड़कों की हालत बहुत खराब है। अध्यक्ष जी, जितनी करप्शन सड़कों में हो रही है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं दो उदाहरण दूंगा। यदि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहां बैठे हैं तो कृपया वे नोट कर लें। एक सड़क थौना से दुर्गापुर है उसका रिन्युअल कोट अभी-अभी हुआ है लेकिन 10 दिन के अंदर वह कोट उखड़ गया। मैंने XEN को फोन किया You don't make payment of this man. You come and check it. Nothing has happened. Corruption is rampant here. जोर-शोर से करप्शन है। एक डंगा वहां पर 50 मीटर बाई 7 मीटर है और लोक निर्माण विभाग ने वह डंगा खुद लगाया है लेकिन किसी के घर के आंगन में वह डंगा लगा दिया। जहां डंगा लगाने की जरूरत है वहां पर लगाते ही नहीं है। ये बड़ी समस्या है। मेरे चुनाव क्षेत्र में 40 सड़कों का निर्माण एस0सी0 सब प्लान के तहत चल रहा है। प्रदेश में 1220 करोड़ 14 लाख रुपया इसके लिए दिया गया है। लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र को आपने 1 करोड़ 37 लाख रुपया दिया है। पूरे प्रदेश के लिए 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा दिया है और मेरे चुनाव क्षेत्र में इतना कम दिया है। उसमें से भी कुल 90 लाख रुपया खर्च

किया है। यह बहुत ज्यादा अन्याय है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

16.03.2016/1805/जेएस/एजी/1

श्री इन्द्र सिंहः-----जारी-----

नाबार्ड में डी0पी0आर0 नहीं बन रही है। नाबार्ड में न तो सड़कों की डी0पी0आर0 बन रही है और न ही पी0एम0जी0एस0वाई0 फ़ेज-I में 14 सड़कों की डी0पी0आर0 बन रही है।

Speaker: No, you are not speaking now. Kindly windup. You have spoken for more than 30 minutes.

Sh. Inder Singh: I am winding up Sir, just one minute. अध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी सुपरवाईजर्ज़ का ऑल इंडिया बेसिज़ पर एक सर्वे हुआ है। उसको बाल विकास विभाग ने किया है। हिमाचल प्रदेश उसमें टॉप पर रहा है। हमारे पास जो आंगनवाड़ी सुपरवाईजर्ज़ हैं वह as many as **57** परसेंट डेफिशिएंट है। यह हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इतना यू0पी0 का भी नहीं है वहां पर 40 के करीब है। You have to improve on these things.

Speaker: Please windup.

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हम एम0एल0ए0 प्रायोरिटी देते हैं। हम दूर से आते हैं। अपनी जनता को पूछ करके फिर लिखते हैं कि क्या-क्या देना है? लेकिन हमारी एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में एक भी स्कीम अपीयर नहीं हुई है। यह क्या किया है, who is responsible for this? यह धक्काशाही है और क्या है? एक भी स्कीम हमारी

एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में अपीयर नहीं हो रही है। इसको रैक्टिफाई किया जाए। हमारे माननीय मंत्री जी इस बात को सुन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा, क्योंकि बम्बर जी मेरे पड़ौसी हैं ये नाराज़ हो जाएंगे। आपने जो 1 करोड़ रूपए की विधायक निधि की बात की है, मैं समझता हूं यह डेढ़ या दो करोड़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्रों में यह जो विधायक निधि है बम्बर जी यही विकास करवा रही है और कोई साधन हमारे पास नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर आप सुन रहे हैं तो इसको डेढ़-दो करोड़ रूपए करिए। अग्निहोत्री जी

16.03.2016/1805/जेएस/एजी/2

आपकी तरफ से इशारें हो रहे हैं। Please help us out. जो discretionary grant है वह भी थोड़ी सी बढ़ाई है । बहुत से लोग दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे थोड़ा ज्यादा टाईम दे दिया। ये बजट किसी के हक में नहीं है। न यह किसान के हक में है, न बागवान के हक में है, न प्रदेश के हक में है और मेरे चुनाव क्षेत्र में इस बजट ने कुछ नहीं किया। इसलिए यह न तो मेरे हित में है और न ही मेरे आदमियों के हित में है, इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

16.03.2016/1805/जेएस/एजी/3

अध्यक्षः श्री राम कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे। Please keep your time brief.
माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी बात की कि इनकी एम0एल0एल0 प्रायोरिटी डीमांड बजट में अपीयर नहीं हुई है। यह बात सरकार के ध्यान में आई है इनको अपीयर करवाया जा रहा है।

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी ने 2016-17 का जो बजट दिनांक 8 मार्च, 2016 को इस माननीय सदन में पेश किया। मैं आपकी अनुमति से उसकी चर्चा हेतु खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, हर वित्त वर्ष में सत्तासीन मुख्य मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो बजट माननीय मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी ने पेश किया वह अपनी तरह का एक प्रगतिशील बजट है। ऐसा बजट जिसमें खासकर गरीबों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी आवास योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को मकान देने की बात कही गई हो, क्योंकि गरीब किसी भी वर्ग का हो सकता है। सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग थे उन्हें हमेशा मकानों से वंचित रखा जाता था। लेकिन इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह दया दृष्टि प्रदेश के सामान्य वर्ग के लोगों के ऊपर करके उन्हें यह सुविधा दी है उसके लिए मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इससे पहले इस माननीय सदन में प्रदेश की बहुचर्चित समस्या आवारा पशुओं की रोकथाम, बन्दरों की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन इस बजट में गौवंश सम्वर्द्धन बोर्ड के माध्यम से उन गौ सदनों को ईनाम देने की बात की गई है, जो आवारा पशुओं को शरण देंगे। फैंसिंग की बात भी इसमें 60 प्रतिशत सहायता की बात सरकार ने की है, उसमें थोड़ी सी अगर सहायता राशि बढ़ जाए तो मैं समझता हूं कि यह एक कारगर कदम सिद्ध होगा।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------------

16.03.2016/1810/SS-DC/1

श्री राम कुमार क्रमागतः

इससे बढ़कर पंचायत पशुधन पुरस्कार योजना के तहत उन पंचायतों को पांच लाख रुपये देने की बात कही गई है जो पूर्णतः आवारा पशु मुक्त हों। इसकेलिए 7.8 करोड़ बजट का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। दुधारू पशुओं के दूध न देने की स्थिति में उन्हें त्यागने वाले पशुपालकों पर अधिक दंड का प्रावधान इस बजट में किया गया। इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को बिना किसी आय सीमा के

सामाजिक सुरक्षा पैंशन 1100 रुपये की गई। इस सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए मैंने सरकार को पहले भी सुझाव दिया था और अब भी मेरा अनुरोध है कि इसकी आयुसीमा 80 से 70 वर्ष करने की कृपा करें ताकि हमारे ज्यादा वृद्ध इसमें कवर हो सकें क्योंकि आजकल दिन-प्रतिदिन मनुष्य की औसतन आयु घटती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी आयुसीमा 70 वर्ष की जाए। ऐसा मेरा सुझाव है। 70 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को पैंशन 1100 रुपये से 1200 रुपये बढ़ाई गई है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन जो 450 रुपये थी उसको बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस पुनीत कार्य को माननीय मुख्य मंत्री जी ने गरीबों के लिए ही तो किया है। इसके अलावा राजीव गांधी अन्न योजना के तहत 37 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई। जिसके तहत उन्हें 3 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। बी0पी0एल0 परिवारों को 35 किलोग्राम राशन प्रतिमाह के हिसाब से सरकार देगी। इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। दैनिक दिहाड़ीदार जिन्हें सारा दिन काम करके केवल 150 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते थे, उनकी दिहाड़ी बढ़ाकर इन्होंने 180 रुपये करने का निर्णय लिया। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा कदम गरीबों के हित में है। प्रदेश के सभी स्कूली छात्रों को मुफ्त यात्रा प्रदान करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने सराहनीय कदम उठाया है। जो हमारे गरीब बच्चे थे, जो बसों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने दूर-दराज के क्षेत्रों में जाते थे उनकी सहायता की है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। 24 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दो इंजीनियरिंग महाविद्यालय और एक हजार नये स्कूल्ज़, 28 नये डिग्री कॉलेज खोले। जिसमें एक डिग्री कॉलेज माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे चुनाव क्षेत्र में बरोटीवाला में पिछली 13 अप्रैल को घोषित किया था। ढाई माह के बहुत छोटे समय में उसको चालू किया है जिसमें 287 बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 25 तारीख को

16.03.2016/1810/SS-DC/2

माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसका नींव पत्थर रखने वाले हैं। इसके लिए मैं विशेष तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं। जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय केन्द्र मे सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री थे तो उस समय बद्दी औद्योगिक क्षेत्र के नौजवानों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु उन्होंने मात्र उस समय की सरकार द्वारा 15 बीघे उपलब्ध

करवाई गई जमीन में इसका नींव पत्थर रखा था। जिसमें प्रदेश सरकार ने 100 बीघा भूमि देखकर, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपये है, माननीय राजा साहब ने माननीय केन्द्रीय मंत्री के साथ पिछले दिनों बद्दी में एक बहुत बड़े टू रूम का नींव पत्थर रखा। जिसके तहत बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र में पूरे हिमाचल प्रदेश से और अन्य क्षेत्रों से जो कामगार काम करते हैं उन्हें उसमें प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। पूरे प्रदेश के नौजवान साथियों को उसका लाभ होगा। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का एक पायलट प्रोजैक्ट था। जो इनका सपना था वह पूरा हुआ। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी और तकनीकी शिक्षा मंत्री की दूरदर्शिता के कारण प्रदेश के हर चुनाव क्षेत्र में एक-एक आई0टी0आई0 देने का फैसला सरकार ने किया है जोकि एक सराहनीय फैसला है। मैं विशेष तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी और बाली साहब का धन्यवादी हूं कि उन्होंने मेरे चुनाव क्षेत्र में दो आई0टी0आई0 पट्टा और कुठाड़ में खोली हैं। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवादी हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बार के बजट को महा-संतुलित बजट की संज्ञा देता हूं। जिसमें प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति से लेकर एक बड़े उद्योगपति तक का ख्याल रखा है।

जारी श्रीमती के0एस0

16.03.2016/1815/केएस/एजी/1

श्री राम कुमार जारी----

वर्तमान में चल रहे उद्योगों पर जो प्रवेश शुल्क 2 प्रतिशत था उसे घटाकर एक प्रतिशत किया गया। नए उद्योगों को जो एक प्रतिशत प्रवेश शुल्क देना पड़ता था उसको घटाकर आधा प्रतिशत किया गया है। इससे जो डर था जैसे विपक्ष के लोग भी बात करते हैं कि यहां से उद्योग पलायन कर रहे हैं। वह पलायन तो नहीं हो रहा था लेकिन उससे उद्योगों की मंदी को कंट्रोल करने में हमें सहायता मिलेगी और उद्योगों का पलायन रुकेगा। इसी तरह से स्टील प्लांट्स की मंदी को देखते हुए सरकार ने स्टील प्लांट्स की ए.जी.टी. को 75 प्रतिशत मीट्रिक टन से घटाकर 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन

किया गया, इसके लिए स्टील उद्योग को राहत मिलेगी और मैं समझता हूं कि यह भी सरकार का बहुत बड़ा कदम औद्योगिक ईकाइयों को बढ़ावा देने के लिए है। इसके अलावा 25 लाख का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को एक मुश्त कर योजना के तहत लाया गया यह सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। डीम्ड असैसमैंट के दायरे में आने वाले डीलरों के कारोबार की लीमिट एक करोड़ से एक करोड़ पच्चास लाख रु0 की गई यह भी बहुत अच्छा कदम है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में संजौली में एक हैलीपैड का बनाना एक नया कदम है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि शिमला में कोई भी हैलीपैड नहीं था सिर्फ कक्कड़हट्टी में था। सड़कें किसी भी प्रदेश की भाग्य रेखाएं कहलाती है जिसके तहत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 3200 करोड़ वाली हिमाचल प्रदेश सड़क योजना चरण-2 का बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत सैद्धान्तिक रूप से सरकार ने इसको अनुमोदित किया है। इसके लिए धन्यवाद और इसके तहत इसी वर्ष 2016-17 में 400 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कों व 20 पुलों की प्रस्तावना एक सराहनीय कदम रोड़ज़ के लिए लोक निर्माण विभाग में सरकार का है जिसमें 500 किलोमीटर सड़कों को पक्का करना और 550 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों की जल निकासी को पूर्ण करना प्रस्तावित है यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है1 मुख्य मंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं इस

16.03.2016/1815/केएस/एजी/2

वर्ष शुरू की है । जैसे हमारे विपक्ष के मित्रों द्वारा कहा जा रहा है कि सिर्फ योजनाओं के नाम चेंज किए गए हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने जो योजनाएं शुरू की है, वे इससे पहले कभी नहीं थी। मुख्य मंत्री ज्ञानदीप योजना के अंतर्गत देश के मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यवसायिक एवं तकनीकी उच्च अध्ययन कर रहे पात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी हिमाचली विद्यार्थियों को बैंकों से 10 लाख रु0 के शिक्षा ऋण पर बिना किसी आय सीमा के 4 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जबकि इससे पहले विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण लेते समय आयसीमा आड़े आती थी। हमारे बहुत से ऐसे होशियार विद्यार्थी हैं जो घर की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण पढ़ नहीं पाते थे लेकिन सरकार का यह सराहनीय कदम है ताकि वे बच्चे हायर ऐजुकेशन प्राप्त करें । उसमें आय सीमा को हटाकर जो ऋण देने की बात प्रदेश

के गरीब बच्चों के हित की की है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री वर्दी योजना के तहत प्लस टू के विद्यार्थी जिन्हें पहले वर्दी से वंचित किया गया था, उनको भी वर्दी दी जाएगी। विधायक प्राथमिकता के तहत दो करोड़ रुपये की मांग सभी विधायकों ने, चाहे पक्ष के विधायक हैं या विपक्ष के हैं, रखी थी उसको बढ़ाकर मुख्य मंत्री जी ने 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया है इसका भी सभी ने स्वागत और धन्यवाद किया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसको सरकार अगले साल डेढ़ करोड़ करने की कृपा करें ताकि विधायक नीधि से क्षेत्र विकास में और तेजी आए। हैंड पम्प लगाने के लिए विधायक प्राथमिकता में जो जगह दी क्योंकि इससे पहले विधायक प्राथमिकता में कोई भी विधायक अपनी प्रायोरिटी में हैंडपम्प की बात नहीं रख सकता था, उसको प्रायोरिटी में नहीं डाल सकता था, यह भी एक सराहनीय कदम है और मैं समझता हूं कि हम विधायकों के लिए एक अच्छी शुरूआत है। बड़ी स्कीमों को बनने में समय लगता है, तुरन्त पानी की जरूरत होती है कई जगह पानी के स्त्रोत सूख जाते हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.3.2016/1820/av/ag/1

श्री राम कुमार क्रमागत

और उनको एकदम देने के लिए विधायक के पास कुछ नहीं होता। हैंड पम्प लगने से कम-से-कम उस मौके पर पानी के रूप में उनकी सहायता होती है। इसके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। लघु सिंचाई योजना के तहत सरकार ने लगभग 245 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है जो कि किसानों के उत्थान के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। आपदा राहत कि लिए 248 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह से जहां पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के मान-सम्मान की बात करें तो माननीय वीरभद्र सिंह जी ने चुने गये जन प्रतिनिधियों के मान-सम्मान का हमेशा ख्याल रखा है। जब मैं अध्यक्ष, जिला परिषद था तो हमें 3000 रुपये मानदेय मिलता था। मगर राजा

साहब ने उसको अब 8000 रुपये कर दिया है। इन्होंने वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष तक और इसी तरीके से नगर निगम निकायों के पार्षद व अध्यक्ष के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। यह केवल उन जन प्रतिनिधियों का मान-सम्मान नहीं है बल्कि मुख्य मंत्री जी ने एक तरह से आम जनता का सम्मान किया है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच और दूरदर्शिता को दिखाता है जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो मैं यह बताना चाहूंगा कि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ प्राधिकरण का गठन माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा किया गया था। इससे पीछे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय केवल 5 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था। मगर पिछले वर्ष इसमें 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसमें 45 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे है और लगभग 15 करोड़ रुपये हमारे प्राधिकरण के माध्यम से जो रैवन्यू अर्न होता है वह भी इसमें जोड़ा गया है। इस वक्त हमारे उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। हमने इनसे भी प्रार्थना की थी और इस बार के बजट में इन्होंने इसके लिए 30 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। मैं इसके लिए मुख्य तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इंडस्ट्रियल एरिया तथा भारी वाहनों की वजह से वहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई थी। वहां पर जो पार्कों, टॉयलैट्स इत्यादि की जरुरत थी तथा गांव में

16.3.2016/1820/av/ag/2

जिन गलियों से ट्रक गुजरते थे उन गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्ज लगाने की बात है तो इस बी0बी0एण्ड एन0प्राधिकरण के माध्यम से वहां ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। यह प्रदेश का एक मात्र प्राधिकरण है। इस प्राधिकरण की वजह से हमारे प्रदेश के दो निर्वाचन क्षेत्रों के विकास में काफी तेजी आई है। इसके लिए मैं सरकार और मुख्य मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा। केंद्र सरकार ने पिछले कल एक उद्योग विरोधी फैसला लिया है जिसके तहत 342 ड्रग्स को बंद करने का आदेश आया है। फार्मा युनिट्स में बद्दी का नाम वर्ल्ड में कनाडा के टोरंटो के बाद दूसरे नम्बर पर है। मगर जब यह 342 ड्रग्स बंद कर दी जायेगी तो इससे बद्दी के फार्मा हब को बहुत बड़ा

झटका लगेगा। मैं यहां पर बैठे अपने साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि ये जो ड्रग्स की युनिट्स बंद करने का निर्णय लिया गया है इस बारे में केंद्र सरकार से पुनः विचार करें नहीं तो हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। जैसे यहां पर पलायन की बात होती है तो सच्च में ही बद्दी से उद्योगों का पलायन शुरू हो जायेगा। मैं इसके लिए केंद्र सरकार की भर्त्सना करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदा विभाग के अंतर्गत जो डॉक्टर्ज की भर्तियां हो रही हैं उसमें 50 प्रतिशत भर्तियां बैच वाइज करने की कृपा करें। इसी तरीके से शिक्षा विभाग में भी काफी समय से बैच वाइज भर्तियां बंद है। उसकी वजह से हमारे स्कूलों में काफी सारे पद खाली हैं। भर्तियां होने से हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा। मुख्य मंत्री जी ने औद्योगिक क्षेत्रों का ध्यान रखा है जहां से सबसे ज्यादा राजस्व की उगाही होती है। इससे पूर्व इस क्षेत्र के साथ विकास के नाम पर हमेशा भेदभाव होता रहा।

टीसीद्वारा जारी

16.03.2016/1825/TCV/DC/1

श्री राम कुमार --- जारी

यह बजट पिछली सरकार के समय में सिर्फ 5 करोड़ था अब इन्होंने 30 करोड़ कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'आर्दश विद्यालय योजना' के तहत 30 करोड़ का प्रावधान इस बज़ट में रखा मैं उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा। 'पंचायत बालिका पुरस्कार योजना' के तहत प्रदेश की 15 पंचायतों जिनमें बालकों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ कन्या दर है, उनको उन्हें 10 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि विकास के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी जिससे बढ़ते हुए लिंग अनुपात को रोकने में मदद मिलेगी। यह बहुत बड़ी समस्या हमारे भारतवर्ष में होती जा रही है कि लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे लिंग अनुपात को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। "मुख्य मंत्री कन्यादान योजना" के अन्तर्गत विभाग की अनुदान राशि पहले 20 हजार से 25 हजार रूपये की गई और अब इसे 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रूपये कर दिया है, यह एक बहुत बढ़ा कदम है। 45 वर्ष से कम और एक या अधिक बच्चों वाली विधवाओं की पैंशन 600 रूपये से बढ़ाकर 1200

रूपये कर दी गई है। इससे हमारे प्रदेश की विधवाओं को सहारा मिलेगा। शहीदों को दी दिए जाने वाले सम्मान परमवीर,अशोक चक्र, महावीर चक्र के विजेताओं की राशि को एकमुश्त बढ़ाए जाने का प्रस्ताव इस बज़ट में रखा गया है। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी तरह 'नारी सदन' में रहने वाली महिलाओं को उनके विवाह के समय दी जाने वाली राशि जो 25 हजार रूपये से बढ़ाकर 51 हजार रूपये करने का प्रावधान इस बज़ट में किया गया है वह भी एक सराहनीय कदम है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य अब आप वाइंड-अप कीजिए। आपका समय हो गया है।

श्री राम कुमारः सर, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि विरोध उस चीज का होना चाहिए जो विरोध लाइक हो। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो कार्य इस बज़ट में प्रस्तावित किए हैं वह इससे पहले कभी नहीं हुए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर हम पर्यटन की ओर बढ़ावा दें तो एक तो

16.03.2016/1825/TCV/DC/2

हमारी सरकार की आय बढ़ेगी और दूसरे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मेरे चुनाव क्षेत्र के साई,जोहड़ और माहूनाग के जो तीन पर्यटन स्थल है अगर उनको विकसित किया जाये तो हमारे नौजवानों को इससे रोजगार मिलेगा और प्रदेश की आय भी बढ़ेगी। इसके अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों में भी पर्यटन की बहुत-सी संभावनाएं हैं। अध्यक्ष जी आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सरहानीय बज़ट के लिए सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद। मैं इस बज़ट का भरपूर समर्थन करता हूं।

16.03.2016/1825/TCV/DC/3

अध्यक्षः अब श्री विनोद कुमार अपनी बात रखेंगे। आप संक्षेप में बोलिए ताकि सभी चीजें कवर हो जायें।

श्री विनोद कुमारः आदरणीय अध्यक्ष जी, 8 मार्च, 2016 को हिमाचल प्रदेश के मुख्य

मंत्री ने हिमाचल का बज़ट मान्य सदन में पेश किया। इस बज़ट पर चर्चा शुरू हुई है, मैं भी इस चर्चा में शामिल करता हूं। आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष जी, वर्ष 2016-17 के बजट से प्रदेश के लोगों/किसानों/मजदूरों व सभी वर्ग के लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय सदन के समक्ष अपना 19वां बज़ट पेश किया लेकिन जब बज़ट माननीय सदन में पेश किया गया तो

श्री आर0के0एस0 --- द्वारा जारी ।

16.03.2016/1830/RKS/AS/1

श्री विनोद कुमार द्वारा जारी....

प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों को निराशा हाथ लगी। किसी ने ठीक ही कहा है 'खोदा पहाड़, निकला चूहा' । यहां पर सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा इस बजट को लेकर तारीफों के बड़े-बड़े पुल बांधे गए। किसानों के लिए नई-नई योजनाओं को शुरू करने की बात की गई। जिन योजनाओं की घोषणा इस बजट के अंदर की गई है वे सभी की सभी योजनाएं पुरानी है। सिर्फ स्कीमों के नाम ही बदले गए हैं। बजट के पैरा 26 में डा0 वाई. एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना का जिक्र आपने किया है। इस स्कीम को पहले हमारी सरकार ने ही पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम से चलाया था। आपने इस स्कीम का सिर्फ नाम ही बदला है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का जीवनयापन करते हैं। जहां हम मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में खरीदते थे, अब उसका रेट भी 25-30 रुपए हो गया है।

(सभापति महोदया, श्रीमती आशा कुमारी जी अध्यक्ष पीठ पर पदासीन हुई।)

माननीय मुख्य मंत्री जी आपने दूध का मूल्य केवल मात्र 1 रुपया प्रति लीटर ही बढ़ाया है। दूध उत्पादकों के साथ यह एक भद्दा मजाक किया गया है। मैं चाहूंगा कि दूध के रेट में और बढ़ोतरी की जाए।

बजट के पैरा 60 में आपने कहा है कि हमारी सरकार जो बेघर लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है उन लोगों को वर्ष 2016-17 में सभी पात्र लोगों को भूमि दे दी जाएगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज तक आपकी सरकार ने कितने भूमिहीन लोगों को भूमि दी है।

बजट के पैर 85 में आपने खुद माना है कि सड़कें राज्य की जीवन रेखा है। हिमाचल प्रदेश में रेल सेवा, हवाई सेवा केवल न के बराबर है। इन साधनों के अभाव में राज्य सरकार ने सड़कों को सदैव उच्च प्राथमिकता दी है। मगर कहां दी है , यह पता नहीं है? मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं करुंगा लेकिन अपने चुनाव क्षेत्र की बात

16.03.2016/1830/RKS/AS/2

यहां पर जरूर करूंगा। पिछले 3 वर्षों में हमने जितनी भी विधायक प्राथमिकता की स्कीमज डाली हैं और उससे पूर्व भी जो स्कीमें विधायक प्राथमिकता में डाली गई है उनकी डी.पी.आर. अभी तक पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा तैयार नहीं की गई है। नाचन विधान सभा क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा एक इंच भी सड़की नहीं निकाली गई है। प्रदेश में जितने भी विधायक विपक्ष में जीतकर आए हैं उन सभी विधायकों के साथी इसी तरह का भेदभाव प्रदेश सरकार कर रही है। जो हमार मण्डी जिला है उस मण्डी जिला में कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक चुनकर आए हैं। उनमें से 3 इस प्रदेश सरकार में मंत्री है और 2 सी.पी.एस. हैं।

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी...

16.03.2016/1835/SLS-AS-1

श्री विनोद कुमार...जारी

उसके बाद जो 5 विधान सभा क्षेत्र बचते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं वहां से चेयरमैन, वाईस चेयरमैन और सलाहकारों की भी एक फौज खड़ी कर दी गई है, जिला मण्डी में जिनकी संख्या 6 बनती है। मैं उन 3 मंत्रियों, 2 सी.पी.एस. और जो फौज खड़ी की गई है उनसे पूछना चाहूंगा कि मण्डी को 2015-16

में लोक निर्माण विभाग द्वारा 66,97,069,000 का बजट रखा गया था जो अब 2016-17 में घटकर 46,86,42,000 कर दिया है। जब यह किया गया, उस समय आप सब कहां थे। मण्डी के लोगों के साथ इतना बड़ा भेदभाव हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब लोक निर्माण विभाग का यह बजट काटकर किसी और जिले को दिया गया, उस समय आप कहां थे?

सभापति महोदया, इस बजट में कहा गया है कि 1000 से अधिक स्कूल खोले गए अथवा अपग्रेड किए गए। गत 3 वर्षों में प्रदेश में 28 डिग्री कॉलेज खोले गए। मैं बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में प्राईमरी स्कूलों की संख्या 10783, मिडल स्कूलों की संख्या 2249, हाई स्कूलों की संख्या 880, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 1610 तथा डिग्री कॉलेजों की संख्या 94 है। पूरे प्रदेश में आपके आंकड़े 83 परसैंट साक्षरता दर दिखाते हैं। फिर क्या कारण है कि दिनोंदिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम होती जा रही है? आप सरकारी स्कूलों में खाना और वर्दी दे रहे हो जबकि फीस नहीं ले रहे हो। यहां तक कि बस सेवाएं भी मुफ्त दी जाती हैं। उसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दिनोंदिन क्यों कम हो रही है? इसका एक ही कारण है कि स्कूलों में जितने अध्यापक होने चाहिए, उतने नहीं हैं। दूसरे, अभी भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों को बैठने के लिए कमरों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश में टी.जी.टी. आर्ट्स, टी.जी.टी. मैडिकल और टी.जी.टी. नॉन मैडिकल के 1500 पद अभी भी खाली हैं लैक्चरर्ज़ के 900 पद खाली चल रहे हैं और ड्राईंग टीचर, पी.टी.आई. तथा लैंगुएज टीचर्ज़ के 50 प्रतिशत पद खाली हैं। हैडमास्टर के 150 पद खाली हैं। जब स्कूलों में

16.03.2016/1835/SLS-AS-2

बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक ही नहीं है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जा सकती है?

सभापति महोदया, इस बजट में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 130 से अधिक नए संस्थान खोले गए या अपग्रेड किए गए हैं। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि जहां आवश्यकता है वहां नए संस्थान खुलने चाहिए। साथ ही, जहां संस्थानों को और

हॉस्पिटल्ज को अपग्रेड करने की बात है, वह अपग्रेड होने चाहिए। लेकिन मैं आपको अपने क्षेत्र के सिविज हॉस्पिटल गोहर की बात बताना चाहूंगा। सिविल हॉस्पिटल गोहर को अपग्रेड हुए लगभग 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जब उसका उद्घाटन किया गया था उसके बाद एक डैपुटेशन माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने आया था। हमने इनसे निवदेन किया था कि आपने इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, इसके लिए मैं नाचन विधान सभा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं।

जारी ...श्री गर्ग जी

16/03/2016/1840/RG/DC/1

श्री विनोद कुमार------क्रमागत

लेकिन यहां इस अस्पताल में यदि आज आवश्यकता है, तो नए पदों को सृजित करने की आवश्यकता है और खाली पड़े हुए डॉक्टर्ज के पदों को भरने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे उस सिविल अस्पताल में डॉक्टर्ज के 8 पद सृजित हैं और जब उसको अपग्रेड किया गया, तो उसके पश्चात न तो वहां नए डॉक्टर्ज के पदों को सृजित किया गया और वहां जो 4 पद डॉक्टर्ज के खाली चल रहे थे, न हीं पिछले डेढ़-दो सालों से उनको भरा गया। इसी प्रकार से मेरे चुनाव क्षेत्र में पी.एच.सी., समीहार है। उसमें न तो डॉक्टर और न ही फार्मासिस्ट है, न अन्य स्टाफ है। हम अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं, होने चाहिए, लेकिन जब तक हम उन अस्पतालों में स्टाफ नहीं भरेंगे या डॉक्टर नहीं भरेंगे, तो हम, लोगों को किस प्रकार से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे पाएंगे? यह संभव नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार आयुर्वेदा विभाग में बैचवाईज डॉक्टर्ज की भर्ती करे ताकि आयुर्वेदा विभाग में डॉक्टर्ज के जो पद खाली चल रहे हैं उनको भरा जाए।

सभापति महोदया, यहां एक काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक किया है कि हमारी विधायक निधि को 75,00,000/-रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया हे। इसका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि यदि आप सच में हर विधान सभा क्षेत्र का विकास

एकसमान देखना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस विधायक निधि को आप एक करोड़ के बजाय दो करोड़ करने की कृपा करें।

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ मैं केन्द्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि केन्द्र की सरकार ने हिमालय क्षेत्रों के प्रदेशों की सभी केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं को 90:10 में करने का निर्णय लिया है। जिससे प्रदेश सरकार को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसके माध्यम से जो केन्द्र की ओर से हमें 90% मिलेंगे और प्रदेश की तरफ से हमें केवल 10% ही पैसा देना होगा। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार और श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। (घण्टी) मैं केन्द्र की सरकार का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा

16/03/2016/1840/RG/DC/2

कि क्योंकि पिछली बार 13वें वित्तायोग की अपेक्षा जो 14वां वित्तायोग शुरू किया गया है, उसमें हमें पिछली बार की अपेक्षा तीन गुणा से अधिक धन हिमाचल प्रदेश को मिला है। इसके लिए मैं नरेन्द्र मोदी जी और केन्द्र सरकार का धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदया, प्रदेश को विकास की गति देने के लिए कोई भी ठोस कदम हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नहीं उठाए गए हैं। आम-आदमी के कल्याण के लिए कोई भी विशेष योजना नहीं बनाई गई है (घण्टी) सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट में न के बराबर बढ़ौत्तरी की गई है। कृषि और बागवानी के लिए जिन योजनाओं की घोषणा यहां की गई है वे सारी-की-सारी योजनाएं पुरानी हैं जो हमारी सरकार के समय चलती थीं। इसमें किसी भी तरह के सुधार होने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कोई भी ठोस योजना नहीं बनाई गई है। प्रति व्यक्ति ऋण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे कम करने के लिए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। इसलिए इस बजट में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता जिसमें आम-आदमी या नाचन की जनता का भला होता हो। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। अन्त में दो लाईनें कहकर मैं अपनी वाणी को विराम

दूंगा।

एम.एस. द्वारा जारी

16/03/2016/1845/MS/AG/1

श्री विनोद कुमार जारी----------

किसी ने कहा है-

बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर,
बैठन को छाया नहीं फल लागे अति दूर।

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): अभी एक वक्ता और बोलने को शेष है। यदि मान्य सदन की अनुमति हो तो क्या सदन का समय सांय 7.00 बजे तक बढ़ा दें?

सदस्यगण: जी हां।

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): अब इस मान्य सदन की बैठक सांय 7.00 बजे तक बढ़ाई जाती है। माननीय मंत्री कर्ण सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

सहकारिता मंत्री: सभापति जी, अभी माननीय सदस्य ने भी और यहां से भी एक माननीय सदस्य ने जो हमारे डॉक्टर्ज और फार्मासिस्ट्स के पद आयुर्वेद में खाली हैं, उसके बारे में प्रश्न उठाया था। उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 108 डॉक्टर्ज के और 100 के लगभग फार्मासिस्ट्स के पद भरे जा रहे हैं। इन्होंने जो बैचवाइज भर्ती की बात की है, उस पर सरकार विचार कर रही है ताकि कुछ पोस्ट्स भरी जाएं और हर जगह डॉक्टर्ज और फार्मासिस्ट्स हम दे दें।

16/03/2016/1845/MS/AG/2

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): अब चर्चा में मोहन लाल ब्राक्टा जी भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः सभापति जी, आपने मुझे बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति जी, जो 08 मार्च, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2016-17 के लिए बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति जी, वैसे तो पूर्ववक्ताओं ने दोनों पक्षों से काफी डिटेल में इस बजट पर चर्चा की है लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, इनके बोलने से ऐसा लग रहा है जैसे इस बजट में कुछ है ही नहीं। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय का छठी बार इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बनने के बाद उनका यह 19वां बजट है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड प्रदेश का तो है ही बल्कि मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ये पहले मुख्य मंत्री होंगे जिन्होंने अपना 19वां बजट पेश किया है। जहां तक इस बजट की बात है इस बजट को पेश करते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सभी वर्ग, जाति और क्षेत्र का विशेष ख्याल रखा है। सभापति जी, इस बजट की जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि जो यह बजट वर्ष 2016-17 के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पेश किया गया है, यह टैक्स फ्री बजट है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

सभापति जी, थोड़ी सी दोहराने वाली बात है। अभी हाल ही में हमारे हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्था के चुनाव बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुए और कहीं भी कोई अप्रिय घटनाएं नहीं घटीं। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। साथ ही हमारी सरकार की जो तीन साल की उपलब्धियां हैं उनमें जैसे सामाजिक सुरक्षा पैंशन जो पहले 450/-रुपये थी, फिर उसको 600/-रुपये किया और अब बढ़ाकर 650/-रुपये किया है। यह भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही पहले 80 साल से ऊपर की

आयु के लोगों को 1100/- रुपये पैंशन दी जाती थी परन्तु अब उसको बढ़ा दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा

16/03/2016/1845/MS/AG/3

पैंशन के तहत 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को भी 1100/- रुपये पैंशन दी जा रही है। सभापति जी, पिछले तीन सालों के कार्यकाल में जो हमारी सरकार ने तीन नये कॉलेजिज चम्बा हमीरपुर और सिरमौर में खोले हैं, यह भी बड़ी भारी उपलब्धि है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

16.03.2016/1850/जेएस/एजी/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः--------जारी--------

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय more than 100 schools were either opened or upgraded during the last three years. जिनमें 28 नये कॉलेज खोले गए हैं, जिसमें एक फाईन ऑर्टस का कॉलेज भी है जो कि सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि अहै। इसके साथ-साथ सभापति महोदय 130 से ज्यादा स्वास्थ्य संस्थान खोले गए हैं, अपग्रेड हुए हैं। इसके अलावा 24 नये आई0टी0आई0 और दो नए इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले गए हैं। यह भी हमारी सरकार की उपलब्धि है। इसके साथ-साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वैसे तो विपक्ष के सभी माननीय विधायकों ने, जिनमें हमारे माननीय धूमल साहब भी शामिल हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है कि जो हमारी एम0एल0ए0 निधि है, जिसे हमारी सरकार ने शुरू किया था। इसको पहले 50 लाख रु0 से 75 लाख रु0 किया गया था और अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसको 75 लाख से 1 करोड़ रूपए किया है। इसका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ ही साथ जो

ऐच्छिक निधि है जिसे कि माननीय राजा साहब ने ही शुरू किया था। पहले यह 2 लाख रूपए की थी फिर इसको बढ़ा करके 4 लाख रूपए किया गया और अब इसको 5 लाख रूपए बढ़ाया गया है,इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। विपक्ष की ओर से तकरीबन सभी माननीय विधायकों ने इस बजट का विरोध किया है। मेरे साथी बम्बर भाई ने ठीक कहा है कि होम गार्ड की दिहाड़ी 280 रूपए से 350 रूपए की गई है तो क्या इसका ये विपक्ष के सदस्य विरोध करते हैं? यह भी यहां पर तर्कसंगत बात कही गई है। इसके साथ-साथ इस बजट में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिमला शहर में काफी ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस बजट में जो सर्कुलर रोड की वाइडनिंग की बात की गई है, वह भी एक सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा।

16.03.2016/1850/जेएस/एजी/2

सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इन तीन सालों में और जब-जब भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में सत्ता में रही है, जो भी आज तक हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के समय में हुए हैं, यह किसी से छिपा नहीं है और जहां तक राजा वीरभद्र सिंह जी की बात है, इन्होंने कभी भी किसी भी क्षेत्र से भेदभाव नहीं किया और पूरे प्रदेश का समान विकास किया है। जहां तक इस बजट की बात है यह एक सराहनीय बजट है, आम जनता के हित का बजट है। सभापति महोदया, मैं यहां पर अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में भी कुछ बातें रखना चाहूंगा। जहां तक मेरे चुनाव क्षेत्र की बात है, सबसे पहले तो मैं जो हमारा ठियोग-खड़ा पत्थर-हाटकोटी रोड़ है, उसकी बात करना चाहूंगा। जब इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उससे पहले जब हमारी कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और राजा साहब मुख्य मंत्री थे, उस दौरान उसका प्रोसैस चला था। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, काम शुरू हुआ और बीच में काम बन्द हो गया। मैं राजा साहब को बधाई देना चाहूंगा कि जैसे ही 25 दिसम्बर, 2012 को राजा साहब ने छठी बार मुख्य मंत्री की शपथ ली, तुरन्त दो-तीन दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के सभी आला अधिकारियों की बैठक ली और इसकी समीक्षा की कि क्यों इस

रोड़ का कार्य बन्द है और

श्री एस0एस0द्वारा जारी---

16.03.2016/1855/SS-AS/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा क्रमागतः

उसके बाद जो भी प्रोसैस था, चाहे ग्लोबल टैंडर की बात है या दूसरी अन्य बात है, उसका कार्य शुरू हुआ। मैं इस बात को मानता हूं कि शुरू में थोड़ा-सा कार्य धीमी गति से चल रहा था और इसका खासकर जुब्बल-कोटखाई व शिमला डिस्ट्रिक्ट के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता फायदा उठाना चाहते थे। परन्तु उनका नाटक कामयाब नहीं हुआ। मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि आज की तारीख में उस रोड का काम काफी हद तक प्रगति पर है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी-से-जल्दी इसका कार्य पूर्ण हो जायेगा।

इसके अलावा अभी-अभी हाल में 6 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी का मेरे चुनाव क्षेत्र का दौरा था। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 23 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली हॉस्पिटल की एडिशनल एकोमोडेशन का शिलान्यास किया। सिविल हॉस्पिटल, रोहड़ू का दर्ज़ा 150 बैड से बढ़ाकर 200 बैड किया गया। वहां डॉक्टर्ज़ की जो स्ट्रैंथ 17 थी, उसे वर्तमान में बढ़कर 30 किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री का बहुत आभारी हूं और उनका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदया, इसके अलावा यहां सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी

कांस्टीचुऐंसी और बजट के बारे में बोला। खासकर हमारे जो विपक्ष के मित्र लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारे कांस्टीचुऐंसी में कुछ नहीं हो रहा, स्कूल बंद पड़े हैं, हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, यह कहना दुख की बात है। मैं इसकी बहुत निन्दा करता हूं जो यह कह रहे हैं कि पिछले तीन सालों से कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके यहां कुछ काम नहीं हो रहा।

इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी की सरकार है। इलैक्शन के दौरान मोदी जी ने भी जनता के मन में काफी सपने संजोये थे। जिसमें कहा गया था कि काला धन वापिस लाऊंगा और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपये डाले जायेंगे। बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई कम होगी, ये सारे सपने ही दिखाए। बाकी आप

16.03.2016/1855/SS-AS/2

सबके सामने है कि आज केन्द्र सरकार की क्या नीति है। उनकी जन-विरोधी नीति चल रही है। विकास के कार्य नहीं हो रहे।

सभापति महोदया, अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में चलती है तो हिमाचल का कर्ज़ माफ करवाओ। सारा कर्ज़ माफ करायेंगे तब हम ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी को मान सकते हैं।

इसके अलावा मेरी कांस्टीचुऐंसी में पब्बर नदी के चैनेलाइजेशन का काम है। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और उद्योग मंत्री और आई0पी0एच0 मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि वह लगभग 200 करोड़ के करीब प्रोजैक्ट है जोकि भारतवर्ष में केवल एक ही सैंक्शन हुआ। मेरे ख्याल में स्वां नदी के चैनेलाइजेशन के बाद वह मेरी कांस्टीचुऐंसी में दूसरा प्रोजैक्ट होगा। उसका कार्य चल पड़ा है। परन्तु सुनने में आया है कि ये उसमें भी अड़चन पैदा कर रहे हैं। उसके लिए स्टेट से पैसा देना पड़ रहा है।

इसके अलावा सभापति महोदया आप बार-बार घंटी बजा रही हैं, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुए कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 8 मार्च, 2016 को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट पेश किया, उसका जोरदार समर्थन करता हूं।

सभापति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापतिः धन्यवाद। अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 17 मार्च, 2016 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 16 मार्च, 2016 **सचिव ।**